रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/96 REGISTERED No. D.L.-33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 1996/ज्येष्ठ 11, 1918
No 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1996/JYAISTHA 11, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. Date GOVT. OF INDIA

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक प्रभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1996

का.आ. 1486.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री विजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे दिल्ली एवं नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5 (89)/96-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

NOTICE

New Delhi the 16th April, 1996

S.O. 1486.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules by Sh. Vijender Singh, Advocate for appointment as a Notary to practice in Delhi & New Delhi N.C.T of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(89)/96-Judl.]

P.C. KANNAN, Competent Authority

भारत सरकार, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 9 मई, 1996

का. आ. 1487—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों को ऐसे किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में जिस पर उक्त धारा के उपबंध लागू होते है, विचारण न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा संस्थित मामलों के तथा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में इन मामलों से उद्भूत अपीलों/पुनरीक्षणों अथवा अन्य विषयों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :—

सर्वश्री

1. पार्थ तपस्वी
2. प्रकाश कुमार गजरे
3. एस. के. भट्ट

[सं. 225/22/96 एवीडी-II]

एस. सौंदरराजन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(Department of Personnel & Training)
New Delhi, the 9th May, 1996

S.O. 1487.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints the following prosecuting officers of the Central Bureau of Investigation as Special Public Prosecutors for the conduct of cases instituted by the Delhi Special Police Establishment in Trial Courts and appeals/revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate courts established by law in any State or Union Territory to which the provisions of the aforesaid section apply.

S/Shri

1. Parth Tapaswi.
2. Prakash Kumar Gajre
3. S. K. Bhat

[No. 225/22/96-AVD. II]

S. SOUNDAR RAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 मई, 1996

का. आ. 1488—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 25 की उप धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों को, ऐसे किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में जिस पर उक्त धाराओं के उपबंध लागू होते हैं, विचारण न्यायालयों मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा संस्थित मामलों के संचालन के लिए सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है:—

सर्वश्री

1. एस. आर बट्टा

[सं. 225/22/96-एवीडी II]

एस. सौंदरराजन, अवर सचिव

New Delhi, the 9th May, 1996

S.O. 1488.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 25 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints the following Prosecuting Officers of the Central Bureau of Investgation, as Assistant Public Prosecutors for the conduct of cases instituted by the Delhi Special Police Establishment in Trial Courts/Courts of Magistrates in any State or Union Territory to which the provisions of the aforesaid sections apply.

S/Shri

1. S R. Batta.

[No. 225/22/96-AVD. II]

S. SOUNDAR RAJAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1996

(आयकर)

का.आ. 1489:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "इन्स्टीट्यूशन एट धर्मस्थल, धर्मस्थल" को कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा-II की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अधिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो।

[अधिसूचना सं. 9933/फा.सं. 197/149/95—आयकर नि.-1]

एच.के. चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
New Delhi, the 9th January, 1996
(INCOME TAX)

S.O. 1489.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23 C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Institution at Dharmashtala', Dharmashtala for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1991-92 to 1993-94 subject to the following conditions namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section(5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being pofits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9933|F. No. 197|149|95-II-AI]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1996

(आयकर)

का.आ. 1490 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री सिद्धिविनायक गणपति टेम्पल ट्रस्ट, बम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(1) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों के संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9973/फा.सं. 197/26/96—आ.क.नि.-I]

एच.के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 12th February. 1996

(INCOME TAX)

S.O. 1490.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shree Siddhivinayak Ganpati Temple Trust. Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1995-96 to 1997-98 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section(5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9973|F. No. 197|26|96-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1996

(आयकर)

का.आ. 1491 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "सेलेसियन प्राविंस ऑफ कलकत्ता नार्दन इंडिया कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा-11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा,

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9982/फा.सं. 197/23/96—आयकर नि.-I]

एच.के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 20th February, 1996

(INCOME TAX)

S.O. 1491.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Salesian Province of Calcutta (Northern India), Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1995-96 to 1997-98 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the subject for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section(5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9982/F. No. 197/28/96-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1996

(आयकर)

का. आ. 1492.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 'पीर हाजी अली दरगाह ट्रस्ट बंबई" को कर-निर्धारित वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों में सगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा-11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग-से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9984/फा. सं. 197/51/95-आयकर नि-1]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 20th February, 1996

(INCOME TAX)

S.O. 1492.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Pir Haji Ali Dargah Trust, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1994-95 to 1996-97 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the subject for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section(5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9984/F. No. 197/51/95-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1996

(आयकर)

का. आ. 1493 :— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 16 के खंड (23–ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "दि कांग्रीगेशन आफ दि प्रांसिस्कन सिस्टर्स आफ दि प्रेजेन्टेशन आफ दि ब्लेस्ड वर्जिन मैरी, कोयम्बटूर" को कर निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात :—

(1) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के

लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(ii) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9983/फा. सं. 197/5/96-आयकर नि-I]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 20th February, 1996

(INCOME-TAX)

S.O. 1493.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Congregation of the Franciscan Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary, Coimbatore" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1996-97 to 1998-99 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9983/F. No. 197/5/96-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1996

(आयकर)

का. आ. 1494.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23—ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता" को कर निर्धारण वर्ष 1995—96 से 1997—98 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रखरखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9996/फा.सं. 197/138/94—आयकर नि-I]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 7th March, 1996

(INCOME-TAX)

S.O. 1494.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Dakshineshwar Ramakrishna Sangh, Dakshineshwar, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years from 1995-96 to 1997-98 subject to the following conditions, namely:—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9996/F. No. 197/138/94-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1996

(आयकर)

का. आ. 1495.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री दत्त देवस्थान ट्रस्ट, अहमदनगर" को कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि में रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 10015/फा. सं. 197/77/95-आयकर नि.I]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 19th March, 1996

(INCOME-TAX)

S.O. 1495.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shree Datta Devsthas Trust, Ahmednagar" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1994-95 to 1996-97 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 10015/F. No. 197/77/95-ITA-II]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1996

(आयकर)

का. आ. 1496.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "कोडईकनाल बोट, क्लब, कोडईकनाल" 1990-91 से 1992-93 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खंड (23) द्वारा यथा-संशोधित धारा 11 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त खण्ड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा; और

(4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हों जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 10042/का. सं. 196/19/93-आयकर नि-1]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 25th March, 1996

(INCOME TAX)

S.O. 1496.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Kodaikanal Boat Club, Kodaikanal" for the purpose of the said clause for assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-sections (2) and (3) of section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the

form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provision to the aforesaid clause (23) for any period durin the previous year(s) relevant to the assessment year(s) mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 10042|F. No. 196|19|93-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1996

(आयकर)

का. आ. 1497 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "दि बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल फॉर क्रिकेट इन इण्डिया, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खण्ड (23) द्वारा यथा-संशोधित धारा 11 की उप-धारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों भिन्न से तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त खण्ड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रखरखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण अपने से सम्बद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा; और

(4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हों जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 10069/फा. सं. 196/11/96-आ. क. नि. I]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 16th April, 1996

(INCOME TAX)

S.O. 1497.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies "The Board of Control for Cricket in India, Bombay" for the purpose of the said clause for assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of Sub-section (2) and (3) of section 11 as modified by the said clause (23) for

such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds [other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provision to the aforesaid clause (23) for any period during the previous year(s) relevant to the assessment year (s) mentioned above] otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of each business.

[Notification No. 10069/F. No 196/11/96-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1996

(आयकर)

का. आ. 1498:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार "बंबई फ्लाइंग क्लब, बंबई" को 1993-94 से 1995-96 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खण्ड (23) द्वारा यथा-संशोधित धारा 11 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि [जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त खण्ड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न] का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(3) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा; और

(4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 10072/फा. सं. 196/9/96-आयकर नि.-I]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd April, 1996

(INCOME TAX)

S.O. 1498.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Bombay Flying Club, Bombay" for the purpose of the said clause for assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of Sub-section (2) and (3) of section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds [other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provision to the aforesaid clause (23) for any period during the previous year(s) relevant to the assessment year (s) mentioned above] otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of each business.

[Notification No. 10072/F. No. 196/9/96-ITA-II]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1996

(आयकर)

का. आ. 1499.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने हेतु उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खण्ड (23) द्वारा यथासंशोधित धारा 11 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि [जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त खण्ड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न] का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा—

(3) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण अपने से सम्बद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा; और

(4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक न हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 10073/फा. सं. 196/12/96-आ. क. नि-I]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd April, 1996

(INCOME TAX)

S.O. 1499.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Tamil Nadu Cricket Association, Madras" for the purposes of the said clause for assessment years 1995-96 to 1997-98 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-section (2) and (3) of Section 11 as

modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provision to the aforesaid clause (23) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise then in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 10073/F. No. 196/12/96-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1996

(आयकर)

का. आ. 1500.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, अहमदाबाद" को 1996-97 से 1998-99 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खण्ड (23) द्वारा यथा-संशोधित धारा 11 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि [जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त खण्ड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न] का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण अपने संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा; और

(4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हों जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 10074/फा.सं. 196/13/96 आयकर नि.-I]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd April, 1996

(INCOME TAX)

S.O. 1500.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Gujarat Cricket Association, Ahmedabad" for the purpose of the said clause for assessment years 1996-97 to 1998-99 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-section (2) and (3) of Section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provision to the aforesaid clause (23) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (6) of Section 11;

(iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its

members except as grants to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of busines unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 10074/F. No. 196/13/96-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मई, 1996

(आयकर)

का.आ. 1501.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "वि बिलियर्डस एण्ड स्नूकर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, कलकत्ता" को 1993-94 से 1995-96 तक के कर-निर्धारण वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों पर उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है अर्थात्—

(1) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने हेतु उसका संचयन इस प्रकार के संचयन के लिए उक्त खण्ड (23) द्वारा यथा-संशोधित धारा 11 की उप-धारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों के संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु जिसे उपर्युक्त खंड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(3) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण अपने से सम्बन्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा; और

(4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबन्ध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हों जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त-कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबन्ध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 10077/फा.सं. 196/7/95-आयकर (नि. I)]

एच.के. चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st May, 1996

(INCOME TAX)

S.O. 1501.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "The Billiards & Snookers Federation of India, Calcutta" for the purpose of the said clause for assessment years 1993-94 to 1995-96 subject for the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-section (2) and (3) of Section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provision to the aforesaid clause (23) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 10077/F. No. 196/7/96-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(शुद्धिपत्र)

नई दिल्ली, 15 मई, 1996

का. आ. 1502.—आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (VIII) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा समसंख्यांक फाईल में दिनांक 8-5-96 की अधिसूचना संख्या 10081 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"कर निर्धारण वर्षों 1996-97 और 1998-99 के लिए" के शब्दों के स्थान पर "कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक के लिए" पढ़ा जाए ।

[अधि. सं. 10083/फा स 204/13/95/आयकर नि.-II]

निशि सिंह, उप सचिव

(Central Board of Direct Taxes)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th May, 1996

S.O. 1502.—In the exercise of power conferred in clause (viii) of Sub-section (1) of Section 36 of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby makes the following corrections in the Notification No. 10081 dated 8th May, 1996 in even number of file :—

"The words 'for the assessment years 1996-97 and 1998-99' should be read as 'for the assessment years 1996-97 to 1998-99'."

[Notification No. 10083/F. No. 204/13/95-ITA.II]

NISHI SINGH, Dy. Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 15 मई, 1996

का. आ. 1503.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा समसंख्यक फाईल में दिनांक 8-5-96 की अधिसूचना संख्या 10081 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"कर निर्धारण वर्षों 1996–97 और 1998–99 के लिए" के शब्दों के स्थान पर "कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998–99 तक के लिए" पढ़ा जाए ।

[अधिसूचना सं. 10083/फा सं. 204/13/95 आयकर नि–II]

निशि सिंह, उप सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th May, 1996

S.O. 1503.—In exercise of power conferred in clause (viii) of Sub-section (1) of Section 36 of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby makes the following corrections in the Notification No. 10081 dated 8th May, 1996 in even number of file :—

"The words 'for the assessment years 1996-97 and 1998-99' should be read as 'for the assessment years 1996-97 to 1998-99'."

[Notification No. 10083/F. No. 204/13/95-ITA.II]

NISHI SINGH, Dy. Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 15 मई, 1996

का. आ. 1504.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा समसंख्यक फाईल में दिनांक 8-5-96 की अधिसूचना संख्या 10081 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"कर निर्धारण वर्षों 1996–97 और 1998–99 के लिए" के शब्दों के स्थान पर "कर निर्धारण वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक के लिए" पढ़ा जाए ।

[अधिसूचना सं. 10083/फा. सं. 204/13/95 आयकर नि–II]

निशि सिंह, उप सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th May, 1996

S.O. 1504.—In exercise of power conferred in clause (viii) of Sub-section (1) of Section 36 of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby makes the following corrections in the Notification No. 10081 dated 8th May, 1996, in even number of file :—

"The words 'for the assessment years 1996-97 and 1998-99' should be read as 'for the assessment years 1996-97 to 1998-99'."

[Notification No. 10083/F. No. 204/13/95-ITA.II]

NISHI SINGH, Dy. Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 मई, 1996

का.आ. 1505.—भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कृष्णाराम बलदेव बैंक लिमिटेड के कारोबार के अधिग्रहण से संबंधित दिनांक 22-2-1974 की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश की शर्तों तथा निबन्धनों की धारा 5 (iv) तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के खंड 35 के उपखण्ड (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कृष्णाराम बलदेव बैंक, लिमिटेड की वसूल न की गई परिसम्पत्तियों के अंतिम मूल्यांकन की समय सीमा को 19 अप्रैल, 1996 से 18 अप्रैल, 1997] (दोनों दिन शामिल है) तक की एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाती है ।

[संख्या 15/6/95–बी ओ ए]

श्रीमती पी. मोहन, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 13th May, 1996

S.O. 1505.—In pursuance of clause 5(iv) of the Terms and Conditions sanctioned by the Central Government under an Order dated the 22nd February, 1974, relating to the acquisition by the State Bank of India of the business of Krishnaram Baldev Bank Ltd. and in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 35 of the State Bank of India Act, 1956 (23 of 1955), the Central Government hereby extends the time-limit for final valuation of the unrealised assets of the Krishnaram Baldeo Bank Ltd., for a further period of one year, from 19th April, 1996 to the 18th April, 1997, (both day inclusive).

[No. 15|6|95-BOA]

MRS. P. MOHAN, Director

नई दिल्ली, 14 मई, 1996

का. आ. 1506—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत

सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) नियमावली, 1966 के नियम 10 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 31 के प्रावधान निम्नलिखित बैंक पर 1993-94 को समाप्त वर्षों के लिए उसके तुलन पत्र व लाभ हानि लेखों के उनके लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ समाचार पत्र में प्रकाशन के संबंध में लागू नहीं होंगे।

दि कोपरगांव पिपल्स को० बैंक लि., कोपरगांव

[एफ सं. 1(19)/96 ए सी]

सुधीर श्रीवास्तव, उप सचिव

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. 1506.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of Section 31 of the said Act read with Rule 10 of the Banking Regulation (Cooperative Societies) Rules, 1966 shall not apply to the undernoted bank in so far as it relates to the publication of its balance sheet and profit and loss account for the year 1993-94 with the auditor's report in the newspaper.

1. The Kopargaon Peoples Cooperative Bank Ltd., Kopargaon.

[F. No. 1(19)/96-AC]

SUDHIR SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 14 मई, 1996

का. आ. 1507--बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1), के उपबंध इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 31 मार्च, 1998 तक दि भरतपुर सेन्ट्रल को० आपरेटिव बैंक लि., भरतपुर, राजस्थान पर लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. 1(17)/96-ए. सी.]

सुधीर श्रीवास्तव, उप सचिव

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. 1507.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Bharatpur Central Co-operative Bank Ltd., Bharatpur (Rajasthan) from the date of publication of this notification in the official Gazette of 31st March, 1998.

[F. No. 1(17)/96-AC]

SUDHIR SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 14 मई, 1996

का. आ. 1508.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1 के) उपबंध इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 31 मार्च, 1998 तक सिरोही सेन्ट्रल को० आपरेटिव बैंक लि., सिरोही, राजस्थान पर लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. 1 (18)/96/ए सी.]

सुधीर श्रीवास्तव, उप सचिव

New Delhi, the 14th May, 1996

S.O. 1508.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to The Sirohi Central Co-operative Bank Ltd., Sirohi (Rajasthan) from the date of publication of this notification in the Official Gazette of 31st March, 1998.

[F. No. 1(18)/96-AC]

SUDHIR SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

मुख्य आयकर आयुक्त III का कार्यालय

अधिसूचना सं 1-95/96

कलकत्ता, 6 मार्च, 1996

का. आ. 1509.—मुख्य आयकर आयुक्त कलकत्ता, मुख्य आयकर आयुक्त-II, कलकत्ता तथा मुख्य आयकर आयुक्त-III, कलकत्ता के आदेश संख्या 3 दिनांक 26-7-94 तथा पूर्वतन आदेशों का आंशिक संशोधन करते हुए तथा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों के अनुसार तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिसूचना संख्या 9565/एफ सं. 279/129/93 आई टी जे (खंड-II) दिनांक 5-7-94 तथा एस. ओ. संख्या 501 दिनांक 5-7-94 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस दिशा में मुझे सक्षम बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य आयकर आयुक्त-III, कलकत्ता एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि आयकर आयुक्त (अपील)-III, कलकत्ता फाइल सं. सआ/मुख्या. / योजना / 30/94/95 के अधिसूचना संख्या-3 दिनांक 26-7-94 के द्वारा सौंपे गए रेंजों के अतिरिक्त नागरहाट डाकघर सिराकोल 24 परगना (दक्षिण) के श्रीमती सईदा खातून द्वारा पूर्वतन आयकर अधिकारी, वार्ड बी सर्वे सर्कल-1 द्वारा निर्धारण वर्ष 1982-83 के लिए जी आई आर संख्या एस सी-1 / ... 11/बी-को फाईल में पारित निर्धारण आदेश दिनांक 8-3-85 के खिलाफ

दिनांक 10-11-85 को फाईल किए गए अपील का भी क्षेत्राधिकारी होंगे।

[संख्या सी सी —III/क्षेत्रा०-1/आयुम 2/95—96/5199]

तेजिन्दर सिंह, मुख्य आयकर आयुक्त-III

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX-III

Notification No. 1/95-96

Calcutta, the 6th March, 1996

S.O. 1509.—In partial modification of earlier orders and the Order No. 3 dated 26th July, 1994 passed by the CCIT, Cal., CCIT-II, Cal. and the CCIT-III, Cal. and in accordance with the powers vested in me u/s. 120 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) and in exercise of the powers conferred on me by the Central Board of Direct Taxes, New Delhi, vide its Notification No. 9565 F. No. 279/129/93-ITJ (Pt. II) dated 5th July, 1994 and S.O. No. 504 dated 5th July, 1994 and all other powers enabling me in this behalf. The CCIT-III, Calcutta, hereby directs that the Commissioner of Income Tax (Appeal)-III, Calcutta, in addition to the Ranges assigned to him by virtue of the Notification No. 3, dated 26th July, 1994 from the file of AC/HQ/Planning/30/94-95, shall have jurisdiction over the appeal filed by Smt. Saiyda Khatun of Rajarhat, P.O. Sirakole, 24 Pgs(S) on 10th November, 1985 against the assessment order passed on 8th March, 1985 by the erstwhile ITO-Ward Survey Circle-I, for the A.Y. 1982-83 under cover of GIR No. SC-I/K-44/B.

[No. CC-III/Juris-I/Vol.2/95-96/5199]

TEJINDER SINGH, Chief Commissioner of I.T-III

अधिसूचना 1/96

कलकत्ता, 12 अप्रैल, 1996

का. आ. 1510.—आ. सं. म. आ./मुख्या/योजना/30/94-95/2494/3293 दिनांक 27-7-94 के अंतर्गत परिचालित अधिसूचना सं.—3 दिनांक 26-7-94 में आंशिक संशोधन करते हुए, तथा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) व (2) के द्वारा और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली के अधीन जारी अधिसूचना सं. 9565 एफ सं. 279/129/93 आई. टी. जे. (पार्ट—II) दिनांक 5-7-94 और एस. ओ. सं. 504 दिनांक 5-7-94 और इस संबंध में मुझे प्रदत्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं मुख्य आयकर आयुक्त-III कलकत्ता एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि मुख्य आयकर आयुक्त—II कलकत्ता के क्षेत्र के आयकर आयुक्त (अपील) III एवं 8 ऐसे व्यक्तियों के संबंध में अपने कृत्यों का पालन करेंगे जिनके आयकर अथवा धनकर अथवा दानकर अथवा अतिकर अथवा ब्याजकर अथवा व्ययकर अथवा संपदा शुल्क का निर्धारण कालम 1, 2 एवं 3 में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों/निर्धारण अधिकारियों के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खंड (ए) से (एच) तक धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) की धारा 23 की उपधारा (1ए) के खंड (ए) से (ई) तक दानकर अधिनियम 1958 (1958 का 18) की धारा 22(1ए) के खंड (ए) से (ई) तक कंपनी लाभ अतिकर अधिनियम, 1984 (1984 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) ब्याजकर अधिनियम 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (1) और व्ययकर अधिनियम, 1987 (1987 का 35) की धारा 22 की उपधारा (1) और संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 62 में उल्लिखित किन्हीं आदेशों से असंतुष्ट हों।

2. जहां एक आयकर सर्कल, वार्ड अथवा विशेष रेंज या उनके अंश इस अधिसूचना के अनुसार एक प्रभार से दूसरे प्रभार में स्थानांतरित हो गए हों, इस अधिसूचना के जारी होने के तुरन्त पहले आयकर आयुक्त अपील के समीप उस आयकर/वार्ड/सर्कल/विशेष रेंज अथवा उनके अंश में हुई निर्धारण से उत्पन्न अपील लंबित हो तो इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से उस वार्ड/सर्कल/विशेष रेंज अथवा उनके अंश में स्थानांतरित किए मामलों का निपटान उस आयकर आयुक्त अपील के द्वारा किये जायेंगे जिनके अधीन उक्त वार्ड/सर्कल/विशेष रेंज अथवा उनके अंश स्थानांतरित किये गये हैं।

मुख्य आयकर आयुक्त —III कलकत्ता

क्षेत्राधिकार

1	2	3
1.	आयकर आयुक्त (अपील III) कलकत्ता	(अ) आयकर उपायुक्त, रेंज-9, कलकत्ता के अधीन सभी निर्धारण अधिकारी
		(आ) आयकर उपायुक्त रेंज —18, कलकत्ता के अधीन सभी निर्धारण अधिकारी
2.	आयकर आयुक्त (अपील)—8, कलकत्ता	(अ) आयकर, उपायुक्त रेंज-5, कलकत्ता के अधीन सभी निर्धारण अधिकारी
		(आ) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज—6 कलकत्ता तथा आयकर उपायुक्त, वि रेंज—8, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी
		(ई) आयकर उपायुक्त, रेंज—19 कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारियों, हुगली, मिदनापुर तथा हल्दिया सहित।

3. यह अधिसूचना 15-4-96 से लागू होगी।

[संख्या मु. आ. आ. III/क्षेत्रा-I/खंड 2/96-97]

तेजिन्दर सिंह, मुख्य आयकर आयुक्त-III

NOTIFICATION 1/96

Calcutta, the 12th April, 1996

S.O. 1510.—In partial modification of the Notification No. 3 dated 26th July, 1994 which was circulated under the Memo No. AC. HQ. Planning|30|94-95|2494—3293 dated 27th July, 1994 and in exercise of the powers conferred under Sub-section (1) & (2) of Section 120 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) and in exercise of the powers vested in me by the Central Board of Direct Taxes, New Delhi vide notification No. 9565 F. No. 279/129 93-ITJ (Pt. II) dated 5th July, 1994 and S.O. No. 504 dated 5th July, 1994 and all other powers enabling me in this behalf, I, the Chief Commissioner of Income-tax-III, Calcutta, direct that the Commissioners of Income-tax (Appeals)-III & VIII of the region of the CCIT-III, Calcutta, shall perform their functions in respect of such persons assessed to income tax or Wealth Tax or Gift Tax or Sur-tax or Interest Tax or Expenditure-tax or Estate Duty by the Income-tax Authorities/Assessing Officers specified in column 1, 2 & 3 thereof as are aggrieved by any orders mentioned in clauses (a) to (b) or sub-section (2) of Section 246 of the I.T. Act, 1961, clauses (a) to (e) of sub-section (1A) of Section 23 of Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) clauses (a) to (e) of sub-section (1A) of Section 22 of the Gift Tax Act, 1958 (18 of 1958), sub-section (1) of Section 11 of the Companies (Profit) Sur-tax Act, 1984 (7 of 1984), sub-section (1) of section 15 of the Interest-tax Act, 1974 (45 of 1974) and sub-section (1) of Section 22 of the Expenditure Tax Act, 1987 (35 of 1987) and Section 62 of the Estate Duty Act, 1953.

2. Where an Income Tax Circle, Ward or Special Range or part thereof stands transferred by this notification from one charge to another, appeals arising out of the assessments made in this Income-tax Ward/Circle/Special Range or part thereof and pending immediately before the date, from which this notification takes effect, before the Commissioner of Income Tax (Appeals) from whose charge that Income-tax Ward/Circle/Special Range or part thereof is transfetred shall, from the date from which this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Commissioners of Income-tax (Appeals) to whose the said Ward/Circle/Special Range or part thereof is transferred.

Under the Control of the Chief Commissioner of Income Tax-III, Calcutta.

JURISDICTION

1	2	3
1.	Commissioner of Income-tax (Appeal)-III, Calcutta.	(a) All assessing officers functioning under Dy. Commissioner of Income-tax, Range-9, Calcutta. (b) All Assessing officers functioning under Dy. Commissioner of Income-tax, Range-18, Calcutta.
2.	Commissioner of Income-tax (Appeal)-VIII, Calcutta.	(a) All assessing officers functioning under Dy. Commissioner of Income-tax Range-5, Calcutta. (b) Dy. Commissioner of Income-tax, Spl. Range-6, Calcutta and all Assessing officers subordinate to Dy. Commissioner of Income-tax, Spl. Range-6 Calcutta. (c) All Assessing officers functioning under Dy. Commissioner of Income tax, Range-19, Calcutta, including Hooghly, Midnapore and Haldia.

3. This notification takes effec from 15-4-96.

[No. CC-III/Juris-1/Vol. 2/96-97]

TEJINDER SINGH, Chief Commissioner of Income-tax-III.

खाद्य मंत्रालय

(खाद्य प्रापण और वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 1996

का. आ. 1511:— यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने तत्कालीन खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशकों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, संचलन, ढुलाई, वितरण और बिक्री संबंधी किए जा रहे कार्य करने बन्द कर दिए हैं और कांडला पत्तन न्यास, जो तत्कालीन खाद्य विभाग और कांडला पत्तन न्यास के बीच दिनांक 8-4-1965 को हुए एक करार के अनुसार, कांडला पत्तन न्यास में आने वाले टैंकरों/जहाजों से खाद्यान्नों को डिस्चार्ज करने के प्रयोजन के लिए बेकु-वेटरों की हैंडलिंग करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए सरकार के एक एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा था, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन अब उक्त कार्य भारतीय खाद्य निगम के हैं ;

और यद्यपि उपर्युक्त करार के खण्ड 19 के अनुसार, उपर्युक्त कार्यों को करने के लिए कांडला पत्तन न्यास के बेकुवेटर डिवीजन के निम्नलिखित कर्मचारी 1-1-1973 में भारतीय खाद्य निगम ने ले लिए थे।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा 1-1-1973 से इन कर्मचारियों का भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरण

करती है । इन कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण निम्नानुसार हैं :—

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	स्थानान्तरण के समय कांडला पत्तन न्यास केन्द्रीय सरकार के अधीन धारित पद	कांडला पत्तन न्यास/केन्द्रीय सरकार के अधीन धारित स्थायी पद
1.	सुश्री जी. के डुडानी	वरिष्ठ लिपिक	वरिष्ठ लिपिक
2.	श्री एच.एच. मदनानी	टाइम कीपर	टाइम कीपर
3.	श्री आर.यू. अहूजा	टाइम कीपर	टाइम कीपर
4.	एस.आर. गुप्ता	टाइम कीपर	टाइम कीपर
5.	श्री पी.टी.खुशलानी	टाइम कीपर	टाइम कीपर
6.	श्री रामचन्द डी.	नोजल अटेंडेन्ट	—
7.	श्री बलराम एच. एस.	नोजल अटेंडेन्ट	—
8.	श्री हीराचन्द सी. एच.	नोजल अटेंडेन्ट	—
9.	श्री धामजी भारमल	पाइपमैन	—
10.	श्री पंचन देवजी	पाइपमैन	—
11.	श्री हशम मंगु	साइक्लोन अटेंडेन्ट	साइक्लोन अटेंडेन्ट
12.	श्री एम.एस. नथानी	आपरेटर	—
13.	श्री जे.एस. पांडया	आपरेटर	—
14.	श्री अजीज अहमद	आपरेटर	—
15	श्री पोहुमल के.	आपरेटर	—

[फाइल संख्या ए-38022/1/96/एफ.सी. 3]
सत्य नारायण गुप्त, अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD

(Department of Food Procurement and Distribution)

ORDER

New Delhi, the 9th May, 1996

S.O. 1511.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport distribution and sale of foodgrains done by the then Department of Food, the Regional Directors of Food and the Kandla Port Trust which was acting as an agent of the Government for handling and maintenance of vacuvators for the purpose of discharge of foodgrains from tankers|vessels arriving at Kandla Port Trust in terms of an agreement dated 08-04-1965 entered into between the then Department of Food and the Kandla Port Trust, which under Section 13 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are now the functions of the Food Corporation of India;

And whereas as per clause XIX of the said agreement the following employees working in the vacuvator Division of the Kandla Port Trust for the performance of the functions mentioned above were taken over by the FCI with effect from 01-01-1973;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby transfers these employees to the Food Corporation of India with effect from 01-01-1973. The names and other particulars of these employees are as under :—

Sl. No.	Name of the employee	Post held under the Kandla Port Trust/ Central Govt. at the time of transfer	Parmanent post held under the Kandla Port Trust/ Central Govt.
1.	Miss. G.K. Dudani	Sr. Clerk	Sr. Clerk
2.	Shri S.H. Madnani	Time Keeper	Time Keeper
3.	Shri R.U. Ahuja	Time Keeper	Time Keeper
4.	Shri S.R. Gupta	Time Keeper	Time Keeper
5.	Shri P.T. Khushalani	Time Keeper	Time Keeper
6.	Shri Ramchand D.	Nozzle Attendant	—
7.	Shri Balram H.S.	Nozzle Attendant	—
8.	Shri Hirachand Ch.	Nozzle Attendant	—
9.	Shri Dhamji Bharmal	Pipeman	—
10.	Shri Panchan Devji	Pipeman	—
11.	Shri. Hasman Mangu	Cyclone Attendant	Cyclone Attendant
12.	Shri. M.S. Nathani	Operator	—
13.	Shri. J.S. Pandya	Operator	—
14.	Shri. Aziz Ahmed	Operator	—
15.	Shri. Pohumal K.	Operator	—

[F.No.A-38022/1/96/FC-3[
S.N. GUPTA, Under Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली 7 मई 1996

का. आ. 1512.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उप नियम 4 के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करती है :—

(1) उप निदेशक का कार्यालय,
भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण,
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय,
2963, गोकुलम रोड, मैसूर 570002 ।

(2) उप निदेशक का कार्यालय,
भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण,
पश्चिम क्षेत्रीय केन्द्र,
16, मधुवन, उदयपुर–313001 ।

(3) उप निदेशक का कार्यालय,
भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण,
उत्तर पश्चिम, क्षेत्रीय केन्द्र,
192 /1, कौलागढ़ मार्ग, देहरादून ।

[सं 1–2/95-हिन्दी]

राजेन्द्र सिंह उपनिदेशक, (राजभाषा)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Culture)

New Delhi, the 7th May, 1996

S.O. 1512.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (use for official purpose of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices under the Ministry of Human Resource Development, Department of Culture more than 80 per cent staff of which has acquired working knowledge of Hindi :—

1. Office of the Dy. Director, Anthropological Survey of India, Southern Regional Office, 2963, Gokulam Road, Mysore-570002.

2. Office of the Dy. Director, Anthropological Survey of India, Western Regional Office, 16, Madhuban, Udaipur.

3. Office of the Dy. Director, Anthropological Survey of India, North Western Regional Office, 192/1, Kaulgarh Marg, Dehradun.

[No. F. 1-2/95-Hindi]

RAJENDRA SINGH, Dy. Director (OL)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मई, 1996

का. आ. 1513.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में श्री दीपक देशपांडे, उप कलक्टर, विदिशा और शोभाराम पाटीदार, उप कलक्टर, उज्जैन, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, सेन्ट्रल इंडिया रिफाइनरी परियोजना को मध्य प्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[फा. सं. आर–31015/22/95-ओ. आर. II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 9th May, 1996

S.O. 1513.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises S|Shri Deepak Deshpande, Deputy Collector, Vidhisa and Shobharam Patidar, Deputy Collector, Ujjain, Bharat Oman Refineries Limited, Central India Refinery Project to perform the functions of the competent authority under the said Act within the territory of the State of Madhya Pradesh.

[File No. R-31015|22|95-OR. II]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 मई, 1996

का. आ. 1514.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) हिन्दी पाठ पृष्ठ सं. 4063 से 4064 पर प्रकाशित, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3011, तारीख 18-11-1995 द्वारा उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में मुद्रण प्रकृति की कुछ त्रुटियां हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

पृष्ठ 4063 ग्राम मापारवाडी में स्तंभ 2 के नीचे सर्वे संख्या "13/1/2" के स्थान पर "13/1" पढ़ें ।

पृष्ठ 4063 ग्राम सिन्नर में स्तंभ 2 के नीचे सर्वे संख्या "1200/1/2ए/2बी/3" के स्थान पर "1200/1" पढ़ें और स्तंभ 3,4,5 के नीचे "0-96-00 के स्थान पर "0-85-00" पढ़ें ।

पृष्ठ 4063 ग्राम सिन्नर में स्तंभ 2 के नीचे सर्वे संख्या "1202/2" के स्थान पर "1201/2" पढ़ें और स्तंभ 3,4,5 के नीचे "0-46-00" के स्थान पर "0-55-00" पढ़ें ।

ऐसी भूमि में, जिसके बाबत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, हितबद्ध कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निबन्धनों के अनुसार उक्त भूमि के सम्पूर्ण या किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर उपयोग के अधिकार को अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में आक्षेप श्री ए. एन. देशपांडे, सक्षम प्राधिकारी, मुंबई मनमाड पाइप लाइन परियोजना, 9-13, दूसरी मंजिल, वसंत मार्केट-कनाडा कार्नर, नासिक-422002 को कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के द्वारा संशोधित भूमियों और अन्य विशिष्टियों के बाबत ही उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निबन्धनों के अनुसार इक्कीस दिन की उक्त अवधि उस तारीख से आरम्भ होती है जिसको यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन के पश्चात् जनता को उपलब्ध करा दी जाती है।

[फाईल सं. आर-31015/4/93-ओ आर-II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 9th May, 1996

S.O. 1514.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3011, dated the 18th November, 1995, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), at page 4064, issued under sub-section (I), of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government gave notice of its intention to acquire the rights of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification ;

And whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of printing nature have occurred in the publication of the said notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby amends the Schedule appended to the said notification as follows namely :—

In the said notification :—

(i) at page 4064, in village Maparwadi, in column 2, for Survey number "13|1|2" read "13|1",

(ii) at page 4064, in village Sinnar, in column 2, for Survey number "1200|1|2A|2B|3" read "1200|1" and in column 3, 4, 5, for "0-96-00" read "0-85-00",

(iii) at page 4064, in village Sinnar, in column 4 against Survey number 1201|2, for "46" read "55".

Any person interested in any land in respect of which the above amendment has been issued, may within twenty one days from the date on which the copies of this notification are made available to the general public, object to the acquisition of the whole or any part of the said land or any right in or over such land in terms of sub-section (I) of section 5 of said Act to Sh. A. N. Deshpande, Competent Authority, Mumbai-Manmad Pipeline Project, 9-13, 2nd Floor, Vasant Market, Canada Corner, Nasik-422002.

Explanation.—In respect of the lands, Survey| Gat numbers and areas amended through this notification only, the said period of twenty one days in terms of sub-section (I) of section 5 of the said Act shall start running from the date the copies of the Gazette notification are made available to the public after its publication in Official Gazette.

[File No. R-31015|4|93 OR-II]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 1996

का. आ. 1515.—चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि आर. सी. एफ. थाल से एल. पी. जी. प्लान्ट उत्तर महाराष्ट्र राज्य तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाईन अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय

सरकार उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड "प्रभू बिल्डिंग" अलिबाग (रायगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

आर.सी.एफ. थल उसर गैस पाईप लाईन परियोजना

तहसील: अलिबाग जिला : रायगढ़ राज्य : महाराष्ट्र

क्र. म.	गांव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	हुक्कासंपादन है.	क्षेत्र आर	प्र. आर
1	2	3	4	5	6	7
1	वेश्वी	108पै.	—	00	09	00
1.	काबीर	97 पै.		00	01	50
2		81पै		00	02	50
3.		40 पै.		00	10	50
4.		102 पै.		00	26	00
5.		82पै.		00	03	20
1.	सहाण	252पै		00	18	40
2.		250 पै.		00	00	30
3.		407 पै.		00	21	10
4.		282पै.		00	01	30
5.		179 पै.		00	00	90
6.		292 पै.		00	05	80
7.		237 पै.		00	15	00
8.		293 पै.		00	02	50
9.		294ब पै		00	17	90
10.		290 पै.		00	01	00
11.		298 पै.		00	08	70
12.		216अ पै.		00	05	90
13.		297 पै.		00	01	10
14		300 पै.		00	00	90
15.		353पै.		00	01	20
16.		352 पै.		00	25	90
17.		351 पै.		00	01	50
18.		376 पै.		00	20	10
19.		255 पै.		00	51	70
20.		299 पै.		00	08	90
1.	कुवर	751 पै.		00	05	40
2.		752 पै.		00	05	50
3.		779 क पै.		00	05	00
4.		14 पै.		00	03	30
5.		17 पै.		00	03	10
6.		16 पै.		00	03	80
7.		15 पै.		00	06	30
8.		2 पै.		00	05	50
9.		3 पै.		00	12	60
10.		1 पै.		00	05	00
11.		141 पै.		00	.08	40
12.		142 पै.		00	03	40
13.		140 पै.		00	06	00
14.		139 पै.		00	57	00
15.		188 पै.		00	12	00
16.		187 पै.		00	06	00
17.		182 पै.		00	08	00
18.		207 पै.		00	17	20
19.		211 पै.		00	39	00
1.	भाल	41	0 पै.	00	01	30
2.		37	2 पै.	00	05	00
3.		37	1 पै.	00	00	50
4.		36	0 पै.	00	17	40
5.		32	2 पै.	00	22	80
6.		31	3 ब पै.	00	04	00
7.		31	2 पै.	00	13	70
8.		19ई 1	0 पै.	00	12	90
1.	भाल तर्फे झिराड	21	1 पै.	00	04	20
2.		21	2 पै.	00	03	20
3.		33	0 पै.	00	21	00
4.		नवी	पैकी	00	40	20
5.		38	5 पै.	00	00	40
6.		38	3 पै.	00	17	50
7.		40	2 पै.	00	01	60
8.		36	1 पै.	00	05	10
9.		36	2 पै.	00	01	50
10.		36	4 पै.	00	02	00
11		40	1 पै.	00	05	60
12		35	3 पै.	00	02	00
1	बेलकडे	387 पै.		00	03	20
2.		394 पै.		00	09	20
3.		495 पै.		00	04	80
4.		383 पै.		00	03	20
5		476 पै.		00	04	80
1	सुगसि	39	9पै.	00	01	90
2		35	3पै.	00	00	50
3		अलिबाग रेवस रस्त्या पै.		00	00	60
4		39	10 पै.	00	05	50
1.	तुडाल	18	2 पै.	00	02	70
1.	ब्रामणगांव	52 पै.		00	03	60
2		49 पै.		00	12	00
3		281 पै.		00	09	80
4		278 पै.		00	09	60
1	वढाव बुद्रुक	249		00	01	80

[सं. एल-14016/6/93 जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 13 May, 1996

S.O. 1515 .—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from RCF Thal to LPG Plant, Vsar in Maharastra State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred be sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, "Prabhu Building" Alibag (Raigad).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

RCF THAL-USAR GAS PIPE LINE

Tahasil : Alibag District : Raigad Maharashtra State

Village	Survey No./Block No.	Hissa No.	Area H.	Are.	C. Are.
1	2	3	4		
Veshvi	108	0 P	0	09	00
Kawir	97 P		0	01	50
	81 P		0	02	50
	40 P		0	10	50
	102 P		0	26	00
	82 P		0	03	20
Sahan	252 P		0	18	40
	250 P		0	00	30
	407 P		0	21	10
	282 P		0	01	30
	179 P		0	00	90
	292 P		0	05	80
	237 P		0	15	00
	293 P		0	02	50
	294 B P		0	17	90
	290 P		0	01	00
	298 P		0	08	70
	216A P		0	05	90
	297 P		0	01	10
	300 P		0	00	90
	353 P		0	01	20
	352 P		0	25	90
	351 P		0	01	50
	376 P		0	20	10
	255 P		0	51	70
	299 P		0	08	90
Dhawar	751 P		0	05	40
	752 P		0	05	50
	779 (C) P		0	05	00
	14 P		0	03	30
	17 P		0	03	10
	16 P		0	03	80
	15 P		0	06	30
	2P		0	05	50
	3P		0	12	60
	1 P		0	05	00
	141 P		0	08	40
	142 P		0	03	40
	140 P		0	06	00
	139 P		0	57	00
	188 P		0	12	00
	187 P		0	06	00
	182 P		0	08	00
	207 P		0	17	20
	211 P		0	39	00
Bhal	41	0 P	0	01	30
	37	2 P	0	05	00
	37	1 P	0	00	50
	36	0 P	0	17	40
	32	2 P	0	22	80
	31	3B P	0	04	00
	31	2 P	0	13	70
	19E 1	0 P	0	12	90
Maan Tarf Zirad	21	1 P	0	04	20
	21	2 P	0	03	20
	33	0 P	0	21	00
	River	River P	0	40	20
	38	5 P	0	00	40
	38	3 P	0	17	50
	40	2 P	0	01	60
	36	1 P	0	05	10
	36	2 P	0	01	50
	36	4 P	0	02	00
	40	1 P	0	05	60
	35	3 P	0	02	00
Belkade	387 P		0	03	20
	394 P		0	09	20
	495 P		0	04	80
	383 P		0	03	20
	476 P		0	04	80
Gunjis	39	9 P	0	01	90
	35	3 P	0	00	50
	Alibag-Ravas Road P		0	00	60
	39	10 P	0	05	50
Tudal	18	2 P	0	02	70
Bamangaon	52 P		0	03	60
	49 P		0	12	00
	281 P		0	09	80
	278 P		0	09	60
Vadhav Budruk	249		0	01	80

[No. L-14016/6/93—GP]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 13 मई, 1996

का. आ. 1516 .—चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि पुनासन जी. जी एस से विमल ओयल गुजरात राज्य तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाईपलाईन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, दर्पण बिल्डिंग, द्वितीय तल अलकापुरी बडोदरा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पुनासन जी जी एस. से विमल ऑइल

राज्य गुजरात	जिला महसाणा	तालुका मेहसाणा		
गांव	सर्वे नं.	ब्लाक नं.	क्षेत्र	
			हे.	आर. सें.
1	2		3	
पुनासन	126		00	15 25
	116		00	00 64
	113		00	12 57
	112		00	04 93
	111		00	04 35
			00	37 74
हेवुवा	101		00	01 89
	104		00	05 90
	102		9	01 43
	103		00	06 93
	106		00	11 82
	292		00	00 07
	107		00	12 06
	108		00	12 71
	123		00	07 00
	109		00	07 46
	122		00	08 29
	121		00	09 47
	156		00	05 30
	157		00	07 58
	रोड पुईकी		00	00 65
	150		00	06 72
	01		00	05 33
सोभासन	101		00	07 03
	99		00	04 73
	98		00	07 67
	97		00	08 97
	87		00	05 70
	89		00	08 71
	92		00	08 36
	पुईकी रोड		00	02 90
	73		00	16 68
	74		00	00 28
	8		00	09 96
	7		00	00 50
	6		00	08 80
	9		00	12 35
	52		00	00 76
	पुईकी रोड		00	01 20
	11		00	11 90
	14		00	09 35
	17		00	14 50
	21		00	02 92
	रोड		00	02 34
	457		00	14 75
	543		00	12 35
	रेलवे नाला		00	02 34
	खुला स्थान		00	03 51
	01		78	56
	450		00	12 50
	448		00	06 12
	447		00	05 28
	446		00	05 75
	445		00	05 50
	438		00	10 92
	पुईकी रोड		00	01 08
	441		00	19 69
	440		00	10 10
	02		00	55 50
हवुवा	90		00	38 30
हनुसन्टा	89		00	14 80
	रोड पुई की		00	01 14
	00		00	54 24

[सं. एल-14016/2/96-जी. पी.]
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 13th May, 1996

S.O. 1516 —Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from Punasan GGS to Vimal Oil in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub. section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act

1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Darpan Building, IInd Floor Alkapuri, Vadodara.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PUNASAN G.G.S. TO VIMAL OIL

State : Gujarat Dist. : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	S. No. Block No.	Area		
		Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Punasan	126	00	15	25
	116	00	00	64
	113	00	12	57
	112	00	04	93
	111	00	04	35
		00	37	74
Hebuva	101	00	01	89
	104	00	05	90
	102	00	01	48
	103	00	06	93
	106	00	11	82
	292	00	00	07
	107	00	12	06
	108	00	12	71
	123	00	07	00
	109	00	07	46
	122	00	08	29
	121	00	09	47
	156	00	05	30
	157	00	07	58
	Road Puiki	00	00	65
	158	00	06	72
		01	05	33
Sobhasan	101	00	07	03
	99	00	04	73
	98	00	07	67
	97	00	08	97
	87	00	05	70
	89	00	08	71
	92	00	08	36
	Road Puiki	00	02	90
	73	00	16	68
	74	00	00	28
	8	00	09	96
	7	00	00	50
	6	00	08	80
	9	00	12	35
	52	00	00	76
	Road Puiki	00	01	20
	11	00	11	90
	14	00	09	35
	17	00	14	50
	21	00	02	92
	Road	00	02	34
	457	00	14	75
	543	00	12	35
	Railway Nala	00	02	34
	Open Place	00	03	51
		01	78	56
	450	00	12	50
	448	00	06	12
	447	00	05	28
	446	00	05	75
	445	00	05	50
	438	00	10	92
	Road Puiki	00	01	08
	441	00	19	69
	440	00	10	10
		02	55	50
Haduva Hanumant	90	00	38	30
	89	00	14	80
	Road Puiki	00	01	14
		00	54	24

[No. L-14016/2/96—G.P]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 13 मई, 1996

का. आ. संख्या 1517—चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होती है कि जनहित में यह आवश्यक है कि गन्धार डबका पाईपलाईन से मधुसूदन सैरोमिक्स इंडस्ट्रीज गुजरात राज्य तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाईपलान गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस आथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड दर्पण बिलडिंग द्वितीयतल, अलका पुरी बडोदरा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

गंधार डबका पा/ला के समीप गांव मासर रोड से मधुसूदन सेरामिक इंडस्ट्रीज

राज्य गुजरात जिला बडोदरा तालका पादरा

गांव	क्रम सं. ब्लाक नं.	क्षेत्र		
		हे.	आरे	सेंटी आरे
1	2	3	4	5
कनजत	562	00	07	41
	566	00	05	26
	564	00	00	78
	565	00	02	05
	कैनाल	00	08	19
	563	00	04	42
	रेलवे	00	02	08
	571	00	05	27
	546	00	03	05
	रोड	00	02	86
	546	00	05	07
	548	00	05	59
	550	00	00	25
	549	00	07	49
	529	00	05	20
	538	00	10	92
	539	00	07	41
	536	00	07	60
	537	00	14	36
	रोड	00	03	51
	पुईकी रोड	00	01	95
	678	00	06	63
	510	00	03	80
	677	00	00	33
	680	00	06	53
	679	00	00	75
	रोड	00	00	91
	685	00	01	52
	683	00	25	91
	735	00	05	72
		01	63	00
	734	00	14	21
	753	00	13	00
	752	00	05	20
	रोड	00	01	04
	751	00	04	29
	1173	00	06	63
	750	00	01	50
	749	00	10	53
	745	00	04	68
	775	00	12	48
कनजत जारी	754	00	06	11
	773/बी	00	04	68
	773/ए	00	08	45
	764	00	00	09
	772	00	07	80
	778	00	03	90
	779	00	03	51
	771	00	10	46
	781	00	10	01
	782	00	09	62
	रोड	00	11	59
		03	15	79

[सं. एल/14016/2/96 जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 13th May, 1996

S.O. 1517—Whereas it appears to the Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from Gandhar-Pabka P/L to Madhusudan Ceramics Industries in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, Darpan Bldg. IInd Floor, Alkapuri Vadodara.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

GANDHAR DABKA P/L NEAR VILLAGE MASAR ROAD TO MADHUSUDAN CERAMIC INDUSTRIES
State : Gujarat Dist. : Vadodara Taluka : Padra

Iage	Sr. No. Block No.	Area		
		Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Kanzat	562	00	07	41
	566	00	05	26
	564	00	00	78
	565	00	02	05
	Canal	00	08	19
	563	00	04	42
	Railway	00	02	08

1	2	3	4	5
Kanzit	571	00	05	27
	546	00	03	05
	Road	00	02	86
	546	00	05	87
	548	00	05	59
	550	00	00	25
	549	00	07	49
	529	00	05	20
	538	00	10	92
	539	00	07	41
	536	C0	07	60
	537	00	14	36
	Road	00	03	51
	Road Puiki	00	01	95
	678	00	06	63
	510	00	03	80
	677	00	00	33
	680	00	06	53
	679	00	00	75
	Road	00	00	91
	685	00	01	52
	683	00	25	91
	735	00	05	72
	734	00	14	21
	753	00	13	00
	752	00	05	20
	Road	00	01	04
	751	00	04	29
	1173	00	06	63
	750	00	01	50
	749	00	10	53
	745	00	04	68
	775	00	12	48
	754	00	06	11
	773/B	00	04	68
	773/A	00	08	45
	764	00	00	09
	772	00	07	80
	778	00	03	90
	779	00	03	51
	771	00	10	46
	781	00	10	01
	782	00	09	62
	Road	00	11	59
		03	12	78

[No. L-14016/2/96—GP]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 13 मई, 1996

का. आ. 1518—चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि नन्दासन ई. पी. एस. से जे. पी. कैमिकल्स गुजरात राज्य तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए, एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड वर्ण विन्डिंग द्वितीय तल अलका पुरी, बड़ौदरा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

नन्दासन ई पी एस से जे पी कैमिकल्स

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाणा	तालुका : कडी		
गांव	ग्राम सं. ब्लाक नं.	क्षेत्र		
		हे.	आरे	सेंटीएअर
नन्दासन	1176	00	09	36
	1174	00	07	15
	1167	00	03	51
	1173/1	00	08	06
	रोड	00	07	93
		00	36	01
कथोल	825 पी	00	09	40
	रोड	00	01	95
	825 पी	00	03	38
	550	00	13	52
	549	00	11	64
	524	00	11	12
	523	00	11	38
	521	00	20	54
	520	00	07	22
	511	00	24	96
	508	00	12	16
	502	00	16	38
	500/1	00	06	12
	499	00	15	97
	497	00	11	83
	488	00	15	28
	486	00	10	01
	485	00	11	25
	482	00	08	07
	481	00	05	49
	457	00	02	21
	458	00	09	75
	459	00	13	65
	460	00	26	91
		02	80	19

[सं. एल 14016/2/96 जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 13th May, 1996

S.O. No 1518.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from Nandasan EPS to J.P. Chemicals in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, Darpan Bldg. IInd Floor, Alkapuri Vadodara.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

NANDASAN EPS TO J.P. CHEMICALS

State : Gujarat Dist. : Mehsana Taluka : Ka di

Village	Sr. No. Block No.	Area		
		Hec-tare	Are	Cen-tiare
Nandasan	1176	00	09	36
	1174	00	07	15
	1167	00	03	51
	1173/1	00	08	06
	Road	00	07	93
		00	36	01
Kaiyol	825/P	00	09	40
	Road	00	01	95
	825/P	00	03	38
	550	00	13	52
	549	00	11	64
	524	00	11	12
	523	00	11	38
	521	00	20	54
	520	00	07	22
	511	00	24	96
	508	00	12	16
	502	00	16	38
	500/1	00	06	12
	499	00	15	97
	497	00	11	83
	488	00	15	28
	486	00	10	61
	485	00	11	25
	482	00	08	07
	481	00	05	49
	457	00	02	21
	458	00	09	75
	459	00	13	65
	460	00	26	91
		02	80	19

[No. L-14016/2/96-GP]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 20 मई, 1996

का.आ. 1519:— पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50वां) की धारा 2 के खण्ड (ए) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम 1 में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त कालम-3 की तदनरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	पता	क्षेत्रीय अधिकार
1	2	3
कालीपाडा श्याम	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड निकट सर्किट हाऊस, पो.आ. अभयानगर, अगरतला-799005	त्रिपुरा

[एल 14016/7/95-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 20th May, 1996

S.O. 1519.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorizes the authorities mentioned in column-1 of the schedule below to perform the function of Competent Authority under the said Act within the area mentioned in the corresponding entry in the column 3 of the said schedule.

SCHEDULE

Name of the Person	Address	Territorial Jurisdiction
1	2	3
Kulipida Shyam	Gas Authority of India Ltd. Near Circuit House, P.O. Abhaya Nagar Agartala-7990005.	

[L-14016/7/95-G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, 10 मई, 1996

का.आ. 1520:— केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80% कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किया है, अधिसूचित करती है :—

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर ।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., मेरठ विपणन कार्यालय, मेरठ ।

कृषक भारती कोआपरेटिव लि., राज्य विपणन कार्यालय, अहमदाबाद, गुजरात ।

कृषक भारती कोआपरेटिव लि., राज्य विपणन कार्यालय, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

कृषक भारती कोआपरेटिव लि., राज्य विपणन कार्यालय, चण्डीगढ़, हरियाणा ।

कृषक भारती कोआपरेटिव लि., राज्य विपणन कार्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश ।

कृषक भारती कोआपरेटिव लि., राज्य विपणन कार्यालय पटना, बिहार ।

कृषक भारती कोआपरेटिव लि., राज्य विपणन कार्यालय, चण्डीगढ़, पंजाब ।

कृषक भारती कोआपरेटिव लि., राज्य विपणन कार्यालय, जयपुर, राजस्थान ।

कृषक भारती कोआपरेटिव लि., राज्य विपणन कार्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि., क्षेत्रीय कार्यालय, भटिण्डा ।

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि., क्षेत्रीय कार्यालय, पटियाला ।

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि., क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि., क्षेत्रीय कार्यालय, रांची ।

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि., राज्य विपणन कार्यालय, पंजाब ।

[सं. ई-11011/5/93-हिन्दी]

नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Fertilizers)

New Delhi, the 10th May, 1996

S.O. 1520.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Language 'Use for official purposes of the Union' Rule 1976 the Central Government hereby notifies the following offices, under the Administrative control of Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Fertilizers, 80% staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd., Regional Office, Bhubaneswar.

Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd., Meerut Mktg. Office, Meerut.

Krishak Bharati Cooperative Ltd., State Mktg. Office, Ahmedabad, Gujarat.

Krishak Bharati Cooperative Ltd., State Mktg. Office, Mumbai Maharashtra.

Krishak Bharati Cooperative Ltd., State Mktg. Office, Chandigarh, Haryana.

Krishak Bharati Cooperative Ltd., State Mktg. Office, Bhopal, M.P.

Krishak Bharati Cooperative Ltd., State Office, Patna, Bihar.

Krishak Bharati Cooperative Ltd., State Mktg. Office, Chandigarh, Punjab.

Krishak Bharati Cooperative Ltd., State Mktg. Office, Jaipur, Rajasthan.

Krishak Bharati Cooperative Ltd., State Mktg. Office, Lucknow, U.P.

Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., Regional Office, Bhatinda.

Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., Regional Office, Patiala.

Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., Regional Office, Allahabad.

Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., Regional Office, Ranchi.

Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., State Mktg. Office, Punjab.

[No. E. 11011/5/93-Hindi]

NARENDER KUMAR AGGARWAL,
Addl. Industrial Adviser

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का. आ. 1521:—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में, डा. जी. पाल का राजस्थान विश्वविद्यालय से केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के सदस्य के रूप में चयन किया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 482 (अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, शीर्षक "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" के नीचे, क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"11.	डा. जी. पाल, प्राचार्य, डा. एम. पी. के. राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

[फ. सं. वी. 27021/46 (27) / 94-होम्यो-ई. यू.]

कंवल दास, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र की अधिसूचना का. आ. 482 (अ) दिनांक 6-8-74 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

का. आ. 484 (अ) दिनांक 6-8-74, का. आ. 740 (अ) दिनांक 29-8-1990, का. आ. 818 (अ) दिनांक 22-10-1990, का. आ. 75 (अ) दिनांक 6-2-1991, का. आ. 547 दिनांक 27-1-1992, का. आ. 1263 दिनांक 27-4-1992 और का. आ. 2700 दिनांक 25-9-1992

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1521.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), Dr. G. Pal has been elected as a member to the Central Council of Homoeopathy, from the Rajasthan University ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health), No. S.O. 482(E), dated the 06th August, 1974, namely :—

In the said notification under the heading "Elected under Clause (b) of the sub-section (1) of section 3" for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1		2.
"11	Dr. G. Pal, Principal, Dr. M. P. K. Rajasthan, Homoeopathic Medical College, Jaipur.	Rajasthan University, Jaipur.

[F. No. V. 27021/46(27)/94-Homoeo-EU]

KANWAL DASS, Under Secy.

Foot Note :

The original Notification was issued vide No. S.O. 482(E), dated the 6th August, 1974 and subsequently amended by notification No. S.O. 484(E) dated 6th August, 1974, No. S.O. 740(E) dated 29th August, 1990, No. S.O. 818(E) dated 22nd October, 1990, No. S.O. 75(E) dated 6th February, 1991, No. S.O. 547 dated 27th January, 1992, No. S.O. 1263 dated 27th April, 1992 and No. S.O. 2700 dated 25th September, 1992.

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 1996

का.आ. 1522:— मिन्नोसोटा विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की गई आयुर्विज्ञान अर्हता भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है,

और उक्त अर्हता प्राप्त डा. डिजांग वस गुडवाई, कोडैकनाल इन्टरनेशनल स्कूल, कोडैकनाल, तमिलनाडु से संलग्न है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ख) के साथ पठित खंड (ग) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार :—

(क) इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि, या

(ख) वह अवधि जिसके दौरान डा. डिजांग बूस एडवार्ड कोडैकनाल इन्टरनेशनल स्कूल, कोडैकनाल, तमिलनाडु से संलग्न है, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि के रूप में जिसको पूर्त कार्य के प्रयोजन के लिए उक्त डाक्टर का चिकित्सा व्यवसाय सीमित होगा, विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा.सं. वी.-11016/4/95-एम.ई (यू. जी.)]

एस.के. मिश्रा, डेस्क अधिकारी

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 7th May, 1996

S.O. 1522:—Whereas the medical qualification Doctor of Medicine (M.D.) granted by University of Minnosota, U.S.A., is a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) under section 14 of the said Act;

And whereas Dr. Dejong Bruce Edward who possesses the said qualification is attached to the Kodaikanal International School, Kodaikanal, Tamil Nadu.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) read with clause (b) of sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hreby specifies :—

(a) a period of two years from the date of issue of this notification, or

(b) a period during which Dr. Dejong Bruce Edward is attached to Kodaikanal International School, Kodaikanal, Tamil Nadu.

whichever is shorter, as the period to which the medical practice of the said doctor shall be limited for the purpose of charitable work.

[No. V-11016/4/95—ME(UG)]

S.K. MISHRA, Desk Officers

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1996

का.आ. 1523:— केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ को जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है ।

[संख्या ई-11012/6/96-हिंदी]

राम तिलक पाण्डेय, निदेशक

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 19th April, 1996

S.O. 1523:—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the union) Rules, 1975 the Central Government hereby notifies the Northern Regional Office, Chandigarh of Bureau of Indian Standards, New Delhi under the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution, where more than 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi.

[No. E-11012/6/96-Hindi]

R.T. PANDEY, Director

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी कार्य और गरीबी उन्मूलन विभाग)

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का. आ. 1524:—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली), अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित अधिकारी को, जो जम्मू-कश्मीर सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करता है जो उक्त सारणी के स्तंभ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थान की बाबत, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थान का प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
सचिव, निवासी आयोग, जम्मू-कश्मीर सरकार, नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में जम्मू-कश्मीर सरकार के या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए सभी स्थान जिसमें 5, पृथ्वी राज रोड और कौटिल्य मार्ग, चाणिक्या पुरी, नई दिल्ली के अतिथि गृहों में की वास-सुविधा क्वार्टर और कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली के पीछे का वह क्षेत्र जिसमें सेवक आवास समाविष्ट है।

[सं. 21012/1/96 पोल-1

आर. डी. सहाय, संपदा उप निदेशक

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT

(Department of Urban Affairs & Poverty Alleviation)

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1524.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column 1 of the Table below being gazetted officer of the Government of Jammu and Kashmir to be estate officer for the purpose of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed one Estate Officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table:

TABLE

Designation of the Officer	Category of Public Premises and local limits of jurisdiction
1.	2.
Secretary, Resident Commission, Government of Jammu and Kashmir, New Delhi.	All premises belonging to or taken on lease by Government of Jammu and Kashmir in the National Capital Territory of Delhi including accommodation quarters in the guest houses of Government of Jammu and Kashmir at 5, Prithvi Raj Road and Kautilya Marg, Chanakya Puri, New Delhi and the areas comprising the servant quarters behind Kashmir House, Rajaji Marg, New Delhi.

[No. 21012/1/96-Pol. I]

R. D. SAHAY, Dy. Director of Estates

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 1996

का.आ. 1525.—राजभाषा नियम, (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार डाक विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. अधीक्षक डाकघर,
   कारवार डाक डिवीजन, कारवार,
   कर्नाटक सर्किल ।

2. अधीक्षक डाकघर,
   दार्जिलिंग डाक डिवीजन, दार्जिलिंग,
   पश्चिम बंगाल सर्किल ।

3. अधीक्षक डाकघर,
   संगारेड्डी डाक डिवीजन,
   हैदराबाद क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश सर्किल ।

4. अधीक्षक डाकघर,
   करीम नगर डाक डिवीजन,
   हैदराबाद क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश सर्किल ।

5. अधीक्षक डाकघर,
   मेडक डाक डिवीजन,
   हैदराबाद क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश सर्किल ।

6. अधीक्षक डाकघर,
   सूर्यपेट डाक डिवीजन,
   हैदराबाद क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश सर्किल ।

7. अधीक्षक डाकघर,
   महबूब नगर डाक डिवीजन,
   हैदराबाद क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश सर्किल ।

[सं. ई-11025-1/91-रा.भा.]

डा० गिरिवरधारी सिंह, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Post)

New Delhi, the 17th May, 1996

S.O. 1525.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the following subordinate offices of the Department of Post where 80 per cent staff has acquired the working knowledge of Hindi :

1. Supdt. of Post Offices,
   Karwar Postal Division,
   Karwar,
   Karnataka Circle.
2. Supdt. of Post Offices,
   Darjeeling Postal Division,
   Darjeeling,
   West Bengal Circle.
3. Supdt. of Post Offices,
   Sangareddy Postal Division,
   Hyderabad Region,
   Andhra Pradesh Circle.
4. Supdt. of Post Offices,
   Karimnagar Postal Division,
   Hyderabad Region,
   Andhra Pradesh Circle.
5. Supdt. of Post Offices,
   Medak Postal Division,
   Hydrabad Region,
   Andhra Pradesh Circle.
6. Supdt. Post Office,
   Suryapet Postal Division,
   Hyderabad Region,
   Andhra Pradesh Circle.
7. Supdt. of Post Offices,
   Mehabubnagar Postal Division,
   Hyderabad Region,
   Andhra Pradesh Circle.

[No. (E. 11025-1/91-OL]
DR. G. D. SINGH, Director(OL)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मई, 1996

का.आ. 1526:— केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम 4 के अनुसरण में जल संसाधन मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग के निम्नलिखित कार्यालय, जिसमें 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :

1. जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, गुवाहाटी-781024 (असम)

[सं. 1/2/95-हिन्दी]
गोपाल दीक्षित, उप सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 22nd May, 1996

S. O. 1526.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Central Water Commission under the Ministry of Water Resources where of more than 80 per cent staff have acquired knowledge of Hindi :—

Hydrological Observation Division,
Central Water Commission,
Guwahati-781024 (Assam).

[No. 1/2/95-Hindi]
GOPAL DIXIT, Dy. Secy.

पर्यटन विभाग

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1996

का. आ. 1527:—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में पर्यटन विभाग के निम्न अधीनस्थ कार्यालय को अधिसूचित करती है, जहां के 80% कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है :—

भारत सरकार क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय, कलकत्ता

[सं. ई—11016(4)/96-रा. भा.]
चिरंजीव सिंह, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

DEPARTMENT OF TOURISM

New Delhi, the 8th April, 1996

S.O. 1527.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purpose of the Union) Rules 1976, the Central Government hereby notifies the following subordinate office of Department of Tourism, the 80 per cent staff whereof have acquired working knowledge of Hindi, Government of India Regional Tourist office, Calcutta.

[F. No. E-11016(4)/96-O.L.]
CHIRANJEEV SINGH, Addl. Director General (Admn.)

नई दिल्ली, 2 मई, 1996

का. आ. 1528 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल—29011/92/83-डी III (बी)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 1996

S.O. 1528.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Steel Authority of India, Kuteshwar Limestone Mines and their workmen, which was received by the Central Government on 2-5-1996.

[No. L-29011/92/83-D.III(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR, (MP)

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(10)/1984

BETWEEN

Workmen through the President, Bokaro Steel Limestone Mining Workers Union, Shram Dham, Kymore District Jabalpur, (M.P.).

AND

The Managing Director, Steel Authority of India, Kuteshwar Limestone Mines of Bokaro Steel Plant, Bokaro Steel City, Dhanbad, (Bihar).

PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

APPEARANCES :

For Union : Shri S. K. Rao, Advocate.

For Management : Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Limestone Mine. DISTRICT : Jabalpur (MP).

AWARD

Dated, January, 1996

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-29011/92/83-D.III(B) dated 4-2-1984, for adjudication of the following industrial dispute :—

SCHEDULE

"Whether the management of Kuteshwar Limestone Mines, P.O. Gairtalai, District Jabalpur, (M.P.) of Bokaro Steel Plant under the Steel Authority of India Ltd., are justified in not extending the benefits arising out of the Memorandum of Settlement dated 25-5-83 of National Joint Committee for Steel Industry to the workmen employed through contractors in Kuteshwar Limestone Mines? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

2. The case of the Union is that the management of Kuteshwar Limestone Mine, Gairtalai is owned and operated by the Bokaro Steel Plant which is one of the wing of the Steel Authority of India Ltd.; that the workers are working with the Company and with the contractors since last 10 years and the management through the contractors are issuing the instructions for the allotment of the duties and the jobs to the workmen; that the Bokaro Steel Plant is the principal employer; that the nature of job done by the workmen is similar to that of the departmental workers or regular workers thereof; that the workmen are deemed to be permanent employee of Kuteshwar Limestone Mines and as per Agreement between the management and the workers reached before the Regional Labour Commissioner vide Agreement dated 25-5-83 these workmen be treated as permanent workers of Kuteshwar Limestone Mines. The workmen have prayed that the action of Bokaro Steel Plant in not extending the benefit arising out of the Memo of Settlement dated 25-5-83 is not justified. The workmen of Kuteshwar Limestone Mine employed through the contractors are entitled to the benefits which are given to the permanent workers employed therein.

3. The case of the management is that as per Agreement dated 27-10-1970 and 30-7-1975 which were at the National Level of the Steel Industry and the Unions, the workmen engaged by the contractors were not entitled to be treated as employees employed by the management; that in the similar reference bearing No. CGIT/LC(R)(10)/81 vide Award dated September 25, 1982 the impugned terms of reference was answered in favour of the management and as such the dispute cannot be reagitated and it is barred by the principles of Res judicata.

4. Terms of reference are made the issue in the case vide order dated 6-2-1985.

5. The workmen was directed to lead evidence and the workman failed to produce the witnesses in spite of the repeated adjournments. However, on 30-6-87, the workmen prayed for a date to produce the witnesses and since then last more than seven dates and in spite of enumerable opportunities to the workmen to examine the witnesses, the workmen failed to adduce the evidence. The workmen remained absent on the date of evidence i.e. 1-11-95 and the case was closed for award.

6. The initial burden was on the Union to prove that the workmen were working on the instructions of the management through the contractors and as per definition of Section 2 of the Mines Act the management was the principal employer of the workmen. Unless the workmen prove that the management was their principal employer, the workmen are not entitled for any relief from the Bokaro Steel Plant of Steel Authority of India Ltd. and the workmen will be deemed to be the employees of the contractors. The Ministry of Labour made the similar reference vide letter dated 16-7-81 and the Award dated September 25, 1982 was passed in case No. CGIT/LC(R)(10)/81, published by the Ministry of Labour, vide notification dated 30-10-1982 (Marked as Annexure 1) which was answered in favour of the management. The Union is making an attempt to reagitate the similar dispute and it is barred by the principle of constructive Res judicata.

7. Apart from this, Agreement arrived at between the management and the various trade unions reached at National Level on 27-10-1970 and subsequently on 30-7-1975 envisages that the benefits extended to the contractors workmen will not be extended to the employees of the Steel Authority of India. Consequently, the reference is not maintainable either on facts or in view of the alleged Agreement and also due to the principles of constructive Res judicata.

8. Reference is answered in negative and in favour of the management. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 मई, 1996

का. आ. 1529 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर

केपंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल--40012/126/92—आई आर (डी यू)]
के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 1996

S.O. 1529.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Posts and their workmen, which was received by the Central Government on 1-5-96.

[No. L-40012/126/92-IR(DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 84 of 1993

In the matter of dispute between :

Santosh Kumar Tripathi,

S/o Sri Janardan Tripathi,

269/266, Ashok Sadan, Ram Nagar,

Aishbagh, Lucknow.

AND

The Assistant Engineer (Electrical), Postal Sub-Division Sector C, Aliganj Post Office Building, Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. 40012/126/92-IR(DU) dated 30-9-93, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Postal Sub-Division (Electrical), Lalbagh, Lucknow in terminating the services of Santosh Kumar Tripathi son of Janardan Tripathi, Ex. Assistant Wireman w.e.f. 19-10-88 is justified and legal. If not, what relief the concerned workman is entitled ?

2. In this case on 2-2-96, concerned workman was debarred from adducing evidence as he failed to put in his appearance. Similarly, management was also debarred from adducing their evidence. Thus there is no evidence on the record.

3. It, therefore, appears that the concerned workman is not interested in prosecuting his case. The reference is, therefore, answered in affirmative for want of evidence against the workman.

4. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 मई, 1996

का.आ. 1530.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.-12011/59/88-डी-II-ए/आर आई (बी-II)]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 1996

S.O. 1530.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 1-5-96.

[No. L-12011/59/88-D.II(A)/IR (B-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

परिशिष्ट

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, राज, जयपुर।

केस नं. सी.आई.टी. 4/89

रेफरेन्स : —भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-12011/59/88-डी-II-ए दि. 5-1-89

महामंत्री, बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी यूनियन, एम.एस.ए. शाखा, 7 पार्क हाउस स्कीम, एम.आई. रोड, जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

सहायक, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, डी-38/ए, अशोक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर।

—प्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश, श्री के.एल. व्यास, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से :	कोई भी नहीं।
अप्रार्थी की ओर से :	कोई भी नहीं।
दिनांक अवार्ड : —	21-9-95

अवार्ड

कोई पक्ष उपस्थित नहीं। गवाह यूनियन की होनी है। पत्रावली 1989 की है साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं। कई बार अंतिम अवसर भी दिये गये हैं। कोई कारण भी अनुपस्थिति का नहीं बताया गया है। कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं हुआ है।

अब आदेशिकाओं को व पुराने मुकदमे की प्रवृत्ति को देखते हुए यूनियन पक्ष की साक्ष्य बन्द की जाती है। साक्ष्य के अभाव में व यूनियन द्वारा पैरवी करने के अभाव में इस मामले में "विवाद हीन" नोडिस्पुट अधिनिर्णय पारित करने का आदेश दिया जाता है। अधिनिर्णय अलग से निकाला गया। दफ्तर दाखिल हो।

(के.एल. व्यास)
पीठासीन अधिकारी
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण,
जयपुर।

नई दिल्ली, 2 मई, 1996

का.आ. 1531.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या-एल. 12011/111/87-डी-II/आईआर (बी-II)]
ब्रज मोहन डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 1996

S.O. 1531.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 1-5-96.

[No. L-12011/114/87-DIIA/IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

परिशिष्ट

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, राज., जयपुर।

केस नं. सी.आई.टी. 25/88

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या-एल-12011/114/87-डी-2 (ए) दिनांक 28-4-88

क्षेत्रीय सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी यूनियन 12/284, राजेन्द्रपुरा, अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेशन रोड़, अजमेर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश, श्री के.एल. व्यास, आर.एच.जे.एस.,

प्रार्थी की ओर से : कोई नहीं।

अप्रार्थी की ओर से : श्री एन.के. गुप्ता

अवार्ड दिनांक : 30-10-95

अवार्ड

श्रमिक यूनियन की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। 3.00 पी.एम. तक प्रतीक्षा की गई। नियोजक की ओर से श्री एन.के. गुप्ता प्रतिनिधि उपस्थित। यह प्रकरण 1988 से विचाराधीन है। पूर्व में 1989 में विवाद रहित अधिनिर्णय श्रमिक यूनियन की अनुपस्थिति के कारण पारित किया गया था। वर्तमान में लगातार कई तारीखों से श्रमिक यूनियन की ओर से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है। आज श्रमिक यूनियन की साक्ष्य हेतु तारीख निश्चित की हुई है। कोई भी मौखिक या लिखित अनुरोध तारीख बदलने का यूनियन की ओर से नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य हेतु अवसर देने का कोई उचित कारण नहीं है। श्रमिक यूनियन की अनुपस्थिति व साक्ष्य के अभाव में निर्देश में विवाद रहित अधिनिर्णय पारित करने का आदेश दिया जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

के.एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 2 मई, 1996

का.आ. 1532.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/29/89-डी 2(बी)]

के.बी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 1996

S.O. 1532.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby pubishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Kanpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Post and their workman, which was received by the Central Government on 1-5-96.

[No. L-40012/29/89-D2(B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 53 of 1990

In the matter of dispute between :

Adayaksh,
Bhartiya Dak Karamchari Sangh
(Postman & Chaturth Shrani)
Through Pradhan Dakghar,
Naveen Market,
Kanpur.

AND

Chief Post Master,
Kanpur Pradhan Dakghar,
The Mall Road,
Kanpur.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-40012/29/89-D.2 (B) dated 19-1-1990, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Kya Chief Post Master Kanpur ke prabandhak dvara Sri Nirmal Kumar Tiwari dainik vetan bhogi group 'D' karmkar ko unke 9-8-87 ko li gai niyamit group D post ke liye vibhagiya pariksha me anuttirya hone par dainik vetan bhogi karamkar kis anutosh ka haqdar hai ?

2. It is not necessary to give facts of the case in detail, as on the last date of hearing i.e. 16-4-96, the authorised representative of the concerned workman N. K. Tiwari made an endorsement on the claim statement that he does not press the reference as the same being defective, required amendment. Suffice it to that the concerned workman has raised this Industrial dispute regarding his failure in the departmental examination.

3. As the concerned workman has not pressed the reference, the same is answered against the concerned workman. The concerned workman is not entitled to any relief.

Sd/-25-4-96

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officre

नई दिल्ली, 2 मई, 1996

का.आ. 1533 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29012/19/88-डी-III (बी)]
बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 1996

S. O. 1533.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure. in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajasthan State Tungsten Development Corpn. and their workmen, which was received by the Central Government on 1-5-96.

[No. L-29012|19|88-D-III(B)]
B. M. DAVID, Desk Officer

परिशिष्ट

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर
केस नं. सी. आई. टी. 81 /88

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल 29012/19/88 डी III(बी)

दिनांक 1-12-88

श्री मूल सिंह द्वारा खनिज विकास निगम टंगस्टस मजदूर संघ (इन्टक) टंगस्टन परियोजना, डेगाना, जिला नागौर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान स्टेट टंगस्टन डैवेलपमेंट कार्पोरेशन लि. सी —196, उदय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर
2. प्रोजेक्ट मैनेजर (टंगस्टन) टंगस्टन प्रोजक्ट —डेगाना

अप्रार्थीगण

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के. एल. व्यास आर. एच. जे. एस.
प्रार्थी की ओर से श्री जे. के. अग्रवाल
अप्रार्थीगण की ओर से श्री जी. एल. माथुर
दिनांक अवार्ड : 15-9-95

अवार्ड

निम्न विवाद केन्द्र सरकार द्वारा अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है :

'Whether the action of the management of Rajasthan Stete Tungsten Development Corporation Ltd. Jaipur in terminating the services of Shri Mool Singh Casual Workman with effect from 16-1-87 is justified ? If not to what relief is the workman entitled ?'

2. प्रस्तुत क्लेम में श्रमिक ने यह अभिकथित किया है कि उसने विपक्षी सं. 2 की प्लाण्ट में 10-9-95 से 23-1-87 तक निरन्तर कार्य किया था व इसके पश्चात 24-1-87 से धारा 25-एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया है) के प्रावधान की पालना किये बिना उसकी सेवाएं नियोजक द्वारा समाप्त की गई। श्रमिक का यह भी कथन है कि उसकी सेवा मुक्ति के समय प्लान्ट में उसके कनिष्ठ श्रमिकगण कार्यरत थे व इस प्रकार नियोजक द्वारा धारा 25-जी के प्रावधान की अवहेलना भी की गई। एक तथ्य यह बताया गया है कि श्रमिक को एक आरोप पत्र 20-1-87 को दिया गया था जिसका समुचित जवाब उसने 29-1-87 को प्रस्तुत कर दिया था किन्तु इसके बाद उस आरोप पत्र पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तथा श्रमिक की सेवा मुक्ति का एक परोक्ष कारण यह कथित दुराचरण भी रहा है व चूंकि दुराचरण के संबंध में कोई भी जांच नियोजक द्वारा नहीं की गई इसलिए इस आधार पर भी सेवा मुक्ति का आदेश अवैध व शून्य है। अनुतोष यह मांगा गया है कि सेवा मुक्ति की तिथि से निरन्तर सेवा में मानते हुए श्रमिक को पुनः सेवा में बहाल करने के आदेश दिये जावें व बीच की अवधि का समस्त बकाया वेतन स्वीकृत किया जावे।

3. नियोजक के क्लेम के उत्तर में यह बताया है कि श्रमिक ने 10-9-85 से 15-1-87 तक नियोजक के प्लाण्ट पर कभी भी लगातार कार्य नहीं किया किन्तु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृत के अनुसार इस अवधि में निश्चित समय के लिए कई बार श्रमिक को नियुक्ति आदेश दिये गये थे व अंत में 24-11-86 से 15-1-87 की अवधि के लिए श्रमिक को नियोजित किया गया था व 15-1-87 के पश्चात उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई। इससे पूर्व 10-9-85 से 26-9-85 की अवधि में भी श्रमिक को नियोजित करने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। श्रमिक की सेवा मुक्ति के समय कोई भी कनिष्ठ श्रमिक कार्य पर होने के तथ्य को नियोजक द्वारा अस्वीकार किया गया है। 20-1-87 के आरोप पत्र के संबंध में यह प्रतिरक्षा ली गई है कि चूंकि श्रमिक की सेवाएं 15-1-87 को समाप्त हो गई थी इसलिए उस आरोप पत्र पर आगे कोई भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं था व कथित सेवा मुक्ति का इस आरोप पत्र से कोई भी संबंध नहीं है।

4. श्रमिक की ओर से मौखिक साक्ष्य में सर्वश्री राम सिंह राठौड़, भोगेन्द्र सिंह व श्रमिक स्वयं के शपथ पत्र

प्रस्तुत हुए हैं नियोजक की ओर से एक गवाह श्री के. डी. एस. राजावत का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों की ओर से कुछ प्रलेख साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। बहस सुनी गई ।

5. दोनों पक्षों के प्रस्तुत अभिकथनों को देखते हुए सर्व-प्रथम विचारणीय बिन्दु यह हैं कि क्या कथित सेवा मुक्ति से पूर्व श्रमिक द्वारा नियोजक के यहां लगातार 240 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए कार्य किया गया। श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में यह बताया है कि उसने 10-9-85 से 29-1-87 तक नियोजक के यहां लगातार कार्य किया था व उस बीच अपनी स्वेच्छा के अनुसार नियोजक द्वारा समय समय पर प्लाण्ट को बंद रखा गया किन्तु उस दौरान श्रमिक को अन्य कोई कार्य नहीं दिया गया व न ही उस अवधि का वेतन भुगतान किया गया। इस साक्ष्य से यह सिद्ध करने का प्रयास श्रमिक का है कि जिस अवधि का भुगतान उसे नहीं किया गया उस बीच भी वह नियोजक के यहां कार्य पर था। प्रदर्श डब्ल्यू-1 नियुक्ति आदेश श्रमिक की ओर से प्रस्तुत किया गया है जो 10-9-85 का है व उसमें वर्णित शर्तों के अनुसार श्रमिक को पूर्ण रूप से अस्थाई तौर पर 30 दिन की अवधि के लिए नियोजित किया गया था। इसके अलावा कोई भी नियुक्ति आदेश या नियोजन के संबंध में अन्य कोई प्रालेखीय साक्ष्य श्रमिक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्रमिक के शपथ पत्र से यह भी स्पष्ट है कि जिस अवधि में उसे नियोजक के यहां कार्यरत रहना बताया है उस बीच समय समय पर प्लाण्ट का कार्य बंद भी रहा था। सामान्य स्थिति में जिस अवधि में प्लाण्ट का कार्य बंद रहा उस बीच श्रमिकों को नियोजित करने की औचित्यता प्रकट नहीं होती। जिरह में श्रमिक ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि प्रारंभ में उसने मात्र 10-9-85 से 26-9-95 तक ही कार्य पर रखा गया था। इसके अलावा उसका यह भी कथन है कि दुबारा कोई भी नियुक्ति आदेश उसे नहीं दिया गया क्योंकि वह तो प्रारंभ से ही 29-1-87 तक लगातार नियोजन में था। इस सुझाव को भी श्रमिक ने अस्वीकार किया है कि दिसम्बर 1986 से जनवरी 1987 तक की निश्चित अवधि के लिए उसे नौकरी पर अंतिम बार लगाया गया था।

6. श्रमिक की ओर से जो दो अन्य गवाहान राम सिंह राठौड़ व जोगेन्द्र सिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए हैं उन दोनों ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि सितम्बर 1985 से 29-1-87 तक श्रमिक ने लगातार नियोजक के यहां कार्य किया था। गवाह राम सिंह राठौड़ संबंधित समय उस यूनियन का महासचिव था जिसके द्वारा श्रमिक के विवाद को प्रायोजित किया गया है व इसके अलावा उसने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि श्रमिक उसका रिश्ते में भाई लगता है। गवाह जोगेन्द्र सिंह का यह कथन है कि वह तथा मूल सिंह दोनों ही एक साथ शिफ्टिंग में प्लाण्ट में कार्य करते थे। गवाह राम सिंह ने शपथ-पत्र पर की गई जिरह में यह कहा है कि नियुक्ति आदेश मूल सिंह को कब से कब तक का दिया गया यह उसे पता नहीं। इस तथ्य को भी उसने स्वीकार नहीं किया है कि प्रारंभ में 10-9-85 से 26-9-85 की अवधि का नियुक्ति आदेश मूल सिंह को दिया गया था। 8-1-86 से पुनः मूल सिंह को नौकरी पर रखने के तथ्य को व 15-1-87 से उसकी सेवा समाप्त करने के तथ्य को भी इस गवाह ने स्वीकार नहीं किया है। गवाह जोगेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य बयान व जिरह में मात्र यह कहा है कि श्रमिक ने नौकरी से हटाने से पूर्व 240 दिन से अधिक अवधि तक नियोजक के यहां कार्य किया था किन्तु इस संबंध में कोई भी विशिष्ट तथ्य उसके द्वारा उल्लिखित नहीं किया गया है।

7. श्रमिक पक्ष की पूर्व संवर्णित साक्ष्य के विरुद्ध नियोजक की ओर से गवाह श्री के.डी.एस. राजावत ने उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर शपथ पत्र में यह बताया गया है कि 4-9-85 को प्रदर्श एम-1 आदेश कुछ पदों हेतु अस्थाई स्वीकृति के लिए जारी किया गया था व उसी के तहत श्रमिक मूल सिंह को प्रदर्श डब्ल्यू-1 के जरिये 10-9-85 से 30 दिन की अवधि के लिए प्लाण्ट पर नियोजित किया गया था। इस अवधि में श्रमिक ने 10-9-85 से 26-9-85 तक कार्य किया था व इसके पश्चात उसका नियोजन स्वतः ही समाप्त हो गया था। पुनः 8-1-86 से 2-6-86 व उसके पश्चात 13-6-86 से 3-9-86 तक श्रमिक को सेवा में रखने के तथ्य इस गवाह द्वारा पुष्ट किया गया है। इसके समर्थन में कुछ प्रलेख पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये हैं किन्तु उनको साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। सितम्बर 1986 के पश्चात 21-11-86 से श्रमिक को 15-1-87 तक की निश्चित अवधि के लिए नियोजित करना गवाह श्री के.डी.एस. राजावत की साक्ष्य में बताया गया है व इसके लिए स्वीकृति आदेश प्रदर्श एम-2 व नियुक्ति आदेश प्रदर्श एम-3 साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये हैं। गवाह का यह भी कथन है कि प्रदर्श एम-3 आदेश की शर्त के अनुसार 15-1-87 से श्रमिक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई थी। प्रदर्श एम-4 संचालित अवधि में सम्पूर्ण उप-स्थिति का विवरण गवाह द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न अवधि में श्रमिक को जिस प्रकार नियोजित किया गया उस तमाम अवधि को तोड़ने से किसी भी रूप में उसके द्वारा 240 दिन कार्य करने का तथ्य साबित नहीं होता है। श्री राजावत ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उस समय टंगस्टन विकास का जो प्लाण्ट डेगाना में कार्यरत था व बाद में हिन्दुस्तान जिंक लि. को हस्तांतरित हो गया तथा जिस अवधि में मूल सिंह की नियुक्ति व सेवा मुक्ति का विवाद उत्पन्न हुआ उस समय वह संबंधित प्लाण्ट पर कार्यरत नहीं था इसलिए मूल सिंह की सेवा अवधि के संबंध में उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि का यह कथन है कि गवाह द्वारा रिकार्ड के आधार पर जो साक्ष्य दी गई है वह श्रमिक की साक्ष्य की तुलना में किसी भी रूप में विश्वसनीय नहीं हो सकती। उनका यह

तर्क दोनों पक्षों की साक्ष्य को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जो भी प्रलेख नियोजक की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं वे प्लाण्ट में नियमित रूप से रखे जाने वाले प्रलेख की सत्यापित फोटो प्रतियां हैं तथा बिना किसी ठोस कारण के इन प्रलेख को गलत मानने का आधार नहीं बनता। श्रमिक की ओर से इन प्रलेख के मल प्रलेख तलब करवाने का किसी भी प्रक्रम पर कोई अनरोध नहीं किया गया है। जो प्रलेख नियोजक पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि श्रमिक द्वारा विवादित अवधि में 240 दिन तक नियोजक के यहां कार्य नहीं किया गया बल्कि तीन अलग अलग अवधि में निश्चित समय के लिए उसे प्लाण्ट पर नियोजित किया गया था व निश्चित अवधि के बाद स्वीकृति के अभाव में उसकी सेवाए स्वतः समाप्त हो गई थी। श्रमिक की ओर से लगातार 240 दिन कार्य करने की जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके समर्थन में कोई भी प्रलेख प्रस्तुत नहीं हुआ है। यह बात स्वाभाविक व विश्वसनीय नहीं लगती कि श्रमिक ने जिस अवधि में कार्य किया उसका वेतन उसे नहीं दिया गया व इसके बावजूद उसने इसकी कोई शिकायत कहीं भी नहीं की व न ही कोई वैधानिक कार्यवाही इस बाबत उसके द्वारा की गई। इस विवाद के निर्देशित होने के पूर्व कोई कार्यवाही इस संबंध में श्रमिक द्वारा की गई हो ऐसा उसका कथन नहीं है। श्रमिक द्वारा नियोजक पक्ष का अन्य कोई रिकार्ड तलब करवाने का अनुरोध भी नहीं किया गया है जिससे उसके कथन की पुष्टि हो सके। श्रमिक की ओर से ए.आई.आर. 1986 (एस.सी.) 1413 गोपाल किशन बनाम मोहम्मद हाजी का एक निर्णय प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिपादित सिद्धान्त तथ्यों को देखते हुए लागू नहीं होते। श्रमिक का किसी प्रकार से यह कथन नहीं है कि उसके नियोजन के संबंध में कोई भी अन्य रिकार्ड नियोजक के कब्जे में है जो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है नियोजक के गवाह से ऐसी कोई जिरह नहीं की गई है जिससे यह पता लगे कि अन्य रिकार्ड उपलब्ध होने के बावजूद उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा नियोजक के गवाह ने यह कहा है कि प्रस्तुत रिकार्ड के अलावा श्रमिक की सेवा का अन्य कोई रिकार्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है।

8. श्रमिक ने अपने क्लेम में सेवा मुक्ति की तिथि 23-1-87 बताई है जबकि नियोजक का जवाब में यह कथन है कि उसकी सेवा 15-1-87 को नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार स्वतः ही समाप्त हो गई। प्रदर्श एम--3 आदेश के पठन से नियोजक पक्ष के कथन की पुष्टि होती है व श्रमिक द्वारा 15-1-87 के पश्चात् काम करने के तथ्य के समर्थन में कोई भी प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस अवधि का वेतन भी उसे प्राप्त हुआ हो ऐसा श्रमिक का कथन नहीं हैं। श्रमिक के एक गवाह राम सिंह ने 23-1-87 से 29-1-87 तक श्रमिक का प्लाण्ट पर नियोजित रहना बताया है किन्तु इस प्रकार का कथन स्वयं श्रमिक का भी नहीं है। नियोजन के संबंध में जो विस्तृत विवेचन दोनों पक्षों की साक्ष्य के संबंध में पूर्व में किया गया है उसे देखते हुए श्रमिक का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि 15-1-87 के पश्चात् 28-1-87 तक उसने प्लाण्ट पर कार्य किया था।

9. दोनों पक्षों की विवेचित साक्ष्य का निष्कर्ष यह है कि श्रमिक द्वारा नियोजक के यहां 240 दिन काम करने का तथ्य प्रमाणित नहीं है व इस कारण धारा 25-एफ के प्रावधान कथित सेवा मुक्ति के मामले में लागू नहीं होते हैं यदि तर्क के लिए यह माना जावे कि श्रमिक को नियोजक द्वारा सेवा मुक्त किया गया था। यह मान्य स्थिति है कि कथित सेवामुक्ति के समय नियोजक द्वारा धारा 25-एफ अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई थी इसलिए इस संबंध में साक्ष्य पर और कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रदर्श एम-3 आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है कि श्रमिक को अन्य श्रमिकगण के साथ 45 दिन की अवधि के लिए प्लाण्ट पर अस्थाई रूप से नियोजित किया गया था इसलिए नियोजक पक्ष की इस साक्ष्य को प्रमाणित मानने पर श्रमिक की सेवाएं 15-1-87 के पश्चात् स्वतः ही सेवा शर्तों के अनुसार समाप्त हो गई, कथित सेवा मुक्ति पर मामला छंटनी की परिभाषा में धारा 2(00) (बी बी) के अन्तर्गत नहीं आता है। इस संबंध में नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि द्वारा 1985 एल. आई. सी. 1933, सी. एम. जीतेन्द्र कुमार बनाम भारत अर्थ मूवर्स, जीवन बीमा निगम बनाम राजीव कुमार श्रीवास्तवा 1994-II एल. एल. जे., (एम. पी.) 489 व 1994 एफ. जे. आर. 275 (पंजाब व हरियाणा) बनारसीदास बनाम श्रम न्यायालय, अम्बाला के निर्णय संदर्भित किये गये हैं। इन सभी निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां निश्चित अवधि के लिए संविदा के तहत किसी श्रमिक को नियोजित किया जाता है वहां उस अवधि के पश्चात सेवा समाप्ति का मामला धारा 2(00) (बीबी) के तहत छंटनी की परिभाषा में नहीं आता है।

11. जिन तथ्यों व विधिक स्थिति के संबन्ध में पूर्व में विचार किया गया है उसे देखते हुए श्रमिक द्वारा धारा 25–जी के प्रावधान की अवहेलना का जो तथ्य क्लेम में अभिकथित किया गया है वह विचारणीय नहीं है व इसके अलावा श्रमिक की ओर से इस संबन्ध में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके आधार पर भी धारा 25–जी के प्रावधान की अवहेलना नियोजक द्वारा करना सिद्ध नहीं होता है। शपथ पत्र के पद सं. 4 में श्रमिक ने एक सामान्य कथन यह किया है कि उसे सेवा से हटाया गया तब उससे कनिष्ठ श्रमिकगण को कार्य पर रखा गया था। किसी भी श्रमिक का नाम इस संबन्ध में उल्लिखित नहीं किया गया है। नियोजक के जबाव में यह बताया गया है कि चूंकि श्रमिक को एक निश्चित अवधि के लिए अन्य श्रमिकों के साथ सेवा में

नियोजित किया गया था इसलिए बाद में उनमें से किसी भी श्रमिक को सेवा में नहीं रखा गया इसलिए श्रमिक से कनिष्ठ कर्मचारियों को सेवा में रखने का कोई भी प्रश्न नहीं था ।

12. श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में पद सं. 10 में यह उल्लिखित किया है कि उसे सेवा से हटाने के पश्चात् अन्य श्रमिकगण को प्लान्ट पर नियोजित किया गया था व इस प्रकार नियोजक द्वारा धारा 25-एच के प्रावधान की पालना नहीं की गई । पूर्व में जो विचार किया गया है उसे देखते हुए श्रमिक का मामला छंटनी की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए धारा 25-एच के प्रावधान भी विचारणीय नहीं है व इसके अलावा श्रमिक के अपने क्लेम में धारा 25-एच के प्रावधान भी विचारणीय नहीं हैं इसके अलावा श्रमिक ने अपने क्लेम में धारा 25-एच के प्रावधान की अवहेलना के संबन्ध में कोई भी तथ्य उल्लिखित नहीं किया है वह यह मान्य विधिक स्थिति है कि अभिकथन के अभाव में किसी भी तथ्य के संबन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकती व न ही न्यायाधिकरण द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है । नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने करनाल सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण रोहतक एस. एल.जे. (पंजाब व हरियाणा) 1005 का एक निर्णय संदर्भित किया है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि संदर्भित विवाद में धारा 25-एच की अवहेलना के संबन्ध में कोई उल्लेख नहीं हो तो न्यायाधिकरण इस पर विचार करने के लिए वैधानिक रूप से सशक्त नहीं है। इस निर्णय के विरुद्ध अन्य कोई विधि दृष्टान्त श्रमिक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है तमाम विवेचित तथ्यात्मक व विधिक स्थिति को देखते हुए धारा 25-एच अधिनियम के प्रावधान की अवहेलना नियोजक द्वारा करना न तो साबित है व न यह स्थिति इस विवाद में विचार के लिए प्रसांगिक है ।

13. दुराचरण के सम्बन्ध में आरोप पत्र दिया जाना व उसके प्रभाव के संबध में श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में यह बताया है कि 20-1-87 को उसे जो आरोप पत्र दिया गया था उसका जवाब उसने 29-1-87 को प्रस्तुत कर दिया था किन्तु इस पर कोई कार्यवाही किये बिना उसे सेवा से हटाया गया था । श्रमिक के दो अन्य गवाहान राम सिंह व जोगेन्द्र सिंह ने भी इसी प्रकार का तथ्य वर्णित किया है । आरोप पत्र व उसके सम्बन्ध में श्रमिक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब की फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है यद्यपि उसे साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया गया है किन्तु इसलिए विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि नियोजक द्वारा अपने जवाब में वे श्री राजावत के शपथ पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि श्रमिक को आरोप पत्र 20-1-87 को जारी किया गया था । पूर्व में जिस तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया है उससे यह प्रमाणित माना गया है कि श्रमिक की सेवा नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार 15-1-87 को स्वतः ही समाप्त हो गई थी इसलिए कथित दुराचरण के आधार पर उसे सेवा से मुक्त करने का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता । नियोजक के गवाह ने शपथ पत्र में यह बताया है कि श्रमिक को दिये गये आरोप पत्र पर इसलिए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी क्योंकि उसकी सेवा 15-1-87 को ही समाप्त हो गई थी । इस तथ्य पर को भी जिरह गवाह नहीं की गई है । यह सही है कि 15-1-87 को सेवा समाप्ति के पश्चात् श्रमिक को आरोप पत्र देने का सामान्यतः कोई भी औचित्य नहीं हो सकता था किन्तु इसके लिए नियोजक के प्रतिनिधि का तर्क है कि अन्य कोई लोगों की भी आरोप पत्र इस प्रकार के दिये गये थे इसलिए श्रमिक को भी उनके साथ आरोप पत्र जारी कर दिया गया था किन्तु तथ्यों को देखते हुए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी इसलिए जांच नहीं की गई। यदि यह स्थिति प्रमाणित मानी जावे कि श्रमिक को 15-1-87 के पश्चात् व आरोप पत्र जारी करने के पश्चात सेवा से हटाया गया तो निश्चित रूप से यह विचार करने का आधार बन सकता था कि श्रमिक की सेवा मुक्ति की पृष्ठभूमि कथित दुराचरण हो सकती है । इसके विपरीत जो तथ्य साबित माने गये हैं उनको देखते हुए दुराचरण के आधार पर श्रमिक को सेवा मुक्त करने की धारणा लिया जाना न्यायोचित नहीं है । श्रमिक की ओर से इस सम्बन्ध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम के. एल. सहगल एस. एल. आर. 1995(1) दिल्ली 407 व गुरु प्रसाद बनाम यू. पी. राज्य 1990(4) एस. एल. आर. (इलाहाबाद) 400 के निर्णय संदर्भित किये गये हैं जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि सामान्य सेवा मुक्त के आदेश के उपलब्ध होने के बावजूद दोनों पक्षों की साक्ष्य व अभिकथनों के संदर्भ में न्यायाधिकरण यह विचार करने के लिए सक्षम है कि क्या श्रमिक की सेवा मुक्ति किसी दुराचरण के आधार पर की गई व न्यायाधिकरण इसके लिए साक्ष्य लेने को व सेवा मुक्ति की पृष्ठभूमि पर विचार करने के लिए सक्षम है। इन सिद्धान्तों पर कोई भी विवाद नहीं है किन्तु विवेचित तथ्यों को देखते हुए इनके आधार पर श्रमिक को कोई भी लाभ नहीं दिया जा सकता ।

14. अन्य कोई भी बिन्दु किसी भी पक्ष की ओर से बहस में प्रस्तुत नहीं किया गया है व न ही पक्षकारों के अभिकथन य साक्ष्य को देखते हुए मामले पर अन्य किसी दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

15. निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि श्रमिक मूल सिंह को नियोजक राजस्थान स्टेट टंगस्टन कार्पोरेशन लि. द्वारा दिनांक 16-1-87 से सेवा मुक्त करने की कार्यवाही उचित एवं वैध है व श्रमिक कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

16. अवार्ड आज दिनांक 15-9-95 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

के. एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 2 मई, 1996

का. आ. 1534:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार शुक्ला सोप स्टोन एवं पयना वाले माईन्स के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1 मई, 1995 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-29012 /2 /94-आई आर (विविध)]
बी एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 1996

S. O. 1534.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure. in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shukla Soap Stone and Piana Clay Mines and their workmen, which was received by the Central Government on 1-5-96.

[No. L-29012|2|94-IR(Misc)]
B. M. DAVID, Desk Officer

परिशिष्ट

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, राज०, जयपुर

केस नं. सी. आई टी 23/94

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या एल–29012 /2 /94 आई आर) दिनांक 5 अक्टूबर, 1994

श्री मदन लाल पुत्र श्री देवी लाल द्वारा भारतीय खान मजदूर संघ, कार्यालय, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

शुक्ला सोप स्टोन एवं पयना क्ले माईन्स, बहादुरपुरा, पोस्ट—आमलटा, तहसील जहाजपुरा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के० एल० व्यास आर०एच०जे०एस० ।

प्रार्थी की ओर से	कोई नहीं
अप्रार्थी की ओर से	कोई नहीं
दिनांक अवार्ड	27-9-95

अवार्ड

किसी भी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । पूर्व में भी लगातार कई तारीखों पर किसी भी पक्ष का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था । गत पेशी पर नियोजक पक्ष के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश किया गया था व यूनियन की साक्ष्य हेतु आज तारीख दी गई थी । यूनियन की ओर से क्लेम प्रस्तुत करने के पश्चात् आज तक वस्तुतः कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है । उनकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि संबंधित यूनियन क्लेम को प्रेरित नहीं करना चाहती है व साक्ष्य हेतु अवसर देने का कोई भी न्यायोचित कारण नहीं है यूनियन पक्ष की साक्ष्य बंद की जाकर प्रकरण में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित करने के आदेश दिये जाते हैं जो केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

के० एल० व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 2 मई, 1996

का. आ. 1535:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री रंगीलाल माईन ओनर, सेन्ड स्टोन माईन के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-96 प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29012 /30/92-आई आर (विविध)]
बी० एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 1996

S.O. 1535.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shri Rangi Lal, Mine Owner Sand Stone Mine and their workmen, which was received by the Central Government on 1-5-96.

[No. L-29012/30/92-IR (Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई.टी. 14/1992

रेफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. एल-29012/30/92-आई.आर. एम. एंड सी. 5–8–92

श्री बाबू लाल पुत्र श्री शिम्भू राम जाति अग्रवाल आयु 51 वर्ष निवासी हिन्डोन । ---प्रार्थी

बनाम

श्री रंगीलाल माईन ओवर सेंड स्टोन माईन करौली जिला सवाई माधोपुर ---प्रार्थी

माननीय न्यायाधीश श्री के. एल. व्यास, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री एम. एफ. बेग

अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं

दिनांक अवार्ड : 22-5-95

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा निम्न विवाद अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है :

'Whether the action of Shri Rangi Lal, Mine owner Sand stone Msne, Karauli, district Sawai Madhopur in terminating the services of Shri Babu Lal S/o Shri Shambhu lal Clerk w.e.f. 1-10-90 is legal & justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled to and from what date ?'

2. श्रमिक के क्लेम में वर्णित तथ्यों के अनुसार उसने विपक्षी/नियोजक के यहां 1-9-63 से मुनीम के पद पर कार्यभार संभाला था व उस तिथि से 1-10-90 तक लगातार विपक्षी के यहां नियोजित रहा । श्रमिक के अनुसार 1-10-90 से नियोजक द्वारा उसकी सेवाएं बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस व क्षतिपूर्ति को समाप्त कर दी गई। श्रमिक का यह भी कथन है कि उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व नियोजक द्वारा धारा 25-जी के प्रावधान की पालना भी नहीं की गई।

3. नोटिस विपक्षी को न्यायाधिकरण द्वारा जारी किया गया था व उसकी तामील के बावजूद नियोजक की ओर से न्यायाधिकरण के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । नोटिस की तामील विपक्षी पर जरिये रजिस्टर्ड डाक करवाई गई थी जिसकी प्राप्ति की रसीद पत्रावली पर उपलब्ध है। नियमानुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा विवाद को इस न्यायाधिकरण में निर्देशित करने का नोटिस भी विपक्षी को भेजा गया था परन्तु इस नोटिस व न्यायाधिकरण के नोटिस के पश्चात् भी नियोजक द्वारा कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया इसलिये नियोजक के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

4. श्रमिक ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है व इसके अलावा कुछ प्रलेख की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की हैं। बहस सुनी गई व उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रलेख पर विचार किया गया।

5. श्रमिक के शपथ पत्र से तथ्य प्रथम दृष्टया साबित होता है कि उसे नियोजक द्वारा 1-9-63 से नियोजित किया गया था व धारा 25-जी एफ व 25-जी औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान की पालना किये बिना उसकी सेवायें 1-10-90 से समाप्त की गई। शपथ पत्र के पट सं. 6 में यह भी बताया गया है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से पूर्व कोई वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई व उस समय श्रमिक से कनिष्ठ अन्य कामगार यादूराम, संजीव कुमार व भारत भूषण नियोजक के यहां मुनीम के पद पर कार्यरत थे। श्रमिक की ओर से जो प्रलेख प्रस्तुत किये गये हैं उनमें सहायक श्रम आयुक्त केन्द्रीय सरकार को भेजे गये परिवाद की फोटो प्रति, सहायक श्रम आयुक्त द्वारा नियोजक को परिवाद का नोटिस भेजने के पत्र की फोटो प्रति व भविष्य निधि खाते में श्रमिक के नाम से समय समय पर रकम जमा होने के प्रलेख की फोटो प्रतियां हैं। श्रमिक की मौखिक व प्रालेखीय साक्ष्य से यह साबित माना जाता है कि उसने नियोजक के यहां मुनीम के पद पर 1-9-63 से कार्य प्रारंभ किया था व उसकी सेवाएं नियोजक द्वारा 1-10-90 से धारा 25-एफ व जी की पालना के बिना समाप्त की गई। श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में यह भी उल्लिखित किया है कि वह सेवा मुक्ति की तिथि में बेरोजगार है। संबंधित प्रलेख से यह भी साबित है कि श्रमिक द्वारा सेवा मुक्ति के बाद बिना असाधारण विलम्ब के सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया । इन परिस्थितियों में श्रमिक समस्त बकाया वेतन का लाभ भी प्राप्त करने का अधिकारी भी है।

6. निर्देशित विवाद में एक पक्षीय अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि नियोजक श्री रंगीलाल माईन ओनर करौली जिला सवाई माधोपुर द्वारा 1-10-90 से श्रमिक बाबू लाल की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही अनुचित व अवैधानिक है परिणामस्वरूप श्रमिक पुनः सेवा में आने का, सेवा की निरन्तरता बनाये रखने का व सेवा मुक्ति की तिथि से सेवा में आने की तिथि तक समस्त बकाया वेतन व अन्य वित्तीय परिलाभ नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अवार्ड आज दिनांक 22-5-95 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जाये।

के. एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का. आ. 1536— औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1974 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ——————के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1 मई, 1996 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल 41012/4/91 आई आर]

पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1536.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publisshes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of N. Eastern Railway, and their workman which was received by the Central Government on 1-5-1996.

[No. L-41012/4/91-IR (B-I)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR& COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 153 of 1991

In the matter of dispute :

BETWEEN

Zonal Working President
Uttar Railway Karamchari Union
6/196 Roshan Bajaj Lane Ganeshganj
Lucknow

AND

D.S.T.E. (Construction)
North Eastern Railway
Ashok Marg, Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-41012/4/91-I.R. (DU) dated 25-9-91, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the DSTE (Construction) North Eastern Railway Lucknow is justified in terminating the services of Sri Izharul Huda Khan S/o Fauzdar Khan as Wireman w.e.f. 6-8-86 ? If not, what relief the workman concerned is entitled to ?

2. Instant case was fixed for evidence on 19-12-95 but when none appeared from the side of the Union, it was debarred. Management met same fate on 2-2-96. The result is that there is no evidence in the case.

3. From the above, I am inclined to hold that the Union is not interested in prosecuting the case. As such reference is answered in affirmative for want of evidence of the parties. Consequently, it is held that the Union is not entitled for any relief.

4. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1996

का. आ. 1537—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मध्य रेलवे के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1 मार्च 1996 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/56/90 आईआरबी-I]
पी. जे. माईकल डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1537.—In pursuace of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government

Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Railway and their workman, which was received by the Central Government on 1-5-1996.

[No. L-41012/56/90-IR (B-I)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 69 of 1993

In the matter of dispute :

BETWEEN

President,
Rashtriya Chaturth Shreni Rail Maldoor Congress, Namnair, Agra.

AND

D.M.E. (C and W)
Central Railway,
Jhansi-284001.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-41012/56/90-I.R. (DU) dated 3-4-91, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the D.M.E., Carriage and Wagon Workshop Deptt. of Central Railway, Jhansi is justified in removing Shri Banke Behari Lal, MRCL w.e.f. 1-11-85 ? If not, what relief the workman concerned is entitled to ?

2. It is not necessary to give facts of the case, as the authorised representative of the concerned workman Sri Banke Behari Lal has made statement on 18-3-96 that he does not press the claim.

3. In view of above I answer the reference against the workman. It is further held that the concerned workman is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का. आ. 1538.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1 मई 1996 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41011/16/85 आई आरबी-I]
पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1538.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Paschim Railway, and their workman, which was received by the Central Government on 1-5-1996.

[No. L-41011/16/85-IR (B-I)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर
केस नं. सी० आई० टी० 18 /86

रैफरेंस :— केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रम एल 41011/(16)/85-डी. II (बी) दि. 27-2-86

श्री बी. स्टीफन द्वारा डिवीजनल चैयरमैन, पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद, 33/ए रेलवे कालोनी, कलोल —प्रार्थी

बनाम

जनरल मैनेजर, वैस्टर्न रेलवे, बाम्बे

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के. एल. व्यास, आर. एच. जे. एम०

प्रार्थी की ओर से — श्री आर. सी. जैन
अप्रार्थी की ओर से — श्री बी एस माथुर
दिनांक अवार्ड 11-10-1995

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा निम्न विवाद अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है :

"क्या महाप्रबन्धक, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट बम्बई का इस समय अहमदाबाद के मुख्य आरक्षण निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे श्री बी. स्टीफन को 425—640 रुपये के वेतनमान में सहायक आरक्षण सुपरवाईजर के रूप में 24-12-74 के वरिष्ठता न देना न्यायोचित है यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।"

2. श्रमिक यूनियन की ओर से प्रस्तुत क्लेम में जो तथ्य अभिलिखित किये गये हैं वे सारांश में इस प्रकार हैं कि श्रमिक की नियुक्ति विपक्षी रेलवे में 3-11-54 को हुई थी, 1974 में वह सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर वेतनमान 330-560 में कार्यरत था, उस वर्ष दुर्घटना में चोट आने के कारण उसे चिकित्सीय रूप से उस पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया, इसके परिणामस्वरूप 24-12-74 को उसे इन्क्वायरी-कम-रिजर्वेशन क्लर्क के पद पर 330-560 के वेतनमान में समायोजित किया गया, उस तिथि से पूर्व नियोजक द्वारा उसकी पदोन्नति सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में वेतनमान 425—640 के वेतनमान में कर दी गई थी इसलिए उसने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि उसे नये पद पर उसी वेतनमान में समायोजित किया जावे व जिन व्यक्तियों को वरिष्ठता में उनसे उपर बताया गया है उसे संशोधित किया जाकर श्रमिक की वरिष्ठता सही स्थान पर निश्चित की जाये। इसके आगे यह भी बताया गया है कि रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 14-12-76 के श्रमिक को वेतनमान 425-640 में स्थिर कर दिया गया था व तत्पश्चात 12-3-82 के आदेश से इस वेतनमान की वरिष्ठता सूची को संशोधित करते हुए श्रमिक को क्रम सं. 6(अ) पर बताया गया किन्तु इससे पूर्व श्री टी. के. नैनी को 455-700 के वेतनमान में 22-9-76 को पदोन्नत कर दिया गया जो कि वरिष्ठता सूची में क्रम सं. 11 पर थे। अनुतोष यह क्लेम किया गया है कि श्रमिक को 455—700 के वेतनमान में 22-9-76 से पदोन्नति दी जावे व उसी के अनुरूप एरियर का लाभ स्वीकृत किया जावे।

3. नियोजक की ओर से प्रस्तुत जवाब में श्रमिक द्वारा वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया गया है व यह बताया गया है कि वेतनमान के निर्धारण व वरिष्ठता के संबंध में जो भी व्यथा कर्मचारी की थी उसका निराकरण स्वयं उसके अभिकथनों के अनुसार हो गया है इसलिए वह कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। श्री नैनी की पदोन्नति के संबंध में यह बताया गया है कि वेतनमान 455-700 का पद चयन प्रक्रिया से भरने का है व इसके लिए विभागीय परीक्षा ली गई थी जिसमें श्री नैनी उतीर्ण हुए थे किन्तु श्रमिक इस परीक्षा में उतीर्ण नहीं हुआ इसलिए उसे पदोन्नत नहीं किया गया। यह भी बताया गया है कि श्रमिक को 425-640 के वेतनमान में मानते हुए परीक्षा में शामिल किया गया था।

4. श्रमिक यूनियन की ओर से क्लेम के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। नियोजक की ओर से एक गवाह श्री बी. वी. देसाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है वह संबंधित आदेशों की फोटो प्रतियां प्रदर्श एम —1 से एम-3 प्रस्तुत की गई हैं बहस दोनों पक्षों की सुनी गई।

5. नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने बहस के समय एक आपत्ति यह प्रस्तुत की कि श्री आर. सी. जैन को इस प्रकरण में प्रतिनिधित्व करने के निदेश यूनियन या संबंधित कर्मचारी की ओर से नहीं है इसलिए वे प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं हैं। इस विवाद का निस्तारण न्यायाधिकरण द्वारा 6-3-92 के आदेश से किया गया था व लिखित में जो आपत्तियां नियोजक की ओर से ली गई थी उन्हें खारिज किया गया था। ऐसी स्थिति में पूर्व में पारित नियुक्ति आदेशों को पुनरावलोकित करने का कोई भी आधार नहीं है व ऐसा कोई अनुरोध भी नियोजक की ओर से नहीं किया गया है अतः श्री आर० पी० जैन के प्रतिनिधित्व के संबंध में ली गई आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है।

6. दोनों पक्षों के प्रस्तुत अभिकथनों, मौखिक साक्ष्य व प्रालेखीय साक्ष्य से यह सिद्ध है कि श्रमिक को रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 14-12-76 (प्रदर्श एम-1) के जरिये 24-12-74 से 425-640 की वेतन श्रृंखला स्वीकृत की गई थी, उस वेतनमान में उसकी वरिष्ठता क्रम तिथि से वेतनमान

स्वीकृत करने के कारण संशोधित की जाकर उसको सही स्थान पर वरिष्ठता में रखा गया था जिसके आदेश प्रदर्श एम-2 हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जिस रूप में विवाद निर्देशित किया गया है उसके अनुसार न्यायाधिकरण को मात्र यह अभिनिर्धारित करना है कि श्रमिक स्टीफन को 24-12-74 से सहायक आरक्षण निरीक्षक के पद पर वेतनमान 425-640 में वरिष्ठता प्रदान नहीं करने की कार्यवाही नियोजक की उचित है या नहीं श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि भी पूर्व विवेचन को देखते हुए इस बात से सहमत है कि यह अनुतोष नियोजक द्वारा श्रमिक को प्रदान किया जा चुका है व इस कारण कोई भी विवाद इस बाबत शेष नहीं है। उनका तर्क यह है कि न्यायाधिकरण संशोधित वरिष्ठता के आधार पर अन्य सुसंगत व पारिणामिक लाभ स्वीकृति करने के लिए सक्षम है इसलिए 22-9-76 से श्रमिक को 450-700 के वेतनमान में पदोन्नति करने का आदेश दिया जावे क्योंकि उस रोज उससे कनिष्ठ श्री नैनी को इस वेतनमान में पदोन्नत किया गया था इस प्रकार को अनुतोष प्रत्यक्ष रूप से निर्देश के स्वरूप को देखते हुए स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार न्यायाधिकरण को उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा गुण दोष पर भी यह अनुतोष स्वीकृत इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि नियोजक के जवाब के खण्ड में श्रमिक ने यह रोजोइण्डर प्रस्तुत नहीं किया है कि उसे 455-700 के वेतनमान में पदोन्नति के लिए श्री टी. नैनी के साथ परीक्षा में नहीं बुलाया गया था व इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य भी श्रमिक की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। परीक्षा का कोई रिकार्ड भी श्रमिक द्वारा तलब नहीं करवाया गया है नियोजक के गवाह श्री देसाई ने शपथ पत्र में यह बताया है कि पदोन्नति हेतु श्री नैनी के साथ श्रमिक को भी परीक्षा में बुलाया गया था किन्तु वह उत्तीर्ण नहीं हुआ था श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि का कथन है कि श्रमिक को 425-640 के वेतनमान में समायोजित करने का आदेश 14-12-76 को प्रदर्श एम 1 जारी किया गया था यद्यपि उसे 24-12-74 से प्रभावी बनाया गया है इसलिए सितम्बर 1976 से पूर्व श्रमिक को इस वेतनमान में मानते हुए पदोन्नति हेतु परीक्षा में बुलाने का आधार नहीं हो सकता नियोजक के प्रतिनिधि का कथन है कि 425-640 के वेतन में अस्थाई वरिष्ठता श्रमिक को पूर्व में दी गई थी व अभिकथनों में भी ऐसा बताया गया है। निष्कर्ष यह है कि 22-9-76 को जारी पदोन्नति के आदेश के संबंध में परीक्षा में नहीं बुलाने बाबत श्रमिक द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है व सीधे रूप से इस प्रकार का अनुतोष इस विवाद में स्वीकृत नहीं किया जा सकता किन्तु उपलब्ध विधि दृष्टान्तों को देखते हुए यह उल्लेख न्यायाधिकार कर सकती है कि 24-12-74 से श्रमिक की वरिष्ठता 425-640 के वेतनमान में मानते हुए यदि नियमानुसार कोई भी सुसंगत लाभ प्राप्त करने का वह अधिकारी हो तो नियोजक द्वारा इस संबंध में उचित आदेश पारित किये जायेंगे।

7. निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि तारीख 24-12-74 से श्रमिक का वेतनमान 425-640 नियोजक द्वारा स्वीकार किया जाकर उसकी वरिष्ठता उसी तिथि से निश्चित की जा चुकी है इसलिए इस संबंध में वह कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है 24-12-74 से 425-640 में वरिष्ठता प्राप्त करने के कारण यदि कोई भी पारिणामिक लाभ श्रमिक नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है तो वह नियोजक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

8. अवार्ड आज दिनांक 11-10-95 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये।

के. एन. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का.आ. 1539—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.बी.बी.जे. के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/46/86-आई आर बी आई]
पी.जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1539.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.B.B.J. and their workman, which was received by the Central Government on 1-5-1996.

[No. L-12012/46/86-IR (B-I)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR DEOKI PALACE ROAD KANPUR

Industrial Dispute No. 10 of 1987

In the matter of dispute :

BETWEEN

Sri Arvind Kumar
C/o V. N. Sekhari
U.P. Bank Employees Union
26/104 Birhana Road
Kanpur.

AND

The Manager

State Bank of Bikaner and Jaipur

Birhana Road

Kanpur.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-12012/46/86-D.II (A) dated 19-1-1987, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur, Birhana Road Kanpur in terminating the services of Sri Arvind Kumar w.e.f. 8-11-73, is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?

2. The concerned workman Arvind Kumar in his claim statement has alleged that he was appointed as peon in the Birhana Road Branch Kanpur of opposite party State Bank of Bikaner and Jaipur on 3-7-78 and continued to work there upto 7-11-79 for a period of 227 days. His services were illegally terminated w.e.f. 8-11-79. As no retrenchment compensation and notice pay under Section 25-F of Industrial Disputes Act was give, further juniors to the concerned workman were retained in service, further fresh hands were appointed but no opportunity was afforded to the concerned workman hence, there has been breach of Sections 25-G, 25-H of I. D. Act. Further the concerned workman has referred to a number of paras of Desai Award and Bipartite Settlement, the provisions of which are analogous to that of above mentioned Industrial Disputes Act.

3. The opposite party has filed reply in which it is alleged that the concerned workman was appointed for for a fixed period and he did not complete 240 days in a calender year by render continuous service. As such his fase falls within the exception of sub-section (oo) of Section 2(bb) of I. D. Act. In all the concerned workman had worked for 59 days on regular basis and further for 153 days as daily rated worker. In this way he had render for 212 days. It is denied that the juniors to the concerned workman were retained.

4. In rejoinder, the concerned workman has reiterated the facts alleged in the claim statement and has denied the factual pleas raised in the written statement.

5. It may be mentioned that during the pendency of the case the management also moved an application on 10-3-88 informing the Tribunal that circular was issued on 23-8-87 to all retrenched employees to appear in the test. The concerned workman failed to appear in the test hence he is not entitled for any relief from this Tribunal.

6. In the first place it has to be seen as to whether the concerned workman has completed 240 days in a calender year. He has also alleged that he had worked from 3-7-78 to 7-11-79, whereas according to management he has worked for 212 days. It is not very material as to whether the concerned workman has worked for 212 days or 227 days as in either case the Sundays and other holidays have not been included which ought to have been included as they are termed as artificial breaks, beyond the control of the workman. Hence if we include even 52 Sundays in a year it will exceed 240 days. In this way I accept the statement of Arvind Kumar that he has completed for more than 240 days in a calender year. Admittedly he has not been paid retrenchment compensation and notice pay, hence his termination is in utter breach of Section 25-F of I. D. Act.

7. There is no evidence, worth the name of show that juniors to the concerned workman were retained in service. Hence the concerned workman is not entitled for benefit of Section 25-G of I. D. Act. As regards applicability of Section 25-H of the Act, once again reference may be made to letter dated 23-4-87 issued by the opposite party informing all the retrenched employees including the sub-taff of the nature of peon to appear in interview test. The management has also filed the extracts of advertisement in press to show that general notice was issued to all but the applicant had failed to take advantage of it. In the case of Management of State Bank of Bikaner and Jaipur versus Their workmen Civil Appeal 7029 of 1944 decided on 8-2-96 Hon'ble Supreme Court has held that where opportunity by way of holding test for accommodating retrenchment employee and the retrenched either employees either fails in the test or fails to appear in the test he will not be entitled for the benefit of Section 25-H of I. D. Act. In view of this authority the concerned workman is not entitled for benefit of Section 25-H of I. D. Act.

8. Thus from the above discussion it will be evident that termination of the concerned workman is bad because of breach of Section 25-F I. D. Act. As is evident termination took place on 8-11-79 whereas this dispute was raised in 1986. Thus there has been delay for about more than 6, 7 years. In the case of Balwant Singh versus Labour Court Bhatinda, 1996 Lab. I. C. 45 (Punjab), it has been held that in the absence of satisfactory explanation for delay in claiming reference. Delay of six years was held to be sufficient to refuse reinstatement. Instead in lieu of reinstatement reasonable compensation is to be awarded.

9. Hence, the concerned workman will not be entitled for reinstatement and will be entitled for compensation.

10. Accordingly my award is that the termination of concerned workman is bad in law. However, the concerned workman will not be entitled for reinstatement. Instead he will be entitled for Rs. 10,000 as compensation in lieu or reinstatement.

11. Reference is accordingly answered.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का.आ. 1540.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दी बैंक आफ राजस्थान लि. के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/11/89-आईआरबीआई]

पी.जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1540.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of The Bank of Rajasthan and their workman, which was received by the Central Government on 1-5-1996.

[No. L-12012/11/89-IR (B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर,

केस नं. सी.आई.टी. 23/1990

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एल. 12012/11/19 दिनांक 2-3-1990

बैंक ऑफ राजस्थान एम्पलाईज यूनियन,
रामपुरा बाजार, कोटा .....प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबन्धक, दी बैंक ऑफ राजस्थान लि.,
एरोड्रम सर्किल, कोटा .....अप्रार्थी

उपस्थित :

माननीय न्यायाधीश श्री के.एल. व्यास, आर एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे.एल. शाह
अप्रार्थी की ओर से : श्री आलोक फतहपुरिया
दिनांक अवार्ड : 12-10-95

अवार्ड

श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि श्री जे.एल. शाह व यूनियन के जिला सचिव श्री अरविंद सक्सैना तथा नियोजक की ओर से प्रतिनिधि श्री आलोक फतहपुरिया उपस्थित हैं। इस प्रकरण में प्रलेख प्रस्तुत होने के लिए पत्रावली आज निश्चित की हुई है किन्तु दोनों पक्षों ने स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित समझौता प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में समझौते के आधार पर अधिनिर्णय पारित करने का अनुरोध किया है। समझौता दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया गया व उनके द्वारा स्वीकार करने पर अभिप्रमाणित किया गया। अतः पक्षकारों की प्रार्थना पर प्रकरण में समझौते के आधार पर एवं समझौते में उल्लिखित शर्तों पर अधिनिर्णय पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये। समझौता अधिनिर्णय के भाग के रूप में पढ़ा जायेगा।

के.एल. व्यास, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का.आ.1541.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-41012/49/92-आईआरबी-I]
पी.जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1541.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway and their workman, which was received by the Central Government on 1-5-1996.

[No. L-41012/49/92-IR (B-I)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 88 of 1993

In the matter of dispute :

BETWEEN

Dinanath Tewari
President
Uttar Railway Karamchari Union
2 Navin Market Parede Kanpur.

AND

Mandal Rail Prabandhak
Uttar Railway
Allahabad.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-41012/49/92-I.R. (DU) dated 30-9-93, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the management of DRM, Northern Railway Allahabad, is justified in terminating the services of Sri Sunil Kumar Sharma w.e.f. 15-2-82 and again appointing him a fresh w.e.f. 4-5-87 ? If not, what relief he is entitled to ?

2. The concerned workman Surendra Kumar was posted as Welder with the opposite party Northern Railway, Kanpur On 3-6-81, Supriya Sen EFO/T alongwith others were retrenching at about 11.30 a.m. in the Locoshed at Kanpur, when they found near outpit 4 persons playing cards during office hours. Three of them manage to escape from the spot but the concerned workman was caught red handed alongwith playing cards and a Rs. 10 note. In this regard a report was sent on that very day. On the basis of this report chargesheet dated 18-6-81 Ext. W-7 was given to the concerned workman in standard form No. 5. During the course of evidence Raju Kurian, Supriya Sen and Arvind Kumar were examined. On the basis of above it was found that the case against the concerned workman was proved. Consequently dismissal order dated 15-9-82 was passed. Appeal was also dismissed. Feeling aggrieved the concerned workman filed a civil suit in the court of Munsif Kanpur which was dismissed. Civil Appeal No. 80/84 was filed in the court of District Judge, which after the establishment of C.A.T. was transferred to CAT where it was registered as T.A. No. 783 of 86. By order dt. 6-11-86 Central Administrative Tribunal has allowed the case and directed the punishing authority to reconsider the appeal of the applicant and pass orders supported by reasons The appeal has again been rejected by order dated 12-1-87. Feeling agerieved, the concerned workman has raised the industrial dispute.

3. In the claim statement in the first place the genesis of industrial dispute has been given. But at no where it had been denied that he was not cought red handed playing cards. Instead his grievance is that three other associates were also chargesheeted Out of them first was meted out with the punishment of stoppage of increments for two years, the second was punished by withholding of pass and third was not punished at all. In this way there has been discrimination in awarding the punishment.

4. It may be mentioned that a memorial was given after the dismissal of appeal which was considered and order dated 4-8-87, the concerned workman was given fresh appointment. It is alleged that the punishment of dismissal dted 15-2-82, is too harsh.

5. The opposite party has failed to put in appearance inspite of sufficient service.

6. In support of his case, the concerned workman has examined himself as WW-1. Besides he has filed Ext. W-1 to W-7 pertain to enquiry.

7. From the above, narration of facts it will be evident that the concerned workman himself does not dispute the fact that he was caught red handed playing cards during office hours. Hence, there is no need to go into this fact.

8. As regards the quantum of punishment, the railway has not turned up to rebut the version of the concerned workman that others three have not been awarded punishment of dismissal. In this way there could be no manner of doubt that there has been hostile discrimination between the same class of persons and placed in similar circumstances in awarding punishment which would in turn attract the provisions of Article 14 of Constitution of India.

9. Hence, my conclusion is that order of dismissal dated 15-2-82 being too harsh is not justified. As such it should be set aside. The concerned workman has already been given appointment on 4-5-87, the concerned workman should be granted continuity of service in between 15-2-82 and 4-5-87 for promotion, pensionary benefits and gratuity. However, he will not be entitled for back wages for this period which is denied by way of punishment.

10. I award accordingly.

Dated : 22-3-1996

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का.आ. 1542—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-12012/192/94-आईआरबीआई]

पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1542.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Balia Kshetriya Gramin Bank and their workman, which was received by the Central Government on 1-5-1996.

[No. L-12012/192/94-IR (B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 38 of 1955

In the matter of dispute :

BETWEEN

Sri Markandey Dubey
Village and Post Akhar
District Ballia U.P.

AND

The Chairman
Ballia Kshetriya Gramin Bank
Head Office Idris Market
Ballia.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/192/94-I.R. (B-I) dated 22-3-95 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Ballia Kshetriya Gramin Bank, Ballia in terminating the services of their employee Shri Markendaya Dubey, Clerk-cum-Cashier at Srinagar Branch is justified ? If not what relief the workman is entitled to ?

2. The concerned workman Markenday Dubey in his claim statement has alleged that he was appointed as clerk-cum-cashier after being selected by Banking Service Recruitment Board Lucknow on 1-3-85. He worked for 10 days. On 11-3-85, he proceeded on leave because of illness upto 30-4-85 which was sanctioned without pay, as no leave was due. Thereafter he continued to remain ill and went on giving leave applications supported by medical certificate from 1-7-85 to 3-3-83, the details of which have been given in para 10 of the statement of claim. On 5-7-93, he became medically fit as such after obtaining fitness certificates he reported for duty but he was not permitted to join. That amount to termination of services. It is bad in law because one month's notice was not given. In any case if it is a case of abondonment, no domestic enquiry was held. Principle of Sections 25-G and 25-H have also not been observed. Further he has not been paid wages from 1-3-85 to 10-3-85.

3. The opposite party has filed reply in which it is alleged that from 11-3-85 the concerned workman did not turn up. His initial application was sanctioned. Thereafter no leave application much less supported by medical certificate was ever received. After passage of about 8 years, with oblique motives, the concerned workman had approached the bank. As it was the case of implied abondonment there was no need to hold enquiry or give notice pay.

4. In support of his version the concerned workman has filed Ext. W-1 to W-23 out of them Ext. W-1 is the leave application dated 11-3-85. From Ext. W-2 to 24 are leave applications of various dates from 30-4-85 to 3-3-93. Ext. W-25 is joining application. Ext. W-26 is the letter addressed to District Magistrate seeking his intervention. Ext. W-30 to 32 are medical certificates of 22-8-89, 30-5-93 and 3-7-93. Ext. 33 to 35 are papers relating to conciliation proceedings.

5. Besides the concerned workman has examined himself.

6. The opposite party has filed 12 papers. Further they have examined manager Laxaman Tiwari MW-1.

7. The first point which needs for consideration is as to whether the concerned workman after 30-4-85 upto 5-7-93 continue to remain ill.

8. In support of his version the concerned workman has given his evidence in which he has stated that he was ill and had applied for medical leave. In his cross examination he has stated that he used to sent his application supported by medical certificate through his brother but no acknoledgement was given. He had got treated himself at Chapra.

9. Laxaman Tiwari MW-1 has stated that no applications were received from the applicant at any time. I have gone through the medical certificates which go to reveal that the causes of illness has been conflicting from the very beginning. I am fully satisfied that these medical certificates have been manipulated for the purpose of this case othtrwise the doctor who had treated the applicant would have been brought into the witness box. Further had these certificates been genuine they would have been sent by registered post. Further the opposite party is a public bank. No one had any grudge against the concerned workman. It is unlikely if the applicant would have sent the certificate and the leave application the same would not have been entered in the receipt register. Further the applicant has not examined his brother through whom leave applications and medical certificates are said to have been handed over to the opposite party. Thus taking over all view of the matter, I disbelieve the version of the applicant and hold

that he was not ill and had also not submitted any leave application supported by any medical certificate. Instead the applicant had continued to absent himself with oblique motive.

10. The authorised representative of the concerned workman has drawn my attention to the case of Arun Kumar Mathur and Labour Court and another, 1993 FLR (66), 211 (Allahabad High Court) in which it was held that voluntary abandonment would not fall within Section 2(00) of I. D. Act, hence compliance of retrenchment is necessary. This ruling will not apply to the facts of the present case. This was a case in which in order to deprive the workman the benefit of continuous services on false plea the Management had set up of abandonment of service. In this context it was held that procedure of retrenchment ought to have been adopted. In the instant case admittedly the concerned workman himself for reasons best known to him continue to remain absent. Hence, in such a case there was hardly any need for domestic enquiry and show cause notice. This situation also did not call for giving of notice pay, principles of natural justice cannot be said to have been voilated. In such a state of affairs provisions of Sections 25-G and H would also not be attracted.

11. Hence in the end my award is that the services of the concerned workman were not terminated by the opposite party Ballia Kshetriya Gramin Bank at all. As such question of its being justified does not arise at all. Consequently, the concerned workman is entitled to no relief.

12. Reference is answered accordingly.

Dated : 29-3-1996

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का.आ. 1543.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/148/93-आईआरबीआई]

पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1543.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway and their workman, which was received by the Central Government on 1-5-1996.

[No. L-41012/148/93-IR (B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 82 of 1994

In the matter of dispute :

BETWEEN

Shri Raig Singh

S/o Shri Mathura Prasad
Village Tasipur,
Post Office Tasipur Khas
Haridwar-249401.

AND

Mandal Rail Prabandhak
Northern Railway,
Moradabad-244001.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-41012/148/93-I.R. (DU) (B-I) dated 22-9-94, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Northern Railways in terminating the services of Shri Raig Singh, workman w.e.f. 4-8-1989 is legal and justified ? If not, what relief the workman is entitled to ?

2. The concerned workman Raig Singh has raised this industrial dispute regarding his termination w.e.f. 4-8-89 against the opposite party Northern Railway. After filing claim statement the concerned workman consistently absented himself that shows that he is no more interested in the case.

3. Hence the reference is answered against the concerned workman for want of proof. It is further held that the concerned workman is not entitled any relief.

Dated : 25-4-1996

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का.आ. 1544.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-41012/55/92-आईआरबीआई]

पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1544.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway and their workman, which was received by the Central Government on 1-5-1996.

[No. L-41012/55/92-IR (B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 78 of 1993

In the matter of dispute :

BETWEEN

Zonal Working President,

Uttar Railway Karamchari Union,
96/196 Roshan Bajaj Lane,
Ganeshganj,
Lucknow.

AND

Senior Divisional Personnel Officer
Northern Railway,
Allahabad.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-41012/55/92-IR (DU) dated 24-9-93, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the demand of the Union for reinstatement with full back wages w.e.f. 21-9-87 barring wages of 101 days paid in 1989 of Shri Ram Prakash, son of Shri Ram Sagar, casual labour (Khalasi) in the establishment of Divisional Signal and Telecom Engineer, Aligarh under S.I. (West) Tundla, is justified ? If so, what relief the workman concerned is entitled to ?

2. The concerned workman Ram Prakash has raised this Industrial Dispute regarding his reinstatement with back wages from 24-9-87 against the opposite party Northern Railway. After filing claim statement the concerned workman consistently absented himself that shows that he is no more interested in the case.

3. Hence the reference is answered against the concerned workman for want of proof. It is further held that the concerned workman is not entitled any relief.

Dated : 25-4-1996

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का.आ. 1545—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नार्थ ईस्टर्न रेलवे के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1/5/96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41011/26/92-आईआरबीआई]
पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1545.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Eastern Railway and their workman, which was received by the Central Government on 1-5-1996.

[No. L-41011/26/92-IR (B-I)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 69 of 1993

In the matter of dispute :

BETWEEN

General Secretary,
Purvottar Railway Shramik Sangh,
6-Naveen Market,
Keshar Bagh,
Lucknow-226001.

AND

D.S.T.E. (Const),
North Eastern Railway,
Ashok Marg,
Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-41011/26/92-I.R. (DU) dated 26-8-93, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the demand of the Union (Purvottar Railway Shramik Sangh) to reinstate Shri Jai Kishan, S/o Shri Ram Dularey, Ex-Khalasi under S.I. (C), Aishbag, Lucknow w.e.f. 6-3-89 with full back wages is justified ? If not, what relief the workman concerned is entitled to while his juniors were retained ?

2. It is not necessary to give facts of the case, as after exchange of pleadings the concerned workman failed to put in appearance. It appears that he is no longer interested in the case.

3. Hence my answer for the reference is against the workman for want of proof. The concerned workman is not entitled for any relief.

Dated : 24-4-1996

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का.आ. 1546.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1/5/96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-12012/221/86-आईआरबीआई]
पी.जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1546.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SBI and their workman, which was received by the Central Government on 1-5-1996.

[No. L-12012/221/86-IR (B-I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 38 of 1987

In the matter of dispute :

BETWEEN

Sri Govind Prasad Agarwal
C/o Sri G. K. Pandey
121 Alopi Bagh
Allahabad.

AND

Chief Regional Manager
State Bank of India
Regional Office
The Mall
Kanpur.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/221/86-D. II) dated 16-4-87 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of State Bank of India in relation to their Allahabad Main Branch in discharging from service Sri Govind Prasad Agarwal Money Tester w.e.f. 6-12-66 is fair, justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?

2. The concerned workman Govind Prasad Agarwal, was appointed as Money Tester with the opposite party State Bank of India at its Allahabad Main Branch on 11-6-59. He was confirmed on this post on 11-12-59. He was appointed by erstwhile Deputy Secretary and Treasurer of the Bank. In January, 1965, a remmittence of non issuable notes worth Rs. 7,95,12000 was entrusted to the concerned workman for being carried to Reserve Bank of India, at Kanpur. The concerned workman alongwith P. C. Jain had carried this remittence to Reserve Bank of India at Kanpur. During the course of counting a shortage of Rs. 1500 was detected. On the basis of this the concerned workman was served with the chargesheet on 14-10-65 which goes as under—

(i) During the course of examination of a remittance of non issuable notes worth Rs. 7,95,12000 sent to the Reserve Bank of India, Kanpur, in January 1964, which was packed in your presence and was accompanied by you, it was found that you had surreptitiously removed 10 notes each from 15 packets of ten rupee notes contained in 5 different bundles, thereby embezzling a sum of Rs. 1500 from the remittance.

(ii) In order to avoid detection of the crime, the slips on the above packets as also on 19 other packets were deliberately left unsigned by you, thus you committed an act of most deterimental to the bank's intersts.

(iii) You intentionally forged the signatures of Sri S. L. Gupta, Cashier on 8 slips on the packets contaning ten rupee notes, which throws serious doubts on your integrity and bonafides.

(iv) To coverup your forgery, you also made another illegible signatures on eight slips on the packets containing ten rupee notes; this further stregthens mis givings that your integrity is not above board.

Ultimately one S. D. Ganda an officer of the Bank was appointed as enquiry officer. During the course of enquiry reliance was placed on the joint report of Hand Writing report of Gokul Prasad, A. N. Majoomdad and E. P. David. Further some colleagues of the concerned workman had also given in writing that they would not like to work with the concerned workman because of his dubious role. Mainly on the basis of these two factors and also the enquiry officer by comparing the two writings came to the conclusion that charges 1 and 2 were not proved were as 3rd and 4th charges were proved. This report was submitted on 12-5-66. On the basis of this report a show cause notice was given on 23-8-66 and discharge order was passed on 6-12-66. Appeal too was dismissed on 10-10-1967. Thereafter the concerned workman filed civil suit No. 43 of 1969 in the court of Civil Judge, Allahabad, which was dismissed by judgment and decree dated 26-8-69. First civil appeal No. 319 of 1969 filed by the concerned workman met similar fate vide judgment and order dated 20-4-71. The concerned workman preferred second civil appeal No. 1534 of 1972 which was dismissed by Hon'ble High Court. The concerned workman tried his luck before Hon'ble Supreme Court as well but his Special Leave Petition was also dismissed. It may be mentioned that the concerned workman was non suited in the civil litigation as his case was covered by the various provisions of Industrial Disputes Act and this was accepted under Section 9 CPC. Having failed before Civil Court, the concerned workman has raised instant industrial dispute.

3. In his claim statement the concerned workman has denied his complicity. The fairness and proprietory of domestic enquiry was also raised. It was also alleged that the dismissal order was bad in law inasmuch as the appointing authority has not passed this order.

4. Management has filed written statement in which it has been held that reference is highly belated. Once the concerned workman had withdrawn his application from the office of ALC consequently second application could not be maintained. In this way reference on such claim is bad in law. It was further alleged that enquiry was fairly and properly held.

5. In support of his case, the concerned workman has filed his affidavit, whereas management bank had filed the affidavit of one S. P. Srivastava. Before the domestic enquiry could be decided, the authorised representative of the bank on 31-3-92 conceaded that enquiry report was vitiated and request was made to prove the charges on merits.

6. In para 22 of the written statement, the bank has specifically alleged that they would like to prove only charges 3 and 4. Impliedly it would mean that first and second charges were not pressed.

7. Before taking up the main charge it will be convinient to deal with legal objections.

8. In the first place it was alleged on behalf of the management that reference is highly belated. No doubt reference is belated but there is satisfactory explanation for the same. While narrating the facts of the case it has been revaled that right from the time of his dismissal the concerned workman had been agitating the matter before civil court and High Court. In other words he was not sleeping over the matter. If delay was caused, it was because of ill advise of the layer. That should not stand in the way of rejecting the reference on this ground. Further there is no period for making reference under Section 10 of I. D. Act. At the most relevancy of belated reference will be considered when the question of granting of relief arises. Hence, on this ground alone the reference cannot be rejected.

9. It was also alleged that the concerned workman had also moved an application before ALC which was lateron withdrawn. He made another application on the basis of which reference has been made. In my opinion, this all will also not render the reference bad in any manner. Further this Tribunal is not supposed to look the circumstances under which reference has been made.

10. The authorised representative of the concerned workman has further alleged that appointing authority had not passed the dismissal order. In this regard, there is no satisfactory explanation to show as to who was the appointing authority and who was the punishing authority at the relevant time. In its absence this point cannot be adjudicated and has to be answered against the workman.

11. Now it will be seen as to how far the management has proved the charge No. 3. As has been noted earlier this charge relates to forgery of signatures of S. L. Gupta on the various bundles of notes. Once again the management has relied upon the report of Hand Writing Expert Madan Mohan Kakkar dated 10-10-92. Further the evidence of B. B. Singh an officer of the bank has also been adduced who in general term has tried to prove all the contents of pleadings including the enquiry report. In rebuttal there is evidence of Hand Writing Expert Radha Krishna Gupta dated 26-5-93 and evidence of the concerned workman. The main evidence of the management against the concerned workman in this regard is the report of Hand Writing Expert Madan Mohan Kakkar dated 10-10-92. In support of this report the management has also referred to a number of rulings viz.—

1. Murari Lal versus State of M.P. A.I.R. 1980 (SC) 531.

2. Ram Prasad versus Shyam Lal A.I.R. 1984 NOC 77 (Alld).

3. Fakhruddin versus State of M.P. AIR 1967 (S) 1326.

in which it has been held that in certain cases even the solitary report of Hand Writing Expert can be acted upon for proving the case. However it should be borne in mind that such enquiry report should have been prepared in accordance with rules. The basic requirement for acceptance of Hand Writing is that the Hand Writing Expert either himself or under his supervision should take the photographs of the original disputed writing and compare the same with the photograph of admitted specimen writing which too should be taken in his supervision. In the

instant case, the original disputed writing of S. L. Gupta has not been brought on record. When I inquired from the authorised representative about whereabout of disputed handwriting of S. L. Gupta he informed that the same is not traceable. However he added that the some was presented before the first finger print hand writing expert Gokul Prasad etc., when the opinion has been sought for the first time. Be that as it may, the hard fact remains that the report of Madan Mohan Kakkar is not based on the comparision of photograph of the original disputed writing. Thus the very foundation for acceptance of a valid hand writing report is wanting in this regard. It was grave matter in which the management ought not to have allowed the original disputed writing of S. L. Gupta caused to be disappeared. The other factor on which the management has relied about the refusal of the colleagues of the concerned workman to work with the concerned workman. In my opinion, it is hardly an adverse circumstances. It may be due to party fraction in the Union.

12. The authorised representative has also sought indulgence of this Tribunal to compare the disputed writing of S. L. Gupta with that of admitted writing of S. L. Gupta. I am unable to do so as the original of writing of S. L. Gupta has not been produced before the court.

13. The evidence of B. B. Singh, an officer of the bank is of no relevance at all. He claims to do pairvi in the case he had no personal knowledge about the facts of the case. Whatever he had stated was based on record. In my opinion, the management has not conducted properly in proving the charge against the concerned workman. In the first place it was necessary to have recorded the statement of S. L. Gupta to ascertain as to whether the disputed writing is his or not. Only when he had denied this could have been said to be a disputed handwriting. It was pointed out that S. L. Gupta is no more in service. It is immaterial. Had his evidence been recorded at the earliest in this regard, that could have been read under section 32 of Evidence Act in the present proceedings as well. Thus in the absence of statement of S. L. Gupta, I have no reason to disbelieve the unrebutted statement of concerned workman Gokul Prasad that he had not forged the signatures of S. L. Gupta, on the various bundles. I am further of the view that the concerned workman had no opportunity to do so. It is admitted case of the opposite party management that remittance was prepared in bundles which was put in trunk and the same was handed over in the joint custody of concerned workman and his colleague P. C. Jain the other money tester. It is expected that during the course of transit from Allahabad to Kanpur these trunks containing the bundles of currency notes were in joint custody of concerned workman and P. C. Jain. If at any stage the concerned workman had retained his exclusive custody over the trunk containing bundles of notes. P. C. Jain could have thrown light on it. But surprisingly his evidence was never recorded. Even his acceptance was also not obtained. Had it been done it would have cleared the myth. In the absence of evidence of P. C. Jain, I once again rely upon the statement of the concerned workman that till the trunk was handed over in the Reserve Bank, he had not tempered with it. This shows that writing of S. L. Gupta, if at all was forged before the trunks was handed over in the joint custody of concerned workman and P. C. Jain. There is another aspect of the case. It is matter of common experience that if a person commits some wrong or misconduct he does so for some motive or gain. The management has conceaded that they do not press the claim of Rs. 1500 for misappropriation against the concerned workman which is charge No. 2. That shows that there was no evil intention in the mind of the concerned workman for misappropriation of Rs. 1500. When there was no such intention there could be no occassion for him to commit this forgenry. This taking into consideration all these factors, I am of the opinion, that the case of the management against the concerned workman is not proved at all. Instead their case is based on surmises. In this way it is held that charge No. 3 as mentioned above is not proved.

14. Enquiry Officer in his report has alleged that there was no evidence on charge No. 4. He has found that this charge is proved on the ground that charge No. 3 was proved. Before this Tribunal too there is no evidence worth the name to prove charge No. 4.

15. Hence this charge also is rendered not proved.

16. From the above discussions, it follows that the management has not proved charges Nos. 1 and 2 whereas charge nos. 3 and 4 have been found to be not proved As such punishment based on these charges is unwarranted and illegal.

17. Consequently the concerned workman is entiled for reinstatement. However, I am not inclined to grant him back wages from the date of termination till the date of reference, because he himself is responsible for delay in claiming reference by unnecessarily litigating in a court of law which had no jurisdiction. Consequently, my award is that the concerned workman will be entitled for reinstatement in service with continuity of service for purposes pension and gratuity and allied benefits. Further he will be entitled for back wages at the rate at which he was drawing salary at the time of discharge from service.

18. Reference is answered accordingly.

Dated : 29-3-1996

P. J. MICHEAL, DeskOfficer

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का.आ. 1547.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.बी.बी.जे. के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1/5/96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-12012/47/86-आई आर बी आई]
पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1547.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.B.B.J. and their workman, which was received by the Central Government on 1-5-1996.

[No. L-12012/47/86-IR (B-I)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR KANPUR

Industrial Dispute No. 121 of 1986

In the matter of dispute :

BETWEEN

Sri S. K. Shukla,

C/o. the 26/104 Birhana Road,
Kanpur.

AND

The Manager,
State Bank of Bikaner and Jaipur
Gita Nagar, Kanpur.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-12012/47/86-D.II (A) dated 2-11-1986 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

> Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur Gita Nagar Branch Kanpur in terminating the service of Sri Shyam Kishore Shukla w.e.f. 17-2-1985 is justsfied ? If not, to what relief the concerned workman is entitled ?

2. The concerned workman Shyam Kishore Shukla has alleged that he was appointed as a peon for a period of 80 days from 29-11-1984 to 16-2-1985 in the Gita Nagar Branch of opposite part State Bank of Bikaner and Jaipur at Kanpur on a regular seat. At the time of his termination he was not the junior most. He had acquired temporary status not principle of last come first go was not observed. For her new hands were recruited but he was not given option in this way he is entitled for reinstatement in service with full back wages, as his services were wrongly terminattd.

3. The opposite party has filed reply in which it is alleged that the appointment of concerned workman was for a fixed period which came to an end by efflux of time. Hence, it is not covered by the definition of retrenchment as laid down in exception (oo) of Section 2(bb) of I. D. Act. The concerned workman was appointed because of administrative exigencies as by that time regular recruited peons wer not available. In any case it is alleged that provisions of Section 25-G and 25-H of I. D. Act applicable to the case of the concerned workman as he has not completed 240 days of continuous service.

4. In his rejoinder the concerned workman has rebutted facts given in the claim statement and has denied the new factual pleas raised in the written statement.

5. From the pleadings of the parties it becomes common ground that the concerned workman was appointed for 80 days i.e. for a fixed period between 29-11-84 to 16-2-85. The authorised representative of the bank has alleged that when services come to an end by efflux of time it is not a case of retrenchment. This contentions stands replied by the case decided by Hon'ble Supreme Court in the case of Management of State Bank of Bikaner and Jaipur versus Their worker C.A. No. 7029 of 1994 decided on 8-2-96. In this case it has been expressely held that such as case will not be covered by the provisions of Section 2(bb) (oo) of I. D. Act. In this case it was further held that such a workman holds the status of temporary employee. Consequently he was entitled for benefit of 14 months notice pay as laid down in para 523 and 524 of Sashtri Award Hence as said earlier the contention of the auth. representative in this regard is over ruled.

6. Obviously as the concerned workman had not continuously for 240 days he will not be entitled for benefit of Section 25-F of I. D. Act. Hence he was not entitled for notice pay and retrenchment compensation under this provision.

7. In the case of management of State Bank of Bikaner and Jaipur versus their workmen (supra) it was further held that a peon was entitled for benefit of Section 25-G as well. In this regard there has been affidavit of concerned workman in which he has specifically sworn that junior to him like Prem Singh, Sri Kant and Awadhesh Kumar were retained in service. There is not a word of cross examination in this regard. Further B. K. Lahri Manager Industrial Relation who had filed his affidavit on 7-12-87 has also not rebutted it Apart from this witness was not submitted for cross examination. In this way the case of the concerned workman in this regard remains unrebutted. Hence it is accepted that junior persons named above were retained in service when the services of the concerned workman came to an end. As such there has been breach of Section 25-G of I. D. Act which vitiated the termination order.

8. There is once again no rebuttal of the concerned workman that Tej Bahadur, Gyan Singh, P. N. Dixit and S. K. Tiwari were subsequently reemployed but the concerned workman was not given opportunity. As this evidence is unrebutted, I accept it. In the case of management of State Bank of Bikaner and Jaipur versus Their workmen (supra) it was once again held that since there are no opportunity for recruitment for peons they will be entitled for benefit of Section 25-H of I. D. Act as well.

9. In view of my findings that new hands were employed after the end of service of the concerned workman and the concerned workman was not afforded opportunity there has been breach of Section 25-H of I. D. Act.

10. The authorised representative of the opposite party bank has drawn my attention to the affidavit of Subramaniam an officer of the bank dated 22-4-88 to show that subsequently all the retrenched employees were called for test and interview, the concerned workman had failed to appear, hence the concerned workman is not entitled for any relief.

11. Once again reference may be made to the case of State Bank of Bikaner and Jaipur (supra) in which it has been specifically held that affroding of such an opportunity would not be a bar in a case of peon. As it is a case of peon this holding of test will be of no consequence. Had it been the case of clerk, the position would have been different.

12. In the end my award is that termination of the concerned workman by order dated 17-2-85 is not justified and as such the concerned workman will be entitled for reinstatement but without back wages.

13. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 7 मई, 1996

का.आ. 1548.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-12012/40/92-आईआर (बी-II)]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1996

S.O. 1548.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Cental Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 6-5-1996.

[No. L-12012/40/92 IR (B-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 77 of 1992

In the matter of dispute between

Vice President

PNB Employees Union

U. P. Kishanpur Rajpur Dehradun

And

Regional Manager
Punjab National Bank
S-20|56-D Canedy Road
The Mall Varanasi

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-12012|40|92 I.R. B-2 dt. 24-6-92 as referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of Regional Manager of Punjab National Bank, Varanasi in awarding punishment of stoppage of one annual graded increment for a period of one year of Sh. S K Chaturvedi, Clerk|Typist, Bulanala Varanasi Branchvide his rder dt. 26-5-88 is just and legal ? If not, to what relief is the workman entitled.

2. The concerned workman S K Chaturvedi is working as clerk cum typist in the branch at Ballia of the opp. party Punjab National Bank. On 15-7-86 he was served with a chargesheet on three counts. In the first place he was faulted for not having despatched the drafts of the customers next day thereby causing loss to the goodwill of the bank. The second charge was regarding his failure to prepare daily extract from 17-10-85 to 18-2-86 the details of which have been given in the chargesheet. The third charge was relating to illegal realization of Rs. 5|- per day as conveyance charge. R C Pandey, Manager of branch office Bisheshwarganj was appointed as E.O. After completing the enquiry he submitted his report dt. nil holding that charge no. 3 was proved while 1 and 2 not proved. On the basis of this punishing authority imposed punishment of stoppage of one increment by order dt. 26-5-88. Appeal was also dismissed. Feeling aggrieved the concerned workman has raised the instant industrial dispute.

3. In the claim statement the validity of enquiry has been challenged, further he has also denied that he was guilty of any misconduct as alleged in the charge sheet. These charges were trumped up because of his active association with the union.

4. The opposite party has filed reply dening the allegations of the concerned workman.

5. After exchange of pleadings the concerned workman failed to put in appearance. He also did not adduce any evidence whereas the management has examined E.O. R C Pandey who has proved the enquiry proceedings and report. He has also stated that no illegality or irregularity was committed in holding enquiry. In the absence of any evidence I have no hesitation in holding that finding against the concerned workman was properly held. Consequently the punishment imposed upon the concerned workman was also justified. In this way the concerned workman is not entitled for any relief.

6. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 7 मई, 1996

का.आ. 1549.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-5-1996 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-12012/403/87-डी-IIए/आईआर(बी-II)]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1996

S.O. 1549.—In pursuance of Section 17 of the Indusrtial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 6-5-1996.

[No. L-12012/403/87-D.IIA|IR(B-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 32 of 1988

In the matter of dispute between :

Sri Mohammad Ahmad Siddiqui,

C/o V. N. Sekhari,
26/104, Birhana Road.
Kanpur.

AND

Manager (Personnel),
Union Bank of India.
Hotel Clarks Awadh,
Mahatama Gandhi Marg,
Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification no. L-12012/403/87-D-2(A) dated nil has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

"Kya Union Bank of India ke prabandhtantra ki Sri Mohib Ahmad Siddiqui ki 17-7-78 se sewayei samapta karne aur audyogik vivad adhiniyam ki karwai nyayochit hai Yadi nahi to karmkar his kichare 25-ja ke adhin nai bharti karte samaya age rojgar ke liye uske nam par vichar na karne ki karwai nyoyochit hai Yadi nahi nahi to karmkar kis anuthosh ka haqdar hai ?"

2. In the claim statement the concerned workman Mohib Ahmad Siddiqui has alleged that according to various provisions of Desai, Shastri Award and bipartite settlement there are 4 varieties of services viz, (1) permanent (2) temporary (3) probationer and (4) part time. It would mean that management of the bank has no right to create a new type of service. Still by adopting unfair labour practice the opposite party Union Bank of India had appointed the concerned workman as peon at Station Road Branch of Banda and allowed him to work from 15-5-78 to 13-7-78. It is further alleged that his appointment was made after due selection by holding interview. A select list of 23 persons was prepared. Later on his name was scored out from this list, and his services were dispensed with. This order of termination is bad in law because of breach of sections 25G, 25H of I.D. Act and paras 493, 495, 507, 516, 519, 524 of Shastri Award and para 20.7 and 20.8 of first Bipartite Settlement.

3. The opposite party has filed written statement. It is not disputed that the concerned workman had worked for the period between 15th May, 1978 to 12th July, 1978 It is alleged that he had actually worked for 30 days in broken span of 5 to 8 days. It is specifically denied that he was selected on the basis of any interview. No penal of 23 persons was prepared at all. As the concerned workman was a casual worker he did not acquire any status and there was no need for compliance of any provision of Industrial Disputes Act or award or Bipartite Settlement. In the end it was alleged that the concerned workman was appointed for short and limited period for less than two months and his appointment came to an end by efflux of time. As such it is not a case of retrenchment at all.

4. The concerned workman has filed rejoinder in which the factual pleas raised in the written statement has been denied.

5. The first point which needs consideration is as to whether the concerned workman was appointed temporarily after a test or for a fixed period. In this regard there is affidavit of concerned workman Mohib Ahmed Siddiqui in which he has specifically alleged that he has been appointed after his test was taken. In support of this averment there is also a copy of letter dated 24th January, 1978 issued to the concerned workman by the opposite party informing that personal interview will be held on 3rd March, 1978. That shows that he was called for interview.

6. There is also copy of letter dated 27th January, 1979 issued by A. H. Kidwai an officer of the bank informing the applicant that a select list was prepared in which his name figures. In rebuttal there is evidence of Shanker Lal, Branch Manager, in which he has deposed that the concerned workman was casual worker and was paid wages through vouchers. Admittedly he has no personal knowledge and has deposed on the basis of record, but that record has not been filed in the Tribunal. Only five payment vouchers M-1 to M-5 have been filed for the months of 27th May, 1978 to 12th July, 1978.

7. From his evidence it is evident that there is a file of the concerned workman in the office, but the same has not been produced before this Tribunal. Had this file been produced it would have been revealed the clear picture. As the opposite party has withheld relevant papers. I am inclined to believe the evidence of the concerned workman which is supported by interview letter and other papers. Simply payments by cash vouchers would not render the appointment as casual. Further in the absence of these papers, I am not inclined to believe that the appointment was not for a fixed period.

8. In the end because of the above reasons, I accept the versions of the concerned workman and hold that he had worked for the period as alleged and his appointment was not for a fixed period. In the case of Management of State Bank of Bikaner & Jaipur versus Their workmen, Civil Appeal No. 7029 of 1994, decided on 8th February, 1996, Hon'ble Supreme Court has held that appointment like that of the instant concerned workman is temporary one. Therefore, it is held that the concerned workman has held a temporary post.

9. There is no dispute that the services of the concerned workmen were dispensed with. In other words it is a case of retrenchment.

10. It will be seen if there has been breach of Section 25G of I.D. Act. Although in the claim statement it has been alleged that junior to the workman has been retained in service but their details have not been given. Instead names of those persons have been given and have been impleaded subsequently. Hence for want of pleadings and proof it is held that there has been no breach of Section 25-G of I.D Act.

11. Now it will be seen if there has been breach of Section 25H of I.D. Act. A controversy has been raised as to whether non compliance of Section 25H would render the retrenchment invalid. That matter has now been set at rest. Once again reference may be made to the case of State Bank of Bikaner & Jaipur versus Their workmen (supra). In this case the dispute related to clerks, peon and watchmen who had held office for a fixed period. Their services came to an end by efflux of time. They had raised industrial dispute in which the matter was decided in favour of the concerned workman. The management took the matter before the Hon'ble High Court. The case was once again decided against the management. Thereafter, the S.L.P was filed in which this judgement was rendered after hearing both sides. In the first place in this judgment it was held that persons who are appointed for a fixed period and whose services come to an end by efflux of time would still attain the status of temporary employee and their case would not be covered by sub clause 2(bb) (oo) of I. D. Act. It was further held that since it was a case of retrenchment these employees were entitled for protection of section 25G & H of I.D. Act. It was further held that balance were afforded opportunity for appearing in regular selection according to Rules as they have either failed to take opportunity or were not successful. They would not be entitled for any benefit of section 25H of I. D. Act. Benefit of sec. 25G was not extended as the case was not proved. However, it was specifically held that peons were entitled for protection of section 25H of I.D. Act. It was further held that even if is held that the management had right to effect retrenchment because of paras 523 and 524 of Sastri Award, they were entitled for one and half month's pay.

12. Thus from the above principle laid down by Hon'ble Supreme Court, the concerned workman having worked as peon was entitled for protection of sec. 25H of I. D. Act. There is unrebutted statement of concerned workman that after his termination one Ram Narain Sahu and Banshi Lal were appointed. Hence the concerned workman ought to have been given a chance. By not giving such chance there has been breach of section 25H of I.D. Act. Accordingly, the termination is bad in law.

13. Still I would not grant the relief of reinstatement or back wages because the reference is highly belated. Termination took place on 13-7-78, whereas reference was made on 18-3-88. There is no explanation as to why this reference has been claimed so late. In the absence of any explanation and taking that reference is highly stale, in view of case 1996 Lab IC page, the concerned workman will not be entitled for the relief of reinstatement and back wages. Instead ends of justice will be met by awarding him Rs. 10,000|- by way of compensation in lieu of reinstatement.

14. In the end my award is that termination of the concerned workman w.e.f. 14-7-78 is bad and the management was not justified in not giving fresh chance to the concerned workman under sec. 25H of I.D. Act. Still as the claim is stale and for which there is no explanation I order that in the absence of reinstatement the concerned workman will be entitled for Rs. 10,000|- as compensation in lieu of reinstatement.

15. Reference is answered accordingly.

16-4-96

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मई, 1996

का.आ. 1550.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान कमर्सियल बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6/5/96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल 12012/447/87-डी-IIए/आईआर(बी-II)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1996

S.O. 1550.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, KANPUR as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of HINDUSTAN COMMERCIAL BANK LTD. (NOW PUNJAB NATIONAL BANK) and their workmen, which was received by the Central Government on 6-5-96.

[No. L-12012|447|87 DIIA|IR(B-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR KANPUR

Industrial Dispute No. 48 of 1988

In the matter of dispute :

BETWEEN

P. K. Maurya & Bhola Nath
C/o V N Sekhari
26/104 Birhana Road
Kanpur.

And

Regional Manager
Punjab National Bank
10 Ashok Marg, Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-12012/447/87-D.II(A) dt. 8-4-88 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Hindustan Commercial Bank Limited now amalgamated with Punjab National Bank in terminating the services of S/S P. K. Maurya and Bhola Nath and not considering them for further employment while recruiting fresh hands under sec. 25H of the Industrial Dispute Act is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

2. At the outset it may be mentioned that the case of the two persons namely, Pradip Kumar Maurya and Bhola Nath has been referred. After the receipt of reference Sri V N Sekhari authorised representative of Bhola Nath informed the Tribunal that reference against this workman is not pressed. Hence, there is neither any pleading nor any proof in respect of his claim. Accordingly reference as far as this workman is concerned has to be answered against him.

3. In his claim statement the other workman Pradip Kumar Maurya has alleged that he was employed as a peon at the rate of Rs. 8/- per day from 2-4-79 to 11-7-79 on a regular post by the erstwhile Hindustan Commercial Bank Limited at Lucknow. Later on 12-7-79, he was retrenched. However, he was given fresh chance w.e.f. 8-7-81 upto 28-7-81. Any way he has challenged his retrenchment w.e.f. 12-7-79 on the ground that there has been breach of section 25G and 25H of I.D. Act. Besides there is reference to a number of paragraph of Sastri Award and Bipartite Settlement, the contents of which are analogous to the above provisions of Industrial Disputes Act. It is further added that this bank was later on amalgamated with the opposite party M/s. Punjab National Bank by order dt. 18-12-86. Hence, relief has been claimed against opposite party Punjab National Bank.

4. The opposite party has filed reply in which it has been denied that the concerned workman was ever employed during the period 2-4-79 to 4-7-79 with the Hindustan Commercial Bank Limited. Of course it is alleged that the concerned workman had worked between 8-7-81 to 28-7-81 but that too on a casual post for the job unconnected with the bank activities.

5. In the rejoinder the concerned workman has reiterated the facts alleged in the claim statement and has denied new factual pleas raised in the written statement.

6. It may be mentioned that the case lingered on because of challenge to the authority of Sri V. N. Sekhari the represent the case of workman.

7. In support of his claim the concerned workman Pradip Kumar Maurya has filed his affidavit. In his cross-examination he has stated that no appointment letter was given to him. Rajendra Tiwari was an officiating manager at the material time in the erstwhile Hindustan Commercial Bank. He has stated that at the material time, the concerned workman was not in the employment of the erstwhile bank at all. Instead he had worked between 8-7-81 to 28-7-81 in respect of which cash vouchers have also been filed. In respect of above none of the parties have filed any other paper.

8. The first point which needs consideration is as to whether the concerned workman had actually worked from 2-4-79 to 11-7-79. In my opinion, the above mentioned bald statement of P. K. Maurya in support of his claim is not enough specially when Rajendra Tiwari has rebutted by filing cash vouchers as well. Hence I am not inclined to accept the version of the concerned workman. Accordingly it is held that the concerned workman had not worked at all between 2-4-79 to 11-7-79. Hence question of his retrenchment w.e.f. 12-7-79 does not arise which is the basis of cause of action of this reference. Once it is held that the concerned workman had never been retrenched at all on 12-7-79, question of its justification or terminating the services does not arise. Further he has got no right whatsoever under sec. 25H of I.D. Act. Consequently the opposite party was not obliged to consider the case of the concerned workman under section 25H of I.D. Act. As such he is not entitled for any relief. I award accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मई, 1996

का.आ. 1551.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वित्तीय केन्टीन के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-4-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल 42012/15/88-डी-2बी]

के.वी.बी. उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1996

S.O. 1551.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Tribunal between the employers in relation to the management of Deptt. Canteen and their workman, which was received by the Central Government on 2-8-96.

[No. L-42012/15/88-D.2B]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 29/89

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. एल.-42012/15/88-II-बी दिनांक 17-2-89

श्री कृष्ण कुमार सक्सेना पुत्र श्री द्वारका प्रसाद सक्सैना, कल्याण जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर ।

—प्रार्थी

बनाम

सचिव, महालेखाकार, कार्यालय वित्तीय जलपान गृह प्रबंध समिति ।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के.एल. व्यास, आर.एच.जे.एस

श्री जे. एल. शाह प्रार्थी की ओर से

श्री डी.एन. शर्मा अप्रार्थी की ओर से

दिनांक अवार्ड 26-9-95

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा निम्न विवाद अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है :

"क्या सचिव, विभागीय कैन्टीन, महालेखाकार कार्यालय जयपुर के प्रबन्धतंत्र की श्रमिक श्री कृष्ण कुमार सेक्सेना की सेवाएं 2-1-84 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस राहत/अनुतोष का हकदार है ? "

2. श्रमिक ने जिन तथ्यों पर क्लेम आधारित किया है वे सारांश में इस प्रकार हैं कि उसने विपक्षी संस्थान में बेयरर के रुप में 15-6-82 को अपनी ड्यूटी जोइन की थी वे उसके पश्चात समय समय पर उसकी सेवा अवधि बढ़ाई गई तथा 1-8-83 के आदेश से उसे 6 माह की परिवीक्षा पर बेयरर के पद पर नियुक्त किया गया तथा यह अवधि समाप्त होने से पूर्व 2-1-84 को उसकी सेवाएं अवैध रूप से पत्र क्रमांक 58 के जरिये समाप्त की गई । इस प्रकार श्रमिक का कथन है कि उसने नियोजक के यहां लगातार 240 दिन से अधिक कार्य किया था वे उसकी सेवाएं धारा 25-एफ के प्रावधान की पालना के बिना समाप्त की गई है इसलिये नियोजक की यह कार्यवाही अवैधानिक व अनुचित है । अनुतोष यहां मांगा गया है कि श्रमिक को सम्पूर्ण बकाया वेतन के लाभ सहित निरन्तर सेवा में मानते हुए पुनः बहाली का आदेश दिया जावे ।

3. नियोजक के अपने जवाब में प्रारंभिक आपतियों यह ली हैं कि महालेखाकार जयपुर के कार्यालय में संलग्न कैन्टीन में श्रमिक को बेयरर के पद पर नियुक्त किया गया था तथा उसका पद सिविल पदों को धारित करने वाले कर्मचारी के रूप में था व केन्द्रीय सरकार के सेवा नियमों में उसकी नियुक्ति को शर्तें प्रभावित थी इसलिए श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम (जिसे बाद में अधिनियम संशोधित किया जायेगा) के तहत कामगार की परिभाषा में नहीं आता है । यह भी अभिकथित किया गया है कि जिस कैन्टीन में श्रमिक को नियुक्त किया गया था वह संस्थान उद्योग की परिभाषा में भी नहीं आता है । इसके अलावा गुण दोष पर यह बताया गया है कि श्रमिक की प्रथम नियुक्ति 15-6-82 को कैन्टीन में नहीं की गई थी बल्कि 1-8-83 से ही उसे परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था । परिवीक्षा अवधि में श्रमिक का कार्य संतोषजनक नहीं था इसलिए जलपानगृह कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा) नियम 1980 के नियम 8 (4) के तहत श्रमिक की सेवाएं समाप्त की गई थी वह तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को देखते हुए नियोजक को यह कार्यवाही अधिनियम के तहत छंटनी की परिभाषा में नहीं आती है इसलिए धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधान मामले में लागू नहीं होते हैं । सेवा मुक्ति से पूर्व श्रमिक को कोई भी नोटिस या मुआवजा देने के तथ्य को अस्वीकार किया गया है । श्रमिक द्वारा 240 दिन से कम अवधि में कार्य करना भी तथ्यात्मक रूप से जवाब में अभिकथित किया गया है । उपलब्ध प्रतिरक्षाओं के आधार पर यह अनुरोध किया गया है कि श्रमिक का क्लेम खारिज किया जावे ।

4. मौखिक साक्ष्य के रूप में श्रमिक ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है वे नियोजक की ओर से एक गवाह श्री रतनपाल सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । दोनों की ओर से कुछ प्रलेख भी प्रस्तुत किये गये हैं । उपलब्ध मौखिक व प्रालेखिया साक्ष्य तथा संबंधित विधिक प्रावधान की दृष्टि से दोनों पक्षों की बहस सुनी गई ।

5. सर्वप्रथम नियोजक की ओर से ली गई इस आपति पर विचार किया जाता है कि संबंधित कैन्टीन उद्योग की परिभाषा में नहीं आती है इसलिए न तो श्रमिक अधिनियम के तहत कामगार है व न ही अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। श्रमिक को परवीक्षा अवधि में भी नियुक्ति आदेश दिया गया था उसकी प्रतिलिपि प्रदर्श डब्ल्यू-1 श्रमिक की ओर से प्रस्तुत की गई है जिस पर नियोजक पक्ष को कोई भी विवाद नहीं है । यह नियुक्ति आदेश सहायक सचिव व्यवस्थापक विभागीय जलपानगृह कार्यालय महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किया गया है । शपथ पत्र के पद सं. 9 में यह बताया गया है कि इस कैन्टीन में चाय कॉफी, नाश्ता व भोजन आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा ये सुविधाएं ए.जी. कार्यालय के कर्मचारियों व बाहर के व्यक्तियों को भुगतान पर उपलब्ध कराई जाती हैं । जिरह में उसने बताया हैं कि नियुक्ति आदेश उसे कैन्टीन के सचिव द्वारा दिया गया था, वे ही उसके कार्य का सुपरवीजन करते थे व यह भी स्वीकार किया गया है कि नियुक्ति के संबंध में जलपानगृह कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा) नियम 1980 लागू होते थे । नियोजक की ओर से जो गवाह आर.पी. सिंह प्रस्तुत हुए हैं उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की कैन्टीन में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में केन्द्रीय सरकार के गजैट नोटिफीकेशन में प्रसारित नियम लागू होते हैं व उनके तहत ये कर्मचारी सिविल पदों को धारित कर सकते हैं तथा उनके सेवा नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाये गये हैं । उनका यह भी कथन है कि श्रमिक कृष्ण कुमार सक्सैना की नियुक्ति उन्हीं नियमों के तहत की गई थी व उनकी सेवा के मामले में यह नियम लागू होते हैं । इसके अलावा यह बताया गया है कि गृह मंत्रालय ने अपने ज्ञापन सं. 12-1-82 के जरिये कैन्टीन में कार्यरत कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधान से अलग माना है । उक्त नियमों, राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति व केन्द्रीय सरकार के परिपत्र के संबंध में भी साक्ष्य नियोजक गवाह द्वारा दी गई है उस पर कोई भी प्रति परीक्षण की ओर से नहीं किया गया है ।

6. नियोजक के गवाह श्री आर.पी. सिंह ने शपथ पत्र में यह बताया है कि कैन्टीन में मात्र ए.जी. आफीस में कार्यरत कर्मचारियों को जलपान की सुविधा उपलब्ध

कराई जाती है तथा यह कार्य न लाभ हानि के आधार पर किया जाता है । जिरह में उन्होंने यह बताया है कि जलपान में चाय, नाश्ता व भोजन भुगतान पर सप्लाई किया जाता है व हर रोज करीब 600/– रुपये की बिक्री होती है । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि ए.जी. कार्यालय के अलावा बाहर का कोई भी व्यक्ति कूपन खरीदकर कैन्टीन में जलपान कर सकता है । इससे यह स्पष्ट है कि केंटीन की गतिविधि मात्र ए.जी. ऑफीस के कर्मचारियों में तक ही सीमित नहीं है व बाहर के व्यक्तियों को भी वाणिज्यिक स्तर पर भोजन व चाय नाश्ता सप्लाई किया जाता है । न लाभ न हानि के आधार पर कैन्टीन के संचालन के संबन्ध में कोई भी खाता वही नियोजक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है व सामान्यतः यह बात विश्वसनीय नहीं हो सकती कि कार्यालय के बाहर के व्यक्तियों से भी व्यापार उसी सिद्धान्त पर किया जाता हो । गवाह ने इस संबन्ध में भी तथ्य शपथ पत्र में उल्लिखित किये है उन पर कोई भी जिरह नहीं है । इस प्रकार दोनों पक्षों की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि जिस कैन्टीन में श्रमिक कार्यरत था वह ए.जी. कार्यालय से संलग्न थी, उस केंटीन में ए.जी. कार्यालय के कर्मचारियों के अलावा बाहर के व्यक्तियों को भी भोजन व नाश्ता भुगतान पर सप्लाई किया जाता है तथा यह बात निश्चित रूप ये प्रमाणित नहीं है कि यह कार्य न लाभ न हानि के सिद्धान्त पर किया जाता हो । यदि तर्क के लिए यह भी माना जावे कि उक्त सिद्धान्त पर केंटीन का संचालन किया जाता है तो भी जहां तक उसे उद्योग की परिभाषा में माने या नहीं माने जाने का प्रश्न है, उस पर कोई भी प्रभाव गुण दोष की दृष्टि से नहीं होता । जो गतिविधियां केंटीन की साक्ष्य में प्रमाणित हैं उनसे यह धारणा लेना न्यायोचित है कि केंटीन उद्योग की परिभाषा में आता है ।

7. नियोजक की ओर से केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति 30-1-92 व 29-1-92 भी प्रस्तुत की गई हैं उसमें यह निर्देश संबन्धित विभाग को दिये गये हैं कि अक्त प्रकार की केंटीन में कार्यरत कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन भत्ता स्वीकृत किया जाये क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका में इस प्रकार के निर्देश केन्द्रीय सरकार को दिये गये हैं तथा यह सुविधा 1-10-91 से प्रभावी बनाई गई है । इस विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख है कि उक्त सुविधाएं प्रदान करने के पश्चात् केंटीन के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार के समक्ष नियम लागू होंगे । केन्द्रीय सरकार का कोई भी प्रतिष्ठान जो उद्योग की परिभाषा में आता है उसके कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के समवा नियम व वेतनमान लागू होते हैं किन्तु मात्र इसी मापदण्ड से यह नहीं माना जा सकता कि वह संस्थान उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है । हर राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक संस्थान के कर्मचारियों के समवा नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाये जाते हैं व इन सेवा नियमों के लागू होने से उद्योग की परिभाषा तय नहीं की जा सकती । संस्थान की गतिविधि व कार्य के आधार पर ही यह विनिश्चय किया जा सकता है कि संस्थान उद्योग की परिभाषा में आता है अथवा नहीं ।

8. नियोजक की ओर से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जयपुर के एक निर्णय ओ.ए. नं. 334/87 दिनांक 19-7-94 की फोटो प्रति नियोजक की ओर से प्रस्तुत की गई है जिसमें ए.जी. कार्यालय से संलग्न रोजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से संलग्न केंटीन का इस आधार पर उद्योग नहीं माना गया है क्योंकि निर्णय के अनुसार वह केंटीन आर.सी.आई. का एक अविभाजित (इंटीग्रल) है । इस प्रकरण में अधिकरण के समक्ष किस प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत हुई थी इसका विवेचन निर्णय में नहीं किया गया है । इसके अलावा भी उद्योग की परिभाषा के संबन्ध में उपलब्ध विधि दृष्टान्तों की विस्तृत व समुचित व्याख्या इस अधिनिर्णय में नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त भी सुन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का निर्णय इस न्यायाधिकरण के लिए वैधानिक बाध्यता नहीं रखता है । यह टिप्पणी लिखने का किसी भी रूप में यह आशय नहीं है कि अधिकरण के निर्णय के प्रति न्यायाधिकरण का सम्मान नहीं है किन्तु जिन तथ्यों व परिस्थितियों में न्यायाधिकरण द्वारा केंटीन को उद्योग नहीं मानने का भी विनिश्चय किया गया है वह इस न्यायाधिकरण की राय में वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण पर लागू नहीं होता ।

9. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने उपलब्ध तथ्यों को दृष्टि से केंटीन की उद्योग की परिभाषा में मानने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बेंगलौर वाटर सप्लाई बनाम ए. राजप्पा एफ.एल.आर. 1978 (36) पेज 266 ए. सुन्दरमबल बनाम गोआ राज्य ए.आई.आर. 1988 (एस.सी. (1700 के निर्णय प्रस्तुत किये हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दोनों सुविख्यात निर्णयों में किसी भी संस्थान को उद्योग की परिभाषा में मानने के लिए जो सर्वमान्य मापदण्ड निर्धारित किये हैं उनको देखते हुए व इस प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए न्यायाधिकरण की यह निश्चित राय है कि विवादग्रस्त केंटीन उद्योग की परिभाषा में आती है । इसके अलावा श्रमिक की ओर से 1995 लैब.आई.सी. 108(एम.पी.) भारत संघ बनाम पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जबलपुर का एक निर्णय प्रस्तुत किया है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई भी कर्मचारी अधिनियम के तहत श्रमिक की परिभाषा में आता है व उसकी सेवा शर्तों के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के नियम बनाये गये हैं तो उनके आधार पर वह कर्मचारी अधिनियम के प्रावधान से अलग नहीं माना जा सकता । जिन तथ्यों पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है वह पूर्ण रूप से इस

प्रकरण के तथ्यों पर लागू होता है व इसके सम्बन्ध में पूर्व में भी विवेचना की गई है। निष्कर्ष यह है कि मामले के उपलब्ध तथ्यों व दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत विधि दृष्टान्तों को देखते हुए यह विनिश्चय किया जाता है कि जिस कैंटीन में श्रमिक को नियुक्त किया गया था वह उद्योग की परिभाषा में आती है व परिणामस्वरूप श्रमिक कामगार की परिभाषा में आता है।

10. अगला विचारणीय बिन्दु यह है कि दिनांक 2-1-84 को प्रदर्श डब्ल्यू–2 आदेश के जरिये श्रमिक को सेवा मुक्त करने से पूर्व उसने सम्बन्धित कैंटीन में 240 दिन या उससे अधिक कार्य किया था। प्रदर्श डब्ल्यू–1 श्रमिक की नियुक्ति का आदेश 1-8-83 का है जिसके अनुसार उसे परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था प्रदर्श डब्ल्यू–2 उसकी सेवा समाप्ति का आदेश है जिसको नियोजक ने स्वीकार किया है। विवाद दोनों पक्षों के बीच यह है कि नियोजक के अनुसार 1-8-83 से पूर्व श्रमिक ने केन्टीन में कोई कार्य नहीं किया था जबकि श्रमिक का कथन है कि उसने पहली बार 15-6-82 को ड्यूटी जोइन की थी व तब से उसने लगातार वहां कार्य किया था। अपने शपथ पत्र में श्रमिक ने इस तथ्य का समर्थन किया है। जिरह में उसने कहा है कि 1-8-83 से पूर्व उसे कोई नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया था। इसके अलावा कोई भी जिरह इस तथ्य पर प्रहार करने के लिए नहीं की गई है कि वह कैन्टीन में 15-6-82 से कार्यरत था। अपने कथन के समर्थन में श्रमिक ने प्रदर्श डब्ल्यू–3 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं जो 21-8-82 का है यह प्रमाण पत्र भी कैन्टीन के सहायक सचिव द्वारा जारी किया हुआ है। इस प्रमाण पत्र को नियोजक पक्ष ने गलत या संदेहपूर्ण नहीं बताया है। प्रमाण पत्र में यह उल्लेख है कि श्रमिक ने प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व कैन्टीन में करीब 6 माह कार्य किया था। नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि का यह कथन है कि इस प्रमाण पत्र से यह साबित नहीं होता कि 21-8-82 से पूर्व श्रमिक कैन्टीन में कार्यरत था जो कथन प्रमाण पत्र में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है।

11. नियोजक के गवाह श्री आर.पी. सिंह ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि श्रमिक की नियुक्ति 1-8-83 के आदेश से पहली बार की गई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि यह बयान उन्होंने रिकार्ड के आधार पर दिया है। जो जिरह इस संबंध में गवाह से की गई है उसमें उन्होंने यह बताया है कि श्रमिक के काम की उन्हें कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है क्योंकि संबंधित समय वे कैन्टीन में कार्यरत नहीं थे। उन्होंने जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 1-8-83 से पूर्व दैनिक वेतन पर श्रमिक कैन्टीन में कार्यरत था। चूंकि इस गवाह को श्रमिक के कार्य के संबंध में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है इसलिए उनका यह कथन श्रमिक के साक्ष्य की तुलना में मानने योग्य नहीं है। नियोजक का यह दायित्व था कि नकारात्मक साक्ष्य के लिए उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता जो उस समय कैन्टीन के कार्य की देखभाल करता था। इसके अलावा जिरह में श्री सिंह ने यह स्वीकार किया है कि जो भी कर्मचारी कैन्टीन में कार्य करते थे उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती थी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 1983 का हाजिरी रजिस्टर उन्होंने नहीं देखा। वर्ष 82-83 को उपस्थिति रजिस्टर नहीं मिला उनका यह भी कथन है कि उस अवधि में श्री वार्ष्णेय व हिम्मत बहादुर कैन्टीन के प्रभारी थे। प्रदर्श डब्ल्यू-3 पर श्री वार्ष्णेय के हस्ताक्षर उन्होंने स्वीकार किये हैं। उक्त दोनों गवाह में से कोई भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं हुआ है। उपस्थिति रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने के संबंध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही संबैधानिक रूप से उपस्थिति रजिस्टर के कस्टोडियन के बयान नियोजक की ओर से करवाये गये हैं। ऐसी स्थिति में यह धारणा लेना न्यायोचित है कि उपलब्ध प्रालेखीय साक्ष्य अकारण नियोजक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। नियोजक की साक्ष्य का निष्कर्ष यह है कि श्री आर. पी. सिंह को तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, सुसंगत जानकारी की कोई भी व्यक्ति साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं हुआ है, जो महत्वपूर्ण अभिलेख उपस्थिति के संबंध में उपलब्ध थे वह प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा प्रदर्श डब्ल्यू-3 प्रमाण पत्र को नियोजक पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। दोनों पक्षों की मौखिक व प्रालेखीय साक्ष्य के आधार पर यह विनिश्चय किया जाता है कि श्रमिक ने 16-6-82 से 2-1-84 तक निरन्तर नियोजक के यहां कार्य किया था व इस प्रकार यह अवधि 240 दिन से अधिक होती है। यह मान्य स्थिति है कि नियोजक द्वारा सेवा मुक्ति से पूर्व धारा 25-एफ के प्रावधान की पालना नहीं की गई। नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने इस बाबत विवाद नहीं किया है कि प्रारंभ में दैनिक मजदूरी पर व बाद में परिवीक्षा पर नियुक्ति की अवधि की धारा 25-एफ के प्रावधान के लिए संयुक्त रूप से शामिल किया जाता है। इन परिस्थितियों में श्रमिक को सेवा मुक्ति का आदेश अनुचित व प्रारंभ से ही शून्य व अवैध है।

12. श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में यह बताया है कि वह सेवा मुक्ति के पश्चात लगातार बेरोजगार है तथा प्रयास करने के बावजूद उसे दूसरा कोई भी काम उपलब्ध नहीं हो सका। जिरह में उसने स्वीकार किया है कि गत एक वर्ष से वह किसी निजी फर्म में 550/ रुपये मासिक वेतन पर नौकरी करता है। नियोजक की ओर से जवाब में यह प्रतिरक्षा ली गई है कि श्रमिक सेवा मुक्ति के पश्चात लाभकारी रूप से कहीं नियोजित है या उसकी आजीविका का अन्य कोई स्त्रोत है। नियोजक के गवाह श्री सिंह ने अपने शपथ पत्र में इस संबंध में कोई भी तथ्य वर्णित नहीं किया है। श्रमिक के शपथ पत्र पर जिरह 9-7-91 को हुई है व उसके बाद यह प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि श्रमिक बेरोजगार है इसलिए जुलाई 1991 तक श्रमिक समस्त बकाया वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है उसके पश्चात चूंकि वह नौकरी में नियोजित है इसलिए उसे नियोजक पक्ष के यहां नियमित नियोजक की स्थिति में जो वेतन व अन्य लाभ प्राप्त होते उसके व अन्य जगह नियोजक के कारण प्राप्त

होने वाले वेतन के अन्तर के रूप में उपलब्ध राशि श्रमिक नियोजक से प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है । इसके लिए संबंधित पक्षों द्वारा धारा 33 (सी) (2) अधिनियम के तहत अलग से कार्यवाही की जा सकती है ।

12. निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि श्रमिक कृष्ण कुमार सक्सैना की सेवाएं सचिव, कैन्टीन महालेखाकार कार्यालय जयपुर द्वारा 2-1-84 से समाप्त करने की कार्यवाही अनुचित व अवैधानिक है इसलिए श्रमिक सेवा की निरन्तरता कायम रखते हुए पुनः सेवा में बहाल होने का अधिकारी है । 2-1-84 से जून 1991 तक का समस्त पिछला बकाया वेतन व आय लन्भ नियमानुसार श्रमिक नियोजक से प्राप्त करने का अधिकारी है । जुलाई 1991 के पश्चात् श्रमिक को अन्यत्र नियोजन के कारण बकाया वेतन के रूप में क्या राशि नियोजक द्वारा देय होगी उसका विनिश्चय धारा 33 (सी) (2) अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये संबंधित पक्षकारों द्वारा कराया जा सकता है ।

13. अधिनिर्णय आज दिनांक 26-9-1995 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

के.एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 मई, 1996

का०आ० 1552.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार दूर संचार के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कमकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-5-91 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-40012/113/89-डी-2-बी]
के.वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1996

S.O. 1552.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Dispute Jaipur as shown in the Annaxeure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 2-5-96.

[No. L-40012/113/89-D-DB]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस न. सी.आई.टी. 43/1990

रैफरैंस : केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय,, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक एल.-40012/113/89 डी-2बी दिनांक 10-7-90

श्री श्रीलाल पुत्र श्री बन्हैयालाल ग्राम कोकालिया मलारना चौड़ जिला सवाई माधोपुर ।

—प्रार्थी

बनाम

डिवीजनल इंजीनियर टैलीकॉम (आर.ई.) न्य. दिल्ली ।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के.एल. व्यास, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से :	श्री बी.एम. बागड़ा
अप्रार्थी की ओर से :	कोई हाजिर नहीं
दिनांक अवार्ड :	11-9-1995

अवार्ड

निम्न विवाद केन्द्र सरकार द्वारा अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है :

'Whether the action of the management of Divisional Engineer, Telecom R.E. New Delhi is justified in not absorbing Shri Shreelal in Madhya Pradesh due to closureo f Sawai Madhopur Project ? If not, what relief the workman is entitled to ?'

2. श्रमिक ने प्रस्तुत क्लेम में यह बताया है कि उसने विपक्षी विभाग के अधीन सवाई माधोपुर परियोजना में जुलाई 1986 से 31-12-87 तक कार्य किया था व उसके पश्चात उसकी सेवाएं वहां से समाप्त की गई । इस संबंध में उसने समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया था व 2-1-89 को दोनों पक्षों के बीच समझौत अधिकारी के समक्ष यह समझौता हुआ कि श्रमिक को नियोजक द्वारा पुनः कार्य पर लिया जायेगा व मध्य प्रदेश में खाली जगह पर उसे नियोजित किया जायेगा । इस समझौते के परिणामस्वरूप उसने ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया किन्तु मध्य प्रदेश के स्थान पर उसे दक्षिण भारत में सेलम परियोजना पर कार्य करने के लिए भेजा गया तथा सेलम में भी उसे इस आधार पर ड्यूटी पर नहीं लिया गया कि वह अंग्रेजी या तमिल पढ़ना लिखना नहीं जानता । इस पर वह वापस भोपाल डिवीजनल इंजीनियर के यहां उपस्थित हुआ किन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की । इससे व्यथित होकर श्रमिक द्वारा पुनः समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया गया व असफल वार्ता के पश्चात यह विवाद निर्देशित किया गया है । अनुतोष यह मांगा गया है कि 1-1-89 के समझौते के परिणामस्वरूप नियोजक को यह निर्देश दिया जाये कि वह श्रमिक को मध्य प्रदेश में किसी परियोजना पर पदस्थापित करें तथा श्रमिक को 31-12-87

की सेवा मुक्ति के पश्चात समस्त बकाया लाभ निरन्तर सेवा में मानते हुए स्वीकृत किये जावें।

3. नियोजक की ओर से जवाब में प्रारंभिक आपत्ति यह ली गई है कि सवाई माधोपुर में जो विद्युतीकरण की परियोजना थी वह अस्थाई थी तथा वहां काय समाप्त होने के पश्चात परियोजना को बंद कर दिया गया व सभी श्रमिकों व कर्मचारियों का स्थानान्तरण उनकी पुरानी इकाई में कर दिया गया तथा जो कर्मचारी अस्थाई थे उन्हें सेवा मुक्त किया गया। श्रमिक के लिए यह बताया गया है क उसने स्वेच्छा से ही काम पर आना बंद कर दिया था। एक आपत्ति यह ली गई है कि संबंधित विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए विवाद पोषणीय नहीं है। 31-12-87 को श्रमिक को सेवा से हटाने के तथ्य को नियोजक ने स्वीकार नहीं किया है व विकल्प में यह अभिकथित किया है कि परियोजना बंद होने के कारण धारा 25-एफ लाग नहीं होती है। इसके अलावा यह बताया गया है कि अनुकम्पा स्वरूप समझौता अधिकारी के समक्ष नियोजक ने यह स्वीकार किया था कि श्रमिक को मध्य प्रदेश परियोजना में कार्य पर लगाया जा सकता है तथा मध्य प्रदेश योजना उस समय भोपाल से सेलम तक कार्यरत थी व भोपाल में जगह नहीं होने के कारण श्रमिक को सेलम भेजा गया था तथा वहां से उसे तिरूपन्तूर में सहायक अभियन्ता के यहां ड्यूटी जोइन करने के लिए निर्देशित किया गया परन्तु उसने वहां ड्यटी जोइन नहीं की तथा इस बात पर जोर दिया कि उसे उज्जैन में रखा जावे। उज्जैन में कोई भी जगह नहीं होने के कारण वहां श्रमिक को नियोजित किया जाना संभव नहीं था। इस प्रकार नियोजक का कथन यह है कि समझौते के परिणामस्वरूप स्वयं श्रमिक ने स्वैच्छा से ड्यूटी जोइन नहीं की इसलिए वह कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जवाब के साथ आर-1 से आर-6 प्रलेख नियोजक द्वारा प्रस्तुत किये गए हैं।

4. मौखिक साक्ष्य में श्रमिक की ओर से उसका स्वयं का शपथ पत्र व नियोजक की ओर से एक गवाह श्री शिवाजी उपाध्याय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। बहस के समय नियोजक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

5. नियोजक द्वारा संबंधित विभाग को उद्योग नहीं मानने की जो प्रतिरक्षा जवाब में ली गई है उस संबंध में मौखिक साक्ष्य में कोई भी तथ्य गवाह श्री शिवाजी उपाध्याय द्वारा अभिकथित नहीं किये गये हैं। दोनों पक्षों द्वारा जो अभिकथन प्रस्तुत किये गये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि सवाई माधोपुर व भोपाल परियोजना पर रेलवे विद्युतीकरण का कार्य होता था इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंगलोर वाटर सप्लाई के मामले में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं, उन्हें देखते हुए विपक्षी विभाग को उद्योग की परिभाषा में माना जाता है। नियोजक की ओर से केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण इलाहाबाद के एक निर्णय की फोटो-प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें उद्योग के संबंध में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं वे इस न्यायाधिकरण को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

6. दोनों पक्षों के अभिकथनों से यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में श्रमिक को सवाई माधोपुर परियोजना पर नियोजित किया गया था जहां बाद में कार्य समाप्त हो गया था। इसके आगे श्रमिक को कथन है कि नियोजक द्वारा उसकी सेवा धारा 25 एफ अधिनियम 1947 के प्रावधान पालना के बिना समाप्त की गई थी वहीं नियोजक का कथन यह है कि श्रमिक स्वेच्छा से काम छोड़कर चला गया था। अभिकथनों से यह भी स्पष्ट है कि इस कथित सेवा मुक्ति के संबंध में सहायक श्रम आयुक्त कोटा के समक्ष विवाद प्रस्तुत हुआ था व वहां दोनों पक्षों के बीच समझौते के परिणामस्वरूप नियोजक को मध्य प्रदेश परियोजना में श्रमिक को नियोजित करने के निर्देश दिये गये थे। इस आदेश की फोटो प्रति परिशिष्ट-2 है जो विवादग्रस्त नहीं है। इस समझौते में यह स्पष्ट उल्लेख है कि नियोजक ने श्रमिक की मध्य प्रदेश परियोजना में नियोजित करने की सहमति दी व यदि एक सप्ताह के भीतर श्रमिक कार्य पर उपस्थित नहीं होगा तो यह समझौता मानने के लिए नियोजक बाध्य नहीं होगा। इस समझौते के परिणामस्वरूप 31-12-87 को कथित सेवा मुक्ति का जो विवाद था वह स्वतः ही समाप्त हो गया तथा वर्तमान निर्देश में उस पर कोई विनिश्चय करने के निर्देश भी न्यायाधिकरण को नहीं है। अतः 31-12-87 की सेवा मुक्ति के संबंध में जो भी अभिकथन व साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

7. निर्देशित विवाद के अनुसार यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि क्या नियोजक द्वारा श्रमिक को मध्य प्रदेश परियोजना में नियोजित करना न्यायोचित है या नहीं। श्रमिक ने अपने क्लेम में व शपथ पत्र में यह बताया कि 1-1-89 के समझौते के परिणामस्वरूप उसने पहले भोपाल में ड्यूटी जोइन करने के लिए उपस्थिति दी किन्तु उसे वहां से प्रदर्श आर-3 के जरिये सेलम में रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया इसके अलावा श्रमिक का कथन है कि सेलम में भी उसे ड्यूटी पर नहीं लिया गया तथा जो भी बात उससे की गई वह इसलिए नहीं समझ सका क्योंकि वह तमिल भाषा नहीं जानता है। सेलम में ड्यूटी पर नहीं लेने के कारण वह वापस भोपाल आया किन्तु वहां भी उसे ड्यूटी पर नहीं लिया इसलिए उसने समझौता अधिकारी के पास पुनः विवाद प्रस्तुत किया। शपथ पत्र पर श्रमिक से जो जिरह हुई है उसमें उसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि सेलम में उसे तिरूपन्तूर ड्यूटी जोइन करने के लिए कहा गया। इसके आगे उसने यह भी बताया है कि में तमिलनाडू नहीं जाऊंगा क्योंकि वह स्थान बहुत दूर है तथा वहां की भाषा

भी नहीं जानता हूं। इसके अलावा श्रमिक का यह कथन है कि 1-1-89 के समझौते के अनुसार उसे भोपाल में ही नियोजित करने के निर्देश थे जिसकी पालना नियोजक द्वारा नहीं की गई । नियोजक की प्रतिरक्षा यह है कि भोपाल या उज्जैन में कोई जगह नहीं थी इसलिए श्रमिक को सेलम भेजा गया व वहां से उसे तिरुपन्तूर ड्यूटी जोइन करने के लिए निर्देशित किया गया किन्तु स्वेच्छा से उसने वहां ड्यूटी जोइन नहीं की तथा समझौते के अनुसार भोपाल या उज्जैन में नियोजित करने का कोई निर्देश नहीं था व भोपाल परियोजना भोपाल से सेलम तक कार्यरत थी। नियोजक के गवाह श्री शिवाजी उपाध्याय ने अपने शपथ पत्र में इन्हीं तथ्यों की पुष्टि की है व जो जिरह उनसे की गई है उसमें इन तथ्यों को गलत मानने का कोई भी आधार उत्पन्न नहीं हुआ है। इसके अलावा नियोजक की ओर से जो प्रलेख प्रस्तुत किये गये हैं उनमें परिशिष्ट-6 स्वयं श्रमिक का लिखित प्रार्थना-पत्र है जिसमें उसने यह बताया है कि वह दक्षिण भारत में नौकरी करने का इच्छुक नहीं है इसलिए उसे नागदा या उज्जैन में ड्यूटी पर लिया जावे। इस प्रलेख को किसी भी रूप में श्रमिक की ओर से गलत नहीं बताया गया है। स्वयं श्रमिक ने न्यायाधिकरण के समक्ष जिरह में भी यह स्वीकार किया है कि वह दक्षिण भारत में नौकरी करने का इच्छुक नहीं है। 1-1-89 के समझौते में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भोपाल से सेलम परियोजना पर श्रमिक को नियोजित किया जायेगा इसलिए सामान्य स्थिति में नियोजक भोपाल या उज्जैन में श्रमिक को कार्य पर लेने के लिए बाध्य नहीं थे। इसके अलावा नियोजक के गवाह श्री शिवाजी ने यह बताया है कि उस समय उज्जैन व भोपाल में पहले से अधिक श्रमिक कार्यरत थे इसलिए वहां वर्तमान श्रमिक को ड्यूटी पर लेना संभव नहीं था इन तथ्यों पर कोई जिरह गवाह से नहीं की गई है। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने बहस में यह बताया है कि भोपाल या उज्जैन में एक जगह होने के बावजूद श्रमिक को वहां नियोजित नहीं किया गया जो कार्यवाही नियोजक की अनुचित श्रम व्यवहार की परिभाषा में आती है इसलिए विवाद में अधिनिर्णय श्रमिक के पक्ष में पारित किया जावे। विपक्षी की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसके विपरीत स्वयं श्रमिक ने ऐसी कोई भी मौखिक या प्रालेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रमाणित हो कि उज्जैन या भोपाल में श्रमिक को लगाने के लिए जगह उपलब्ध थी। ऐसी स्थिति में श्रमिक की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की ओर से जो मौखिक व प्रालेखीय साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसका सार यह है कि 1-1-89 के समझौते के अनुसार नियोजक को यह निर्देश था कि श्रमिक को भोपाल से सेलम तक की कार्यरत परियोजना में नियोजित किया जावे, उज्जैन व भोपाल में जगह नहीं होने के कारण श्रमिक को सेलम भेजा गया था व वहां से तिरुपन्तूर ड्यूटी जोइन करने के निर्देश उसे दिये गये जहां उसने स्वेच्छा से ड्यूटी जोइन नहीं की। इसलिए 1-1-89 के समझौते की पालना नियोजक द्वारा नहीं करने का तथ्य किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं होता है तथा न ही नियोजक द्वारा किसी प्रकार की अनुचित श्रमिक प्रक्रिया अपनाने का तथ्य प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक कोई अनुतोष इस निर्देश के जरिये प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता।

8. विवेचित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि नियोजक द्वारा श्रमिक श्रीलाल को मध्य प्रदेश परियोजना में नियोजित करने का आदेश पारित किया गया था तथा उसने स्वेच्छा से वहां ड्यूटी जोइन नहीं की इसलिए श्रमिक कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

9. अवार्ड आज दिनांक 11-9-95 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ निम्नानुसार भेजा जावे।

के. एल. व्यास, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 7 मई, 1996

का. आ. 1553.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक व तार के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल—40012/2/85—डी 2 बी]
के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1996

S.O. 1553.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Jaipur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of P&T and their workman, which was received by the Central Government on 2-5-96.

[No. L-40012/2/85-D2B]
K. V. B. UNNY, Dsek Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 5/1986

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. एल. 40012/2/85—डी II (बी) दिनांक 14-2-86

श्याम बिहारी शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा, डाकघर बलोटा, पी. ओ. गिरधरपुरा वाया कुनारी ।

—प्रार्थी

बनाम

एस. डी. ओ. (दूरभाष) द्वितीय डाक व तार विभाग, विज्ञान नगर कोटा (राज.)

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के. एल. व्यास, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री एस. पी. सिंह

अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं (एक-पक्षीय)

दिनांक अवार्ड : 27-10-1995

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा निम्न निर्देश अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है :

"क्या एस. डी. ओ. (टेलीफोन्स II) कोटा की दैनिक दर के नैमित्तिक श्रमिक श्री श्याम बिहारी शर्मा की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार श्री श्याम बिहारी शर्मा किस अनुतोष का हकदार है ?"

2. श्रमिक ने अपने क्लेम में यह अभिकथित किया है कि उसे विपक्षी नियोजक द्वारा अगस्त 1983 से सितम्बर, 1984 तक दैनिक मजदूरी पर नियोजित किया गया था व उस अवधि में उसने लगातार नियोजक के यहां 402 दिन कार्य किया था व उसके पश्चात् धारा 25—एफ व 25—जी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे तत्पश्चात् अधिनियम संबोधित किया जायेगा) की पालना किये बिना उसकी सेवाएं नियोजक द्वारा समाप्त की गई इसलिए श्रमिक की सेवा मुक्ति की कार्यवाही अनुचित व अवैध है। श्रमिक का यह भी कथन है कि सेवा मुक्ति की तिथि से वह बेरोजगार है तथा उसके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। अनुतोष यह मांगा गया है कि श्रमिक को समस्त बकाया वेतन सहित सेवा में पुनः बहाल करने का आदेश दिया जावे।

3. नियोजक की ओर से जवाब में इस तथ्य को विशिष्ट रूप से खण्डन नहीं किया गया है कि श्रमिक ने नियोजक के यहां 402 दिन काम किया था बल्कि इस तथ्य को परोक्ष रूप से स्वीकार किया गया है। प्रतिरक्षा यह ली गई है कि श्रमिक की नियुक्ति पूर्ण रूप से आकस्मिक श्रमिक के रूप में व दैनिक मजदूरी पर की गई थी तथा उसकी नियुक्ति किसी भी स्थाई प्रकृति के कार्य के लिए या स्थाई स्थान के लिए नहीं की गई थी व इसके अलावा श्रमिक की सेवाएं नियोजक द्वारा किसी भी समय समाप्त नहीं की गई बल्कि श्रमिक ने स्वेच्छा से काम पर आना बंद कर दिया था क्योंकि उसे वेतन कम मिलता था तथा वह नियमित वेतनमान चाहता था। इन आधारों पर यह बताया गया है कि नियोजक की ओर से अधिनियम के किसी भी प्रावधान की अवहेलना नहीं की गई।

4. प्रारंभ में नियोजक की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित होते थे किन्तु बाद में नियोजक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इस कारण नियोजक के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया।

5. श्रमिक की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही में उसका स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है व इसके अलावा प्रदर्श डब्ल्यू 1 प्रलेख साक्ष्य में प्रदर्शित करवाये गये हैं। श्रमिक ने शपथ पत्र में यह वर्णित किया है कि उसने अगस्त 1983 से सितम्बर, 1984 की अवधि में लगातार नियोजक के यहां 402 दिन कार्य किया था व 1-10-84 से उसकी सेवाएं नियोजक द्वारा बिना नोटिस छंटनी का मुआवजा दिये समाप्त की गई। यह भी अभिकथित किया गया है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति के समय उससे कनिष्ठ श्रमिक कार्यरत थे तथा बाद में भी अन्य श्रमिकों को नियोजित किया गया था। श्रमिक ने शपथ पत्र में यह भी बताया है कि उसने स्वेच्छा से काम पर आना बंद नहीं किया था। प्रदर्श डब्ल्यू 1 प्रलेख जो साक्ष्य में प्रदर्शित करवाये गये हैं वह संबंधित एस. डी. ओ. टेलीफोन्स कोटा द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र हैं जिनके अनुसार श्रमिक ने उनके यहां अगस्त 1983 से सितम्बर 1984 के बीच 402 दिन काम किया था। नियोजक ने अपने जवाब में इस तथ्य का खण्डन नहीं किया है तथा साक्ष्य में भी इसके विरोध में कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मौखिक व प्रालेखीय साक्ष्य से यह साबित है कि श्रमिक ने लगातार 402 दिन नियोजक के यहां कार्य किया था। नियोजक ने जवाब में जो यह बताया है कि श्रमिक की नियुक्ति आकस्मिक श्रमिक के रूप में व दैनिक मजदूरी पर की गई थी उसके लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है किन्तु श्रमिक का कथन इसके विपरीत नहीं है व इसके बावजूद जहां तक धारा 25—एफ के प्रावधान की पालना का प्रश्न है, उस पर कोई भी विपरीत प्रभाव इस तथ्य से नहीं पड़ता है क्योंकि दैनिक मजदूरी पर भी जिस श्रमिक ने 240 दिन से अधिक लगातार कार्य किया है उसको धारा 25 एफ के अनुसार नोटिस, व मुआवजा दिया जाना आज्ञापक है अतः यह साबित है कि नियोजक द्वारा श्रमिक की कथित सेवा मुक्ति के समय धारा 25; एफ अधिनियम के प्रावधान की पालना नहीं की गई है। नियोजक ने अपने जवाब में जो यह प्रतिरक्षा ली है कि श्रमिक स्वयं ही नौकरी छोड़कर चला गया था उसके समर्थन में कोई भी मौखिक या प्रलेखनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई तथा श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में व क्लेम में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि उसने स्वेच्छा से नौकरी पर आना बंद नहीं किया था बल्कि उसे सेवा से हटाया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज से नियोजक की प्रतिरक्षा की संभावना प्रकट नहीं होती है।

6. श्रमिक ने अपने क्लेम में धारा 25—जी अधिनियम के प्रावधान की अवहेलना नियोजक द्वारा करना बताया है व शपथ पत्र व क्लेम में मात्र यह उल्लेख

किया है कि उसकी सेवामुक्ति के समय उससे कनिष्ठ श्रमिक कार्यरत थे परन्तु किसी भी श्रमिक का नाम उल्लिखित नहीं किया गया है व न ही इस संबंध में नियोजक का कोई रिकार्ड तलब करवाया गया है। ऐसी स्थिति में श्रमिक के अस्पष्ट व अनिश्चित कथन के आधार पर यह माना जाना संभव नहीं है कि उसकी मुक्ति के श्रेणी के कनिष्ठ कर्मचारी नियोजक के यहां कार्य कर रहे थे।

7. श्रमिक ने शपथ पत्र में यह उल्लेख किया है कि उसकी सेवामुक्ति के पश्चात् अन्य व्यक्तियों को नियोजक द्वारा नियोजित करके धारा 25-एच अधिनियम के प्रावधान की अवहेलना की गई है। यह साक्ष्य इसलिए विश्वसनीय नहीं है क्योंकि क्लेम में इस प्रकार का कोई भी कथन श्रमिक द्वारा नहीं किया गया है व इसके अलावा साक्ष्य में भी यह नहीं बताया गया है कि किस व्यक्ति को किस रूप में नियोजक द्वारा श्रमिक की सेवामुक्ति के पश्चात् नियोजित किया गया था। यह विवादहीन विधि की स्थिति है कि किसी भी तथ्य के संबंध में अभिकथन के अभाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अतः धारा 25-एच के प्रावधान की अवहेलना का तथ्य भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

8. श्रमिक ने अपने क्लेम में यह बताया है कि वह सेवामुक्ति के पश्चात् बेरोजगार रहा है, शपथ पत्र में इस संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार नियोजक के लिए यह प्रतिरक्षा लेना आवश्यक है कि श्रमिक के पास आय का अन्य कोई साधन है व इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। नियोजक ने अपने जवाब में इस प्रकार की प्रतिरक्षा नहीं ली है व साक्ष्य भी कोई प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः मान्य विधि सिद्धान्तों के अनुसार श्रमिक बकाया पिछला वेतन नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. श्रमिक की नियुक्ति अभिकथनों के अनुसार आकस्मिक श्रमिक के रूप में दैनिक मजदूरी पर की गई थी। इसलिए सेवा में पुनः बहाली की स्थिति में उसको वे ही अधिकार उपलब्ध होंगे जो सेवा मुक्ति के समय उपलब्ध थे।

10. निर्देशित विवाद अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि श्रमिक श्याम बिहारी शर्मा को दिनांक 1-10-84 से एस. डी. ओ. (टेलीफोन्स) द्वितीय कोटा द्वारा सेवा मुक्त करने की कार्यवाही अनुचित व अवैध है इसलिए श्रमिक पुनः सेवा में आने का, सेवा की निरन्तरता बनाये रखने का व सेवामुक्ति की तिथि से सेवा में आने तक की तिथि का समस्त पिछला वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। श्रमिक को पुनः उसी प्रकृति में नियोजित किया जायेगा जिस रूप में उसे प्रारंभ में नियुक्ति दी गई थी।

11. अधिनिर्णय आज दिनांक 27-10-95 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

के. एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 8 मई, 1996

का. आ. 1554.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/52/92-आई आर (डी यू)]

के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th May, 1996

S.O. 1554.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Posts and their workman, which was received by the Central Government on 2-5-96.

[No. L-40012/52/92-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Thursday, the 28th day of March, 1996

Present :

THIRU N. SUBRAMANIAN, B.A.,B.L., Industrial Tribunal.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 70 OF 1993

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and management of Department of Posts, RMS 'M' Division, Madras-10).

BETWEEN

Thiru A. Asokan,
No. 16 Mosque Back Street,
S. Kodiyur, Jolarpettai-635 851,
N. A. Ambedkar District.

AND

The Superintendent,
Department of Posts,
RMS 'M' Division, Madras-600 010.

Reference :

Order No. L-40012/52/92-IR(DU), dt. 21-7-1993, Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, the 6th day of March, 1996 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru P. Arulmudi, advocate appearing for the workman and of Thiru S. Srinivasan, Addl. Standing Government Counsel appearing for the management and this dispute having stood over till the day of consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

The Government of India by its Letter No. L-40012/55/92-IR (DU) referred for adjudication before this Tribunal u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act relating to "whether the Management of Department of Posts is justified in terminating the service of Shri A. Asokan with effect from 20-7-90, if not what relief the workman concerned is entitled to ?

2. After service of summons the petitioner as well as respondent filed their claim statement and counter statement.

3. The case of the petitioner as per the claim statement is as follows : The Petitioner joined service of the respondent as Casual Mazdoor in May 1989 at Sub-Record Office, Railway Mail Service, Jolarpet. He continued his work till 20-7-90. He was paid at the rate of Rs. 1.40 per hour. Though his post was designated as Casual Mazdoor the work he was called upon was not casual. The respondent terminated his services by an order dated 20-7-90. No notice was given before his termination. The petitioner raised dispute before the Assistant Commissioner of Labour. The respondent filed his reply. Because of conciliation failed the Assistant of Labour submitted his failure report to the Government. The termination of the petitioner without holding any enquiry is against the prsnciples of natural justice. The mandatory condition stipulated u/s 25-F of the Industrial Disputes Act was not complied with. The petitioner was in continuous service for more than 3 years. He has been in service for more than 240 days prior to the order of termination. Hence the dispute has been raised.

4. The respondent filed his counter contending that the petitioner was engaged to work in Sub-Record Office at Jolarpet w.e.f. 18-5-89 temporarily in leave vacancy. He was paid from contingencies only on hourly basis. He was not sponsored by the Employment Exchange. As per the Director General of Posts, New Delhi letter dated 5-2-90 and 29-3-90 the services of the Casual Labourers who had put in less than one year of service as on 5-2-90 had to be dispensed with. Accordingly, the petitioner's service was dispensed with. The petitioner was not appointed against any sanctioned post or establishment. As per the Director General, Posts, Order dated 29-3-90 there was complete ban on recruitment of casual labourers in the entire department. Hence the dispute may be dismissed with costs.

5. By consent Ex. W-1 to W-5 and M-1 marked.

6. The point for consideration is whether the Management of Department of Posts is justified in terminating the service of Thiru A. Asokan w.e.f. 20-7-90 ? If not what relief the workman concerned entitled to ?

7. POINT : The petitioner was employed as Casual Mazdoor from 1-6-89 as per Ex. W-1. The petitioner was in continuous service till his termination under Ex. W-2 on 20-7-90. Admittedly, before termination he was not given any notice or no enquiry was conducted. According to him, he has put in more than 240 days in 12 months prior to the date of his termination. So his termination without notice u/s 25-F of the Industrial Disputes Act is illegal. It is contended by the respondent's counsel the petitioner was employed as Casual Mazdoor in the leave vacancy. He was paid from contingency on the hourly basis. Ex. M-1 is the conditions of the employment. As per Ex. M-1 employment is temporary and he is liable to be terminated at any time if there is no work and the petitioner cannot claim any right. So it is argued by the respondent's counsel as per the conditions of the employment he was terminated from the service and so he cannot question the termination or he cannot invoke Sec. 25-F of the Industrial Disputes Act. For that, he relied on the decision reported in 1993(II) LLJ page 903 the Supreme Court has held. It was expressly indicated in the letter of appointment that such appointment was intrinsically a temporary one and was liable to be terminated at any time without any notice. If in terms of service, the order of termination had been passed, no exception should be made to such orders and such orders cannot be treated as retrenchment within the meaning of Sec. 25-F of the I.D. Act." Further he relied another decision reported in 1993 L.I.C. page 836, the Allahabad High Court has held, the persons appointed on daily wages or on Adhoc basis have no right to claim their services to be regularised merely because he has completed 240 days in service. It is true merely because a casual worker worked more than 240 days in a year cannot claim regularisation. Regularisation requires something more. There must be both post, funds and the need of retention of the employee according to the requirement of the work. Further he must be qualified and the work and conduct of such employee must also be satisfactory. In the present case, it is not the question of regularisation of casual employees. So the decision reported above will not apply to the present case. It is argued by the petitioner's counsel the decision reported in 1993(II) LLJ Supreme Court at page No. 903 also will not apply to the facts of the present case. Even though the petitioner was employed as Casual Mazdoor he was not terminated in terms of his employment. In the cited case the order of the employment, there is condition that his service can be terminated at any time withut any notice. In the present case the appointment order Ex. M-1, there is no condition that his service can be terminated at any time without any notice. Further it is stated his service can be terminated only when there is no work. The termination order Ex. W-2, it is not stated that because of want of work his service was terminated. On the other hand it is stated as per the Circular of the Director General, Posts dated 29-3-90 services of the petitioner was terminated. As per the circular Casual employees who have not completed one year of service as on 5-2-90 their service may be dispensed with. Only on the ground the services of the petitioner was dispensed with. So the termination of the petitioner is not on the terms and conditions of the employment. If the services of the petitioner is terminated for want of work he cannot question the termination as per the decision of the Supreme Court reported in 1993(II) LLJ page 903. If the petitioner is terminated on some other ground the employer must follow the procedure before terminating the service for whatever reason. It is admitted the petitioner is a workman as defined under section 2(s) which includes Apprentice also. Under section 25-F also it is stated as "workman". No distinction is made either in Sec. 25-F or in Sec. 2(s) between Casual worker and temporary worker and permanent worker. U/s 2(oo) retrenchment means the termination by the employer of the services of the workman for any reason whatsoever, otherwise than as punishment inflicted by way of disciplinary action. There also the word workman is used without any qualification. So Casual Labour is also a workman. Since the petitioner was terminated from his service not under the conditions of employment but on some other reasons it amounts to retrenchment. The fact that the petitioner worked more than 240 days in 12 months prior to the order of the termination is not disproved by the management with their records. Therefore the order of termination of the petitioner will amounts to only a retrenchment as defined u/s 2(00) of I. D. Act. Therefore, the respondent who failed to follow the procedure contemplated u/s 25-F before terminating the services of the petitioner for whatever reasons is illegal. It is admitted no notice was given before termination order, one month pay was given in lieu of notice and compensation, as contemplated in Sub-clause 25-F was also not paid. Therefore, the termination of the petitioner is in violation of Sec. 25-F and therefore it is illegal.

In the result, an award is passed setting aside the order of dismissal dated 20-7-90 and directed the respondent to reinstate the petitioner in service without back wages. No costs.

Dated this the 28th day of March, 1996.

N. SUBRAMANIAN, Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For Workman

W.W. 1—Thiru A. Asokan.

For Management : None.

DOCUMENTS MARKED

For Workman

Ex. W-1— —Appointment order issued to the Petitioner-workman Thiru A. Asokan (Xerox copy).

Ex. W-2-20-7-09—Order of termination issued to the workman (xerox copy.

Ex. W-3-21-7-90—Representation of the workman to the Management (xerox copy)

Ex. W-4— -8-90—Representation of the workman to the Chief Post Master General, Madras-2 (Xerox copy).

Ex. W-5— —2-A petition filed by the workman before the Regional Labour Commissioner (copy).

For Management

Ex. M-1—Conditions of employment and its acceptance by the Petitioner Workman (Xerox copy).

नई दिल्ली, 8 मई, 1996

का. आ. 1555.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/55/92—आई आर (डी यू)]

के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th May, 1996

S.O. 1555.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Posts and their workman, which was received by the Central Government on 2-5-1996.

[No. L-40012/55/92-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Friday, the 29th day of March, 1996

PRESENT :

Thiru N. Subramanian, B.A., B.L., Industrial Tribunal.
Industrial Dispute No. 66 of 1993

(In the matter of the disptue for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the management of Department of Posts, RMS Division, Madras).

BETWEEN

Thiru M. Anthony Louis,

No. 12 Jayamadha Nagar, Jolarpettai-635851,
North Arcot Ambedkar District.

AND

The Superintendent,
Department of Posts,
RMS 'M' Division, Madras-600010.

REFERENCE :

Order No. L-40012/55/92-IR (DU), dated 21-7-1993, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This disputt coming on for final hearing on Wednesday, the 6th day of March 1996, upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru P. Arulmudi, advocate appearing for the workman and of Thiru S. Srinivasan, Additional Standing Government Counsel appearing for the management, and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following ;

AWARD

The Government of India by its letter No. L-40012|55|92-IR (DU) referred for adjudication before this Tribunal u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act relating to "Whether the Management of the Department of Posts is justified in terminating the services of Shri M. Anthony Louis with effect from 20-7-90 ? If not, what relief is the workman concerned entitled to ?"

2. After service of summons the petitioner as well as respondent filed their claim statement and counter statement.

3. The case of the petitioner as per the claim statement is as follows :

The petitioner joined service of the respondent as casual Mazdoor in May 1989 at Sub-Record Office. Railway Mail Service, Jolarpet. He continued his work till 20-7-90. He was paid at the rate of Rs. 1.40 per hour. Though his post was designated as Casual Mazdoor the work he was called upon was not casual. The respondent terminated his service by an order dated 20-7-90. No notice was given before his termination. The ptitioner raised dispute before the Assistant Commissioner of Labour. The respondent filed his reply. Because of conciliation failed the Assistant Commissioner of Labour submitted his failure report to the Govtrnment. The termination of the petitioner without holding any enquiry is against the principle of natural justice. The mandatory condition stipulated u/s 25-F of the Industrial Disputes Act was not complied with. The petitioner was in continuous service for more than 3 years. He has been in service for more than 240 days prior to the order of termination. Hence the dispute has been raised.

4. The respondent filed his counter contending that the petitioner was engaged to work in Sub-Record office at Jolarpet w.e.f. 18-5-89 temporarily in leave vacancy. He was paid from contengencies only on hourly basis. He was not sponsored by the Employment Exchange. As per the Director General of Posts, New Delhi letter dated 5-2-90 and 29-3-90 the services of the Casual Labourers who had put in ltss than one year of service as on 5-2-90 had to be dispensed with. Accordingly, the petitioner's service was dispensed with. The petitioner was not appointed against any sanctioned post or establishment. As per the Director General, Posts order dated 29-3-90 there was complete ban on recruitment of casual labourers in the entire department. Hence the dispute may be dismissed with costs.

5. By consen Ex. W-1 to W-5 and M-1 marked.

6. The point for consideration is whether the Management of Department of Posts is justified in terminating the service of Thiru M. Anthony Louis with effect from 20-7-90 If not what relief the workman concerned entitled to ?

7. *Point.*—The petitioner was employed as Casual Mazdoor nuous service till his termination under Ex. W-2 on 20-7-90, Admittedly, before termination he was not given any notice or no enquiry was conducted. According to him, he has put in more than 240 days in 12 months prior to the date of his termination. So his termination without notice u/s 25-F of the Industrial Disputes Act is illegal. It is contended by the respondent's counsel the petitioner was employed as Casual Mazdoor in the leave vacancy. He was paid from contingency on the hourly basis. Ex. M-1 is the conditions of the employment. As per Ex. M-1 employment is temporary and he is liable to be terminated at any time of there is no work and the petitioner cannot claim any right. So

it is argued by the respondent's counsel as per conditions of the employment he was terminated from the service and so he cannot question the termination or the cannot nvoke 25(F) of the Industrial Disputes Act. For that, he relied on the decision reported in 1993 (II)LLJ page 903 the on the decision reported in 1993 (II LLJ page 903 the letter of appointment that such appointment was intrinsically a temporary one and was liable to be terminated at any time without any notice. If in terms of service, the orders of termination had been passed, no exception should be made to such orders and such orders cannot be treated as retrenchment within the meaning of Section 25-F of the Act". Further he relied another decision reported in 1993 Lab. I.C. page 836. The Allahabad High Court has held, the persons appointed on daily wages or on Adhoc basis have no right to claim their services to be regularised merely because he has completed 240 days in service. It is true merely because a casual worker worked more than 240 days in a year cannot claim regularisation. Regularisation requires something more. There must beboth post, funds and the need of retention of the employee according to the requirement of the work. Further he must be qualified and the work and conduct of such employee must also be satisfactory. In the present case it is not question of regularisation of casual employees. So the decision reported above will not apply to the present case. It is argued by the petitioner's counsel the decision reported in 1993 (II) LLJ Supreme Court at page No. 903 also will not apply to the facts of the present case. Even though the petitioner was employed as Casual Mazdoor he was not terminated in terms of his employment. In the cited case the order of the employment there is condition that his services can be terminated at any ime without any notice. In the presen case the appointment order Ex. M-1 there is no condition that his services can be terminated at any time without any notice. Further it it stated his services can be terminated only when there is no work. The termination order Ex. W-2 it is not stated that because of want of work his service was terminated. On the other hand it is stated as per the Circular of the Director General, Posts dated 29-3-90 services of the petitioner was terminated. As per the circular Casual employees who have not completed one year of service as on 5-2-90 their service may be dispensed with. Only on that ground the services of the petitioner was dispensed with. So the termination of the petitioner is not on the terms and conditions of the employment. If the services of the petitioner is terminated for want of work he cannot question the termination as per the decision of the Supreme Court reported in 1993 (II) LLJ page 903. If the petitioner is terminated on some other grounds the employer must follow the procedure before terminating the service for whatever reason. It is admitted the petitioner is a workman as defined under Section 2(s) which includes Apprentice also. Under Section 25-F also it is stated as "workman" No distinction is made either in Section 25-F or in Section 2(s) between casual worker and temporary worker and permanent worker. U/s 2(oo) retrenchment means the termination by the employer of the services of the workman for any reason whatsoever, otherwise than as punishment inflicted by way of disciplinary action. There also the word workman is used without any qualification. So casual labour is also a workman. Since the petitioner was terminated from his service not under the conditions of employm but on someother reasons it amounts to retrenchment. The fact that the petitioner worked more than 240 days in 12 months prior to the order of he termination is not disproved by the management with their records. Therefore the order of the termination of the petitioner will amounts to only a retrenchment as defined under Section 2(oo) of the I. D. Act Therefore the respondent who failed to follow the procedure contemplated u/s 25-F before terminating the services of the petitioner for whatever reasons is illegal It is admitted no notice was given before termination order, one month pay was given in lieu of notice and compensation as contemplated in sub clause 25-F was also not paid. Therefore, the termination of the petitioner is in violation of Section 25-F and therefore it is illegal.

In the result, an award is passed setting aside the order of dismissal dated 20-7-90 and directed the respondent to reinstate the petitioner in service without back wages. No costs.

Dated this 29th day of March 1996.

N. SUBRAMANIAN, Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For both sides :

None

DOCUMENT MARKED

For workman :

Ex. W-1 —Appointment order issued to petitioner-workman Thiru M. Anthony Louis as a Mazdoor (Xerox copy)

Ex. W 2/20-7-90—Order of termination issued to petitioner-workman (Xerox copy)

Ex. W-3/21-7-90—Representation by the petitioner-workman to the management (Xerox copy)

Ex. W-4/ 8-90—Representation by the Petitioner-workman to the Chief Post Master General Madras-2 (Xerox copy)

Ex. W-5 —2 A petition filed by the petitioner-workman before the Regional Labour Commissioner Madras (Xerox copy)

For Management :

Ex. M-1—Conditions of employment and its acceptance by the Petitioner-workman (Xerox copy)

नई दिल्ली, 8 मई, 1996

का. आ. 1556:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/56/92-आई आर (डी यू)]
के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th May, 1996

S.O. 1556.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Madras as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Posts and their workman, which was received by the Central Government on 2-5-96.

[No. L-40012|56|92-IR (DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Thursday, the 28th day of March, 1996

PRESENT :

THIRU N. SUBRAMANIAN, B.A.,B.L., Industrial Tribunal
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 71 OF 1993

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the management of Department of Posts, R.M.S. 'M' Division, Madras-10).

BETWEEN

Thiru S. Dhandapani,
No. 43, M. C. Kuppam,
Reddiyar (Post), Jolarpettal,
N. A. Ambedkar District.

AND

The Superintendent,
Department of Posts, R.M.S. 'M' Division,
Madras-600 010.

Reference :

Order No. L-40012/56/92-IR(DU), dated 21-7-93, Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, the 6th day of March, 1996 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru P. Arulmudi, advocate appearing for the workman and of Thiru S. Srinivasan, Addl. Standing Government Counsel appearing for the management and this dispute hardly stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

The Government of India by its letter No. 40012/55/92 IR(DU) referred for adjudication before this Tribunal u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act relating to "Whether the management of the Department of Posts is justified in terminating the services of Shri S. Thandapani with effect from 20-7-90. If not what relief the workman concerned is entitled to ?".

2. After service of summons the petitioner as well as respondent filed their claim statement and counter statement.

3. The case of the petitioner as per the claim statement is as follows : The petitioner joined service of the respondent as Casual Mazdoor in October 1984 at Sub-Record Office, Railway Mail Service, Jolarpet. He continued his work till 20-7-90. He was paid at the rate of Rs. 1.40 per hour. Though his post was designated as Casual Mazdoor the work he was called upon was not Casual. The respondent terminated his services by an order dated 20-7-90. No notice was given before his termination. The petitioner raised dispute before the Assistant Commissioner of Labour. The respondent filed his reply. Because of conciliation failed the Assistant Commissioner of Labour submitted his failure report to the Government. The termination of the petitioner without holding any enquiry is against the principles of natural justice. The mandatory condition stipulated u/s 25-F of the Industrial Disputes Act was not complied with. The petitioner was in continuous service for more than 3 years. He has been in service for more than 240 days prior to the order of termination. Hence the dispute has been raised.

4. The respondent filed his counter contending that the petitioner was engaged to work in Sub-Record Office at Jolarpet w.e.f. 18-5-89 temporarily in leave vacancy. He was paid from contingencies only on hourly basis. He was not sponsored by the Employment Exchange. As per the Director General of Posts, New Delhi letter dated 5-2-90 and 29-3-90 the services of the Casual Labourers who had put in less than one year of service as on 5-2-90 had to be dispensed with. Accordingly, the petitioner's service was dispensed with. The petitioner was not appointed against any sanctioned post of establishment. As per the Director General, Posts Order dated 29-3-90 there was complete ban on recruitment of casual labourers in the entire department. Hence the dispute may be dismissed with costs.

5. By consent Ex. W-1 to W-5 and M-1 marked.

6. The point for consideration is whether the management of Department of Posts is justified in terminating the service of Thiru S. Thandapani w.e.f. 20-7-90 ? If not what relief the workman concerned entitled to ?

7. POINT : The petitioner was employed as Casual Mazdoor from 1-6-89 as per Ex. W-1. The petitioner was in continuous service till this termination under Ex. W-2 on 20-7-90. Admittedly, before termination he was not given any notice or no enquiry was conducted. Accordingly, to him, he has put in more than 240 days in 12 months prior to the date of his termination. So his termination without notice u/s 25-F of the Industrial Disputes Act is illegal. It is contended by the respondent's counsel the petitioner was employed as Casual Mazdoor in the leave vacancy. He was paid from contingency on the hourly basis. Ex. M-1 is the conditions of the employment. As per Ex. M-1 employment is temporary and he is liable to be terminated at any time if there is no work and the petitioner cannot claim any right. So it is argued by the respondent counsel as per the conditions of the employment he was terminated from the service and so he cannot question the termination or he cannot invoke Sec. 25-F of the Industrial Disputes Act. For that, he relied on the decision reported in 1993 (II) LLJ page 903 the Supreme Court has held "It was expressly indicated in the letter of appointment that such appointment was intrinsically a temporary one and was liable to be terminated at any time without any notice. If in terms of service, the orders of termination had been passed, no exception should be made to such orders and such orders cannot be treated as retrenchment within the meaning of Sec. 25-F of the I.D. Act. Further he relied another decision reported in 1993 L.I.C. page 836 the Allahabad High Court has held, the persons appointed on daily wages or on Adhoc basis have no right to claim their services to be regularised merely because he has completed 240 days in service. It is true merely because a casual worker worked more than 240 days in a year cannot claim regularisation. Regularisation requires something more. There must be both post, funds and the need of retention of the employee according to the requirement of the work. Further he must be qualified and the work and conduct of such employees must also be satisfactory. In the present case, it is not the question of regularisation of casual employees. So the decision reported above will not apply to the present case. It is argued by the petitioner's counsel the decision reported in 1993 (II) LLJ Supreme Court at page No. 903 also will not apply to the facts of the present case. Even though the petitioner was employed as Casual Mazdoor he was not terminated in terms of his employment. In the cited case the order of the employment, there is condition that his service can be terminated at any time without any notice. In the present case the appointment order Ex. M-1, there is no condition that his service can be terminated at any time without any notice. Further it is stated his service can be terminated only when there is no work. The termination order Ex. W-2, it is not stated that because of want of work his service was terminated. On the other hand, it is stated as per the Circular of the Director General, Posts dated 29-3-90 services of the petitioner was terminated. As per the Circular Casual employees who have not completed one year of service as on 5-2-90 their service may be dispensed with. Only on that ground the services of the petitioner was dispensed with. So the termination of the petitioner is not on the terms and conditions of the employment. If the services of the petitioner is terminated for want of work he cannot question the termination as per the decision of the Supreme Court reported in 1993 (II) LLJ page 903. If the petitioner is terminated on some other ground the employer must follow the procedure before terminating the service for whatever reason. It is admitted the petitioner is a workman as defined under Section 2(s) which includes Apprentice also under section 25-F also it is stated as "workman". Not distinction is made either in Sec. 25-F or in Sec. 2(s) between Casual worker and temporary worker and permanent worker. U/s 2(oo) retrenchment means the termination by the employer of the services of the workman for any reason whatsover, otherwise than as punishment inflicted by way of disciplinary action. There also the word workman is used without any qualification. So casual labour is also a workman. Since the petitioner was terminated from his service not under the conditions of employment but on some other reasons it amounts to retrenchment. The fact that the petitioner worked more than 240 days in 12 months prior to the order of the termination is not disproved by the management with their records. Therefore the order of the termination of the petitioner will amounts to only a retrenchment as defined u/s 2(oo) of I.D. Act. Therefore, the respondent who failed to follow the procedure contemplated u/s 25-F before terminating the services of the petitioner for whatever reasons is illegal. It is admitted no notice was given before termination order, one month pay was given in lieu of notice and compensation, as contemplated in Sub-Clause 25-F was als not paid. Therefore, the termination of the petitioner is in violation of Sec. 25-F and therefore it is illegal.

In the result, an award is passed setting aside the order of dismissal dated 20-7-90 and directed the respondent to reinstate the petitioner in service without back wages. No costs.

Dated this the 28th day of March 1996.

N. SUBRAMANIAN, Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For both sides : None.

DOCUMENTS MARKED

For Workman

Ex. W-1—1-9-84—Application by the petitioner-workman for the post of casual Mazdoor (Xerox copy).

Ex. W-2—12-2-90—Representation of the petitioner-worker to the Management (Xerox copy).

Ex. W-3—12-2-90—Order of termination (Xerox copy).

Ex. W-4—21-7-90—Letter from the petitioner-workman to the management requesting to revoke the termination order (Xerox copy).

Ex. W-5—2-3-91—2A petition filed by the petitioner-workman before the Regional Labour Commissioner, Madras-6 (Xerox copy).

Ex. W-6—2-4-91—Representation of the Petitioner-worker to the Director General, Department of Posts, New Delhi requesting to re-appoint him (Xerox copy).

Ex. W-7—11-7-91—Reply by the management to the petitioner-workman (Xerox copy).

For Management :

Ex. M-1—Acceptance letter for conditions of employment (Xerox copy).

नई दिल्ली, 8 मई, 1996

का. आ. 1557 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/57/92-आई आर (डी यू)]

के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th May, 1996

S.O. 1557.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Madras as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Posts and their workman, which was received by the Central Government on 2-5-96.

[No. L-40012/57/92-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Friday, 29th day of March, 1996

PRESENT :

Thiru N. Subramanian, B.A., B.L., Industrial Tribunal

Industrial Dispute No. 67 of 1993.

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the management of Department of Posts, RMS Division, Madras.)

BETWEEN

Thiru D. Selvarajan,
S/o Sh. M. Duraisamy,
No. 81 Nehru Road, Edaiyampatti,
Jolarpettai-635 851.

AND

The Superintendent,
Department of Posts,
RMS 'M' Division, Madras-600 010.

REFERENCE :

Order No. L-40012/57/92-IR(DU), dated 21-7-1993, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, the 6th day of March, 1996, upon perusing the reference, claim and counter statement and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru P. Arulmudi, advocate appearing for the workman and of Thiru S. Srinivasan, Additional Standing Government Counsel appearing for the management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

"The Government of India by its letter No. 40012/55/92-IR(DU) referred for adjudication before this Tribunal u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act relating to "Whether the Management of the Department of Posts is justified in terminating the services of Shri D. Selvarajan with effect from 20-7-90. If not, what relief is the workman concerned entitled to ?"

2. After service of summons the petitioner as well as the respondent filed their claim statement and counter statement.

3. The case of the petitioner as per the claim statement is as follows : The petitioner joined service of the respondent as Casual Mazdoor in May 1989 at Sub-Record Office, Railway Mail Service, Jolarpet. He continued his work till 20-7-90. He was paid at the rate of Rs. 1.40 per hour. Though his post designated as Casual Mazdoor the work he was called upon was not casual. The respondent terminated his services by an order dated 20-7-90. No notice was given before his termination. The petitioner raised the dispute before the Assistant Commissioner of Labour. The respondent filed his reply. Because of conciliation failed the Assistant Commissioner of Labour submitted his failure report to the Government. The termination of the petitioner without holding any enquiry is against the principles of natural justice. The mandatory condition stipulated u/s 25(F) of the Industrial Disputes Act was not complied with. The petitioner was in continuous service for more than 3 years. He has been in service for more than 240 days prior to the order of termination. Hence the dispute has been raised.

4. The respondent filed his counter contending that the petitioner was engaged to work in Sub-Record Office at Jolarpet w.e.f. 18-5-89 temporarily in leave vacancy. He was paid from contingencies only on hourly basis. He was not sponsored by the Employment Exchange. As per the Director General of Posts, New Delhi letter dated 5-2-90 and 29-3-90 the services of the Casual Labourers who had put in less than one year of service as on 5-2-90 had to be dispensed with. Accordingly, the petitioner's service was dispensed with. The petitioner was not appointed against any sanctioned post or establishment. As per the Director General, Posts, order dated 29-3-90 there was complete ban on recruitment of casual labourers in the entire department. Hence the dispute may be dismissed with costs.

5. By consent Ex. W-1 and W-2 and M-1 marked.

6. The point for consideration is whether the Management of Department of Posts is justified in terminating the service of Thiru D. Selvarajan with effect from 20-7-90 ? If not what relief the workman concerned entitled to ?

7. POINT : The petitioner was employed as Casual Mazdoor from 1-6-89 as per Ex. W-1. The petitioner was in continuous service till his termination under Ex. W-2 on 20-7-90. Admittedly, before termination he was not given any notice or no enquiry was conducted. Accordingly to him, he has put in more than 240 days in 12 months prior to the date of his termination. So his termination without

notice u|s 25-F of the Industrial Disputes Act is illegal. It is contended by the respondent's counsel the petitioner was employed as Casual Mazdoor in the leave vacancy. He was paid from contingency on the hourly basis. Ex. M-1 is the conditions of the employment. As per Ex. M-1 employment is temporary and he is liable to be terminated at any time if there is no work and the petitioner cannot claim any right. So it is argued by the respondent's counsel as per conditions of the employment he was terminated from the service and so he cannot question the termination or he cannot invoke sec. 25(F) of the Industrial Dispute Act. For that he relied on the dicision reported in 1993 (II) LLJ page 903 the Supreme Court has held "It was expressly indicated in the letter of appointment that such appointment was intrinsically a temporary one and was liable to be terminated at any time without any notice. If in terms of service the orders of termination had been passed, no exception should be made to such orders and such orders cannot be treated as retrenchment within the meaning of section 25-F of the Act. "Further he relied another decision reported in 1993 Lab. I.C. page 836. The Allahabad High Court has held, the persons appointed on daily wages or on Ad-hoc basis have no right to claim their services to be regularised merely because he has completed 240 days in service. It is true merely because a casual worker worked more than 240 days in a year cannot claim regularisation. Regularisation requires something more. These must be both post, funds and the need of retention of the employee according to the requirement of the work. Further he must be qualified and the work and conduct of such employee must also be satisfactory. In the present case it is not question of regularisation of casual employees. So the decision reported above will not apply to the present case. It is argued by the petitioner's counsel the decision reported in 1993(II) LLJ Supreme Court at page No. 903 also will not apply to the facts of the present case. Even though the petitioner was employed as Casual Mazdoor he was not terminated in terms of his employment. In the cited case the order of the employment there is condition that his services can be terminated at any time without notice. In the present case the appointment order Ex. M-1 there is no condition that his services can be terminated at any time without any notice. Further it is stated his services can be terminated only when there is no work. The termination order Ex. W-2 it is not stated that because of want of work his service was terminaed. On the other hand it is stated as per the Circular of the Director General, Posts dated 29-3-90 services of the petitioner was terminated. As per the circular Casual Employees who have not completed one year of service as on 5-2-90 their service may be dispensed with. Only on that ground the services of the petitioner was dispensed with. So the termination of the petitioner is not on the terms and conditions of the Employment. If the services of the petitioner is terminated for want of work he cannot question the tmination as per the decision of the Supreme Court reported in 1993 (II) LLJ page 903. If the petitioner is terminated on some other ground the employer must follow the procedure before terminating the service for whatever reason. It is admitted the petitiltner is a workman as defined under section 2(s) which includes apprentice also. Under section 25(F) also it is stated as "workman". No distinction is made either in Sec. 25-F or in Sec. 2(s) between Casual worker and temporary worker and permanent worker. U|s 2(oo) retrenchment means the termination by the employer of the services of the workman for any reason whatsoever, otherwise that as punishment inflicted by way of disciplinary action. There also the word workman is used without any qualification. So casual labour is also a workman. Since the petitioner was terminated from his service not under the conditions of employment but on some other reasons it amounts to retrenchment. The fact that the petitioner worked more than 240 days in 12 months prior to the order of the termination is not disproved by the management with their records. Therefore, the order of the termination of the petitioner will amounts to only a retrenchment as defined under section2(oo) of the I.D. Act. Therefore, the respondent who failed to follow the procedure contemplated u|s 25-F before terminating the services of the petitioner for whatever rasons is illegal. It is admitted no notice was given before termination order, one month pay was given in lieu of notice and compensation as contemplated in Sub-Clause 25-F was also not paid. Therefore, the termination of the petitioner is violation of Section 25-F and therefore it is illegal.

In the result, an award is passed setting aside the order of dismissal dated 20-7-90 and directed the respondent to reinstate the petitioner in service without back wages. No costs.

Dated this 29th day of March 1996.

N. SUBRAMANIAN, Industrial Tribunal.

WITNESSES EXAMINED

For both sides : None

DOCUMENTS MARKED

For Workman :

Ex. W-1—20-7-90—Order of termination issued to the petitioner—workman Thiru D. Selvarajan (Xerox copy)

W-2 — —Termination order issued to the Petstioner-worker and 5 others (Xerox copy)

For Management :

Ex. M-1—Conditions of employment and its acceptance by the Petitioner-workman (Xerox copy)

नई दिल्ली, 8 मई, 1996

का.आ. 1558.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट, बम्बई को जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाए;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (छ) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/3/85-डी-1(ए)]

एच. सी. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 8th May, 1996

S.O. 1558.—Whereas the Central Government is satisfied that the public intertst requires that the Indian Government Mint.. Bombay which is epecified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017|3|85-D.I(A)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 मई, 1996

का.आ. 1559.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-6-1996 को उस तारीख के रूप में नियत करती है,

जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45) के सिवाय जो पहले ही प्रदत्त की जा चुकी है। और अध्याय-5, और अध्याय-6 [धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रदत्त की जा चुकी हैं] के उपबन्ध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	जिले का नाम
1.	खुदाकलां, जगाधरी रोड, अम्बाला छावनी	98	अम्बाला
2.	मंगलई, जगाधरी रोड, अम्बाला छावनी	129	अम्बाला

[संख्या : एस-38013/10/96-एस.एस-I]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 8th May, 1996

S.O. 1559.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st June, 1996 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana namely :—

S. No.	Name of Revenue Village	Had Bast No.	Name of Dist.ict
1.	Khuda Kalan, Jagadhri Rd., Ambala (Cantt.)	98	Ambala
2.	Manglhi, Jagadhri Road. Ambala (Cantt.)	129	Ambala

[No. S-38013/10/96-SS.I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 मई, 1996

का.आ. 1560.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में सरकार औद्योगिक अधिकरण, बीकानेर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7/5/96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/98/93-आई आर (डीयू)]

के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th May, 1996

S.O. 1560.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Bikaner as shown in the annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Posts and their workman, which was received by the Central Government on 7-5-96.

[No. L-40012/98/93-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

परिशिष्ट

औद्योगिक न्यायाधिकरण, बीकानेर

केन्द्रीय औद्योगिक विवाद प्रसंग सं. 3 सन् 1995

सत्यनारायण स्वामी पुत्र श्री रतनलाल स्वामी "टी मेकर" मार्फत अध्यक्ष, रेलवे कैज्युअल लेबर यूनियन, डागा स्कूल के पास, बीकानेर

—प्रार्थी/श्रमिक

बनाम

अधीक्षक, डाकघर बीकानेर डिवीजन, बीकानेर

—अप्रार्थी/नियोजक

रैफरेन्स अन्तर्गत धारा 10(1)(घ), औद्यो.वि. अधिनियम, 1947

न्यायाधीश—श्री तेगपाल सिहाग, आर.एच.जे.एस.

उपस्थिति :—

1. श्री भरतसिंह सेंगर, श्रमिक प्रतिनिधि
2. श्री मदनलाल श्रीमाली, नियोजक प्रतिनिधि

अधिनिर्णय

दिनांक, 9 जनवरी, 1996

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जिसे अब के पश्चात् सिर्फ "अधिनियम" कहा गया है, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक एल-40012/98/93-आई.आर. (डी.यू.) दिनांक 4-11-94 द्वारा प्रेषित इस रैफरेन्स के अन्तर्गत निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ पठाया था :

"क्या अधीक्षक, डाकघर बीकानेर डिवीजन, बीकानेर द्वारा श्री सत्यनारायण स्वामी पुत्र श्री रतनलाल स्वामी "टी मेकर" को उसके पद से हटाने का कृत्य न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कामगार किस मदद का हकदार है ?"

2. प्रार्थी सत्यनारायण जिसे अब के पश्चात् सिर्फ "श्रमिक" कहा गया है, की ओर से प्रस्तुत क्लेम विवरण के अनुसार संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उसकी नियुक्ति अप्रार्थी के यहां टी-मेकर के पद पर 22-12-86 को हुई थी, उसे जो वतन मिलता था वह भारत सरकार डाकघर से किया जाता था तथा वह कर्मचारी कैन्टीन के रखरखाव का कार्य करता था, सन् 1990 जनवरी से केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता तथा शहरी भत्ता भी दिया जाने लगा। श्रमिक का कहना है कि वह जिस कैन्टीन में कार्य करता था वह डाकघर की थी तथा कैन्टीन एक उद्योग की श्रेणी में आता है, उसने माह फरवरी 90 में अधीक्षक महोदय को नियमित किये

जाने का निवेदन किया और उसकी इसी मांग के कारण उसकी सेवा दिनांक 1-8-92 से बतौर "छंटनी" मौखिक रूप से समाप्त कर दी गई । उसने टर्मिनेशन निरस्त करने बाबत मौखिक रूप से कई बार निवेदन किया परन्तु नियोजक ने किसी प्रकार का विचार नही किया और उसके निवेदन करने पर अप्रार्थी अधीक्षक ने अपने कार्यालय से पत्र नं० एल० 1-51/93-94 दिनांक 26-8-93, 13-9-93 एवं 5-10-93 उसके नाम घर के ठिकाने से भिजवाये जिनकी पालना में वह अप्रार्थी के यहां हाजिर हुआ परन्तु अप्रार्थी ने कभी भी ड्यूटी पर नहीं लिया अंत में विवश होकर उसने अपना विवाद समझौता अधिकारी केन्द्रीय सरकार बीकानेर के यहां 22-12-92 को दायर किया जहां वार्ता हेतु समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) बीकानेर द्वारा वार्ता में उपस्थित होने हेतु दिनांक 31-12-92, 3-2-93, 26-2-93, 26-3-93, 28-4-93 तथा 17-5-93 को पत्र भेजे गये परन्तु नियोजक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा प्रेषित असफल वार्ता प्रतिवेदन के आधार पर यह विवाद न्यायालय में अधिनिर्णयार्थ आया है । अंत में श्रमिक ने इस सेवामुक्ति की छंटनी बताते हुए अधिनियम की धारा 25-एफ, 25-जी, 25-एच व नियम-77 के प्रावधानों के उल्लंघन में अवैध होने से सेवामुक्ति निरस्त कर सेवा पुनः बहाल होने और सेवामुक्ति अवधि का पूरा वेतन बैंक ब्याज दर सहित दिलाये जाने की प्रार्थना की है ।

3. अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में श्रमिक के उपरोक्त क्लेम विवरण में अंकित तथ्यों को मुख्य रूप से अस्वीकार करते हुए कहा है कि अधीक्षक डाकघर, अप्रार्थी ने उसे कभी भी "टी-मेकर" के पद पर नियुक्ति नहीं दी, न ही उनके अधीन "टी-मेकर" की कोई पोस्ट है, कैन्टीन के संचालन में उनका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है और ना ही उससे कार्यालय की अथवा कोई निजी सेवायें ली है, कैन्टीन उनके कार्यालय में नहीं थी, श्रमिकों को जो न्यूनतम राशि व सुविधायें दी जाती है वे सरकार के निर्धारित नियमानुसार दी जाती है । अप्रार्थी का यह भी कहना है कि उक्त "टीफन रूम" यानि कैन्टीन व्यवस्था न तो व्यापार है, न ट्रेड है और न यह किसी की निजी व्यवस्था है और न ही यह राज्य/केन्द्रीय सरकार की है तथा यह "उद्योग" नहीं होने के कारण यह प्रकरण इस अधिकरण में सुनने योग्य नहीं है क्योंकि यह विधि मंत्रालय के आदेश से धारा 2"जे" में वर्णित "उद्योग" से बाहर की गई है । अप्रार्थी का यह भी कहना है कि वह स्वयं कार्य छोड़कर चला गया बार-बार बलाने पर भी नहीं आया, अप्रार्थी ने उसे कार्य पर उपस्थित होने हेतु जरिये नोटिस ऑफर किया था पर वह कार्य पर नहीं लौटा और अप्रार्थी ने तो बार-बार कार्य पर उपस्थित होने का नोटिस भेजा था यदि उसे सेवा ही समाप्त करनी थी तो वह उसे कार्य पर लौटने के लिये नहीं बुलाता, श्रमिक स्वयं ने कार्य से एबन्डनमेन्ट किया है और अब वह अपने कृत्य को छुपाने के लिये काल्पनिक कहानी बनाकर असत्य कथन कर रहा है । अप्रार्थी नियोजक का यह भी कहना है कि वह प्रार्थी श्रमिक का नियोजक ही नहीं था इस कारण उसे समझौता वार्ता में उपस्थित होने की आवश्यकता नही थी इस प्रकार अप्रार्थी के अनुसार यह प्रकरण सेवा से अबन्डनमेण्ट का है रिट्रेन्चमेण्ट का नहीं है तथा प्रथमतः यह विवाद औद्योगिक विवाद के अस्तित्व में ही नहीं है न उसकी सेवा को किसी व्यक्ति ने मौखिक आदेश देकर सेवा समाप्त की । अप्रार्थी का यह भी कहना है कि उसके अलावा अन्य कोई पेड व्यक्ति कैन्टीन में था ही नहीं तब वरिष्ठता सूची बनाने की आवश्यकता नहीं थी, जब स्वयं ही बिना सूचना दिये कार्य छोड़कर चला गया तब सचिव को कैन्टीन की व्यवस्था करने में कठिनाई होनी अवश्यभावी थी इसी कारण अन्य व्यक्ति श्री अशोक कुमार को कार्य पर लगाया गया तथा अप्रार्थी के अनुसार श्रमिक सेवा छोड़कर गया तब से वह निरन्तर मजदूरी अर्जित करता है और वह बेरोजगार नहीं है । अप्रार्थी का यह भी कहना है कि डाकघर के कर्मचारियों के लिये जो वैलफेयर फण्ड होता है उसी फण्ड में से सबसीडी सरकार द्वारा निश्चित राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है और यह व्यवस्था डोमेस्टीक व्यवस्था का ही एक अंश है व इसमें श्रमिक की हैसियत डोमेस्टिक सर्वेन्ट की है अतः अधिनियम इस प्रकरण में लागू नहीं होता तथा सबसीडी की राशि का भुगतान सचिव को किया जाता है न कि सीधा श्रमिक को और सचिव द्वारा ही उसकी मजदूरी का भुगतान किया जाता था और उसी की देखरेख में वह टीफन रूम में कार्य करता था तथा अप्रार्थी से इसका किसी तरह का सीधा सम्बन्ध नहीं था । विशेष कथन के रूप में यह भी कहा है कि उसे पुनः सेवा में लिया जाना संभव नहीं है, नये विजेता सचिव को उसका नियोजक नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके कार्यकाल में उसने एक दिन भी कार्य नहीं किया है और न सचिव के पास ऐसा कोई फण्ड या वित्तीय साधन है जिससे वह श्रमिक को पिछले वेतन का भुगतान कर सके और रैफरैन्स विधि विरुद्ध है तथा वेलफेयर स्कीम के अन्तर्गत होने के कारण टीफन रूम उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है, न अप्रार्थी धारा 2 "जी" के अनुसार एम्प्लायर है न औद्योगिक विवाद है । अंत में श्रमिक का क्लेम खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

4. श्रमिक ने अपने क्लेम के समर्थन में अपना स्वयं का शपथपत्र पेश किया है जिससे नियोजक द्वारा जिरह की गई है और प्रदर्श डब्लू० 1 तथा 3 दस्तावेज पेश किये । इसके विपरीत अप्रार्थी की ओर से श्री बुलाकीदास, श्री के०डी० स्वामी व श्री आर०एस० गुप्ता के शपथपत्र पेश हुए हैं जिनसे श्रमिक द्वारा जिरह की गई है अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श एम-1 भी पेश किया गया है ।

5. बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया ।

6. निर्णय हेतु देखना है कि आया :

(1) अप्रार्थी इस श्रमिक का नियोजक नहीं है ? और, यह श्रमिक डाकघर के कर्मचारियों की

सुविधा के लिये उनके ही धन से संचालित टिफन रूम का कर्मचारी है जिसे टिफन रूम के सचिव ने नियुक्त किया था जिसका अप्रार्थी से कोई सम्बन्ध नहीं है जिससे प्रार्थी श्रमिक सत्य नारायण एवं अप्रार्थी—अधीक्षक डाकघर बीकानेर के मध्य "कर्मकार" व "नियोजक" का सम्बन्ध नहीं था ?

(2) क्या श्रमिक ने 240 दिवस कार्य कर लिया था और वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है ?

(3) क्या श्रमिक की सेवामुक्ति छटनी है जिस हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना न किये जाने से दूषित है ?

(4) श्रमिक क्या राहत पाने का अधिकारी है ?

बिन्दु सं० 1

7. श्रमिक ने स्वयं को टीफन रूम में "टी मेकर" के पद पर अप्रार्थी के अधीन नियुक्त किया जाना वर्णित किया है—इस टीफन रूम के सम्बन्ध में अप्रार्थी की ओर से दलील है कि यह न तो व्यापार है और न यह किसी की निजी व्यवस्था है और न ही केन्द्रीय/राज्य सरकार का है और यह उद्योग भी नहीं है इस कारण यह श्रमिक अप्रार्थी का नियोजित श्रमिक नहीं है । इस सम्बन्ध में श्रमिक ने अपने कलेम के समर्थन में स्वयं अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया है और जिरह में कहा है कि मुझे श्री जे०पी० गर्ग अधीक्षक, डाकघर ने नौकरी पर लगाया था, मैं डाकघर में चाय बनाने का काम करता था, वह जिरह में ही आगे यह भी कहता है कि यह बात सही है कि अधीक्षक ने मुझे पत्र लिखा हो कि आप अनुपस्थित है इसलिये नौकरी पर उपस्थित हो जावो—यह बात भी सही है कि वह स्थान तो टिफिन रूम ही था जिसकी देखभाल सेक्रेटरी और अधीक्षक दोनों ही करते थे, यह बात सही है कि वहां पर सचिव (सेक्रेटरी) का चुनाव होता है । जिरह में ही श्रमिक ने यह भी कहा है कि पहिले मुझे 323/- रुपये बाद में 750/- रुपये प्रतिमाह अधिक्षक महोदय की अनुमति से सचिव महोदय ही भुगतान करते थे । इसके विपरीत अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में बुलाकीदास ने भी जिरह में यह कहा है कि 750/- रु० मूल वेतन पर और जो महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों को देय है उतनी राशि मिलाकर सत्यनारायण को हर माह दिया जाता था लगभग 1400 या 1450 या 1350 या जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती थी उसे बढ़े हुए डी०ए० के अनुसार ही राशि दी जाती थी और उसे ही बतौर अनुदान के सत्य नारायण को भुगतान किया जाता था, बड़ी हुई राशि अकाअन्टेन्ट ही बताया करता था, वेलफेयर फंड से जो राशि मिलती थी वह 750/- रुपये पर जो भी महंगाई भत्ता नियमानुसार देय था वह ही मिलाकर उसे पूरी पूरी राशि सत्यनारायण को दी जाती थी । अप्रार्थी के दूसरे साक्षी के०टी० स्वामी ने जिरह में कहा है कि मैं तो सबसीडी स्वीकृति अधिकारी हूं, जिरह में ही इस साक्षी का यह भी कहना है कि यह कहना सही है कि सत्यनारायण को मैं अपनी जेब से पैसा नहीं देता था उसे पोस्ट आफिस के फंड जो कि सबसीडी टिफिन रूम के नाम से आता था और वह फंड टिफिन रूम के सेक्रेटरी को देते थे । हम विद्वान प्रतिनिधि अप्रार्थी के इस दलील से सहमत नहीं है कि अप्रार्थी और श्रमिक के मध्य "कर्मकार" व "नियोजक" का सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ था क्योंकि स्वयं अप्रार्थी अपने जवाब में ही यह कहकर आया है कि सचिव द्वारा ही श्रमिक को उसकी मजदूरी का भुगतान किया जाता था और सचिव की देखरेख में ही वह टिफिन रूम में कार्य करता था—डाकघर के अधीक्षक से इसका किसी तरह का सीधा सम्बन्ध नहीं था यानि अप्रत्यक्ष रूप से तो अप्रार्थी के ही अधीन संचालित उस "टिफिन रूम" अर्थात् "कैंटीन" में श्रमिक टी मेकर के पद पर कार्यरत था और उसे सबसिडी के रूप में सचिव के माध्यम से अप्रार्थी ही भुगतान करता था अगर ऐसा नहीं था तो सचिव को अधीक्षक से श्रमिक की अनुपस्थिति बाबत आग्रह करने और अप्रार्थी द्वारा सत्यनारायण को काम पर वापिस लौटने का ऑफर देने अथवा कोई पत्र लिखे जाने का औचित्य ही क्या था । विशेषकर अप्रार्थी के साक्षीगण ने यह स्वीकार भी किया है कि सबसीडी मिलती थी ऐसी स्थिति में जहां अप्रार्थी के अधीन कर्मचारियों के लिये टिफिन रूम चलाया जाता था जिसे सारी सुविधा प्राप्त है तो ऐसी कैन्टीन या टिफिन रूम नोन-स्टेट्यू रिकग्नाईज्ड कैण्टीन की परिभाषा में आ जाती है ऐसी सूरत पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्णीत किया जाता है कि श्रमिक अप्रार्थी के अधीन नियोजन में था और इस प्रकार उसके और अप्रार्थी के मध्य "कर्मकार" व "नियोजक" के सम्बन्ध स्थापित थे ।

बिन्दु सं० 2

8. जहां तक श्रमिक द्वारा एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर अवधि की सेवा पूरी करने का प्रश्न है—इस बारे में श्रमिक अपने क्लेम में सेवा में नियुक्ति दिनांक 22-12-86 से अप्रार्थी के यहां "टी मेकर" के पद पर होना बताते हुए यह भी प्रकट किया है कि उसके द्वारा नियमित करने की मांग के कारण उसकी सेवा बतौर छटनी मौखिक रूप से तारीख 1-8-92 से कर दी गई और वह लगातार 240 दिनों से अधिक कार्य करने के आधार पर "औद्योगिक कर्मकार" हो गया था—इस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र पर अप्रार्थी की ओर से कोई सुझावात्मक प्रश्न नहीं पूछा गया है या जिरह नहीं की गई है एवं इसके खण्डन में अप्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है कि वह लगातार अप्रार्थी के अधीन टिफिन रूम में कार्यरत नहीं रहा था।

9 विद्वान प्रतिनिधि नियोजक की इस दलील से हम सहमत नहीं है कि यह टिफिन रूम जो कि डाकघर के कर्मचारियों के लिये उनकी सुविधा के लिये सरकार द्वारा

मिलने वाली सबसीडी से चलाया जाता था उद्योग की परिभाषा में नहीं आता । मेरे विचार से यह टिफिन रूम उद्योग की परिभाषा में आता है और उसकी सेवा मुक्ति का विवाद अधिनियम की धारा 2 (क) में "औद्योगिक" विवाद की परिभाषा में आता है अतः इस प्रकरण पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील है । ऐसी सूरत में जबकि वह इस टिफिन रूम में 240 दिनों से अधिक की सेवा अवधि पूरी कर चुका था तो निश्चित रूप से वह इस अधिनियम की धारा 25—एफ एवं अन्य आज्ञापक प्रावधानों का संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था।

बिन्दु सं० 3

10. इस बिन्दु के अन्तर्गत देखना है कि क्या श्रमिक की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों की पालना न किये जाने से दूषित है ? सर्वप्रथम तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि श्रमिक की तथाकथित सेवामुक्ति अधिनियम की धारा 2(00) की परिधि में छंटनी है अथवा नहीं ? श्रमिक का तो सशपथ कथन है कि उसके द्वारा नियमित किये जाने की मांग फरवरी 90 में करने के कारण अप्रार्थी ने उसे मौखिक रूप से हटाया था। अप्रार्थी की ओर से जिरह करने पर भी उसने कहा है कि मुझे के० डी० स्वामी अधीक्षक डाकघर ने हटाया था, मुझे कहा था कि कि सैक्शन नहीं आई है और काम भी नहीं है हम कैन्टीन बन्द कर रहे हैं और कहा कि काम पर मत आना, उसने अप्रार्थी की ओर से दिये गये सुझाव को गलत बताते हुए कहा है कि वह स्वयं काम छोड़कर चला गया हो । आगे जिरह में ही वह यह भी कहता है कि यह बात सही है कि अधीक्षक ने मुझे पत्र लिखा कि आप अनुपस्थित है इसलिये नौकरी पर उपस्थित हो जाओ परन्तु उसने अप्रार्थी के इस सुझाव को गलत बताया है कि वह ड्यूटी पर वापिस नहीं आया हो, वह तो पत्र पाते ही नौकरी पर उपस्थित हो गया था । इसके विपरीत अप्रार्थी की ओर से साक्षी गुलाकीदास, कैंटीन मे सचिव ने अपने शपथपत्र में यह अंकित किया है कि श्रमिक के कार्य की देखरेख सचिव होने के कारण मेरी रहती थी, श्रमिक ने मेरी बिना अनुमति लिये ही और बिना सूचना के ही अपने कार्य से दिनांक 1-8-92 से अनुपस्थित हो गया जिससे कर्मचारियों ने टिफन रूप की व्यवस्था न हो पाने व चाय उपलब्ध न होने की शिकायत की थी जिस पर मैंने तत्कालीन अधीक्षक श्री के० डी० स्वामी से बात की इस पर उन्होंने श्री अशोक कुमार को सेवा लेने की वैकल्पिक व्यवस्था का निर्देश दिया । अप्रार्थी का यह साक्षी यह भी कहता है कि श्रमिक को न तो मैंने सेवा से निकाला न ही तत्कालीन अधीक्षक श्री के० डी० स्वामी ने सेवा से हटाया था । अप्रार्थी का यह साक्षी यह भी कहता है कि वह उसके घर पर उसे लेने के लिये गया था लेकिन उसने काम पर आने से मना कर दिया और कहा कि मैं अब टिफिन रूम का कार्य नहीं करना चाहता इस पर साक्षी ने उसे चार्ज संभालने व एडवान्स मनी 200/- रु० लौटाने का कहा जिस पर श्रमिक ने कार्यालय में 4-8-92 को आकर चार्ज दे दिया, अप्रार्थी ने इस चार्ज देने की सूचि प्रदर्श एम-1 को भी प्रमाणित किया है । आगे शपथपत्र में ही वह यह भी कहता है कि श्रमिक टिफिन रूम की नौकरी छोड़ने के बाद कचोड़ी बनाने व बेचने का काम धंधा करता था व कुछ दिनों तक बिजली फिटिंग का काम धन्धा करता था या कुछ दिनों तक टैम्पो चलाने का कार्य करते हुए भी देखा गया था और वह समझाने पर भी नहीं माना । इस संबंध में जिरह करने पर वह कहता है कि जब श्रमिक बुलाने पर नहीं आया तो इसकी रिपोर्ट उसने अधीक्षक को की थी । परन्तु अप्रार्थी की ओर से ऐसी कोई रिपोर्ट जो महत्वपूर्ण हो सकती थी न्यायालय में पेश कर प्रमाणित नहीं की गई है जिसके अभाव में अप्रार्थी के इस साक्षी के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि श्रमिक स्वयं 1-8-92 को काम छोड़कर चला गया । ऐसी सूरत में हम विद्वान प्रतिनेधि नियोजक की इस दलील से सहमत नहीं है कि श्रमिक स्वयं ने सेवा का एबन्डनमेंट कर दिया था इस कारण उसको सेवा मुक्ति अधिनियम की धारा 2(00) में छंटनी की परिधि में नहीं आती—ऐसी सूरत में विशेषकर जबकि श्रमिक ने सेवा मुक्ति के कुछ दिनों पश्चात् ही इस सेवा मुक्ति का विवाद समझौता अधिकारी के यहां उठा दिया था—उसके इस आचरण से ही प्रकट है कि वह सेवा करना चाहता था अतः उसके द्वारा मात्र चार्ज दे देने जो कि श्रमिक के अनुसार उसके अप्रार्थी के अधिकारी श्री के०डी० स्वामी स्वयं अधीक्षक के कहने से दिया था, से उसके द्वारा सेवा से स्वयं अपनी इच्छा से अनुपस्थित हो जाना नहीं माना जा सकता । यद्यपि अप्रार्थी की ओर से श्री के० डी० स्वामी ने अपना शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें उसने श्रमिक के इस शपथ कथन को गलत बताया है परन्तु केस की सभी परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त मेरे विचार से इस श्रमिक की सेवा मुक्ति अधिनियम की धारा 2(00) के अधीन वर्णित किन्हीं अपवादों में नहीं आने के फलस्वरूप छटनी की परिधि में आती है और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह भलीभांति प्रमाणित है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति अधिनियम की धारा 25—एफ एवं 25—एच के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई थी जो कि श्रमिक की छंटनी से पूर्व अप्रार्थी के लिए करना कानूनन अनिवार्य था जो नहीं किये जाने से उसकी सेवामुक्ति निश्चित रूप से दूषित है क्योंकि सेवा मुक्ति के दिनांक तक एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिनों से अधिक की सेवा पूरी कर चुका था ।

बिन्दु सं० 4

11. अब प्रश्न आता है कि श्रमिक क्या राहत प्राप्त करने का अधिकारी है, विधि अनुसार तो अधिनियम की धारा 25—एफ के आज्ञापक, प्रावधानों की पालना किये बिना की गई सेवा मुक्ति प्रारंभ से ही शून्य व अप्रभावी है और श्रमिक पूर्ववत अप्रार्थी के अधीन सेवा की निरन्तरता के साथ साथ क्या पिछला वेतन भी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में विद्वान प्रतिनिधि नियोजक की ओर से मुख्य रूप से दलील थी कि कैण्टीन के सचिव के पास ऐसा कोई फण्ड या वित्तीय साधन नहीं है जिसके माध्यम से वह श्रमिक

के पिछले वेतन का भुगतान कर सके। और उनके यहां "टी मेकर" का कोई पद भी नहीं है अतः उसे सेवा में पुनः बहाल किया जाना और पिछला वेतन दिलाया जाना न्यायोचित नहीं है। हम उनकी इस दलील से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि "टी मेकर" का कोई पद नहीं है क्योंकि अप्रार्थी के सभी साक्षीगण द्वारा इस बात की स्वीकार भी किया गया है कि उसके न आने के कारण किसी अशोक कुमार को टी मेकर के पद पर नियुक्त किया जा चुका है। अतः श्रमिक की सेवामुक्ति अधिनियम की धारा 25-एफ एवं 25-एच के उल्लंघन में होने के फलस्वरूप निरस्तनीय है और श्रमिक अप्रार्थी के नियोजन में सेवा को निरन्तरता के लाभ सहित पुनः बहाल होने का अधिकारी है।

12. अब प्रश्न आता है कि क्या सेवा मुक्ति अवधि में श्रमिक को पिछला वेतन दिलाया जाना न्यायसंगत होगा। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तथाकथित टिफिन रूम जो सरकार से मिलने वाली सबसीडी से संचालित था, को ध्यान में रखते हुए और यह उपधारणा लेते हुए कि श्रमिक सेवा मुक्ति की अवधि में अप्रार्थी के अधीन चाय बनाने का काम करने वाला यह श्रमिक कुछ न कुछ कार्य करके आय अर्जित करता ही होगा यद्यपि इसके बारे में अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है परन्तु केस की सभी परिस्थितियों को विचार करने के उपरान्त मेरे विचार से इस श्रमिक को सेवा मुक्ति अवधि में सेवा मुक्ति दिनांक 1-8-92 से आज निर्णय दिनांक के बीच की अवधि में पिछले वेतन के रूप में मात्र 2,000/- रुपये (रुपये दो हजार मात्र) ही दिलाना उचित एवं न्यायसंगत है तथा आज निर्णय दिनांक के सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की अवधि में देय नियमानुसार पूरा वेतन भी वह प्राप्त करने का अधिकारी है।

13. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित इस रिफरेन्स के संबंध में निम्न प्रकार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :

> अधीक्षक डाकघर बीकानेर डिविजन, बीकानेर द्वारा श्री सत्यनारायण स्वामी पुत्र श्री रतनलाल स्वामी "टी मेकर" को उसके पद से हटाने का कृत्य न्यायोचित नहीं है परिणामतः वह अप्रार्थी के नियोजन में पूर्ववत पद व वेतन पर पुनः बहाल होने और सेवा मुक्ति दिनांक 1-8-92 से आज निर्णय दिनांक 9-1-96 के बीच की अवधि में देय वेतन स्वरूप मात्र दो हजार रुपये एवं आज निर्णय दिनांक से सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की अवधि में देय नियमानुसार पूरा वेतन प्राप्त करने की मदद का अधिकारी है।

उक्त अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ पठाया जाये।

तेजपाल सिंहाग, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 9 मई, 1996

का०आ० 1561.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि सीमेंट उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 3 के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवायें घोषित किया जाना चाहिए।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/13/85-डी-1(ए)]

एच०सी० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 9th May, 1996

S.O. 1561.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Cement Industry which are covered by entry 3 in the First Schedule to the industrial dispute Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purpose of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/13/85-D.I(A)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 मई, 1996

का०आ० 1562 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या-एल-12012/255/92-आई आर (बी-2)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th May, 1996

S.O. 1562.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal 2 Mumbai as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management Bank of of India and their workmen, which was received by the Central Government on 2-5-1996.

[No. L-12012/255/92-IR(B.II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT :

Shri S.B. PANSE, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/62 of 1962

Employer in relation to the management of Bank of India.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the workmen : Shri M.B. Anchan, Advocate.

For the employer : Shri L. L. D'Souza, Representative, Mumbai, dated 29th March, 1996

AWARD-PART-I

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-12012/255/92-IR(B.II) dated 30-10-1992 had referred to the following industrial dispute for adjudication.

"Whether the action of the management of Bank of India, Sachapir Street Saving Branch, Pune in dismissing Shri M. Y. Bandal, accounts clerk, from service is justified ? If not to what relief is the workman entitled to ?"

2. Maruti Yeshwant Bandal the worker joined the banks services as sub-staff on 2-10-78 at its Pune (Main Branch). On promotion in the clerical cadre he was posted at Fergusson Road Branch at Pune (Main) Branch. Later on he was transferred to Sachapir Street (Savings) branch w.e.f. 25th March, 1985. The workman contended that his dismissal order is illegal and unjustified. He submitted that the domestic inquiry which was held against him was again the Principles of Natural Justice, for the following reasons. It is averred that the charge was in English which he could not follow. He asked for its Marathi translation, but it was not given to him. It is pleaded that the inquiry was conducted in English which he could not follow. It is averred that he was not given an opportunity to give his say to the charges. It is submitted that the inquiry officer did not explain the procedure which he was to adopt for the inquiry. He asserted that the copies of the documents were not given to him on 7-9-90 but they were given on 14-9-90. He further pleaded that he was not mentally fit and the medical certificates which he produced before the inquiry officer were not accepted. Then he sent them to the regional manager.

3. It is pleaded that the findings of the inquiry officer are baseless and perverse. The workman asserted that he asked for fresh inquiry in the matter which was not considered by the disciplinary authority. It is therefore contended that the procedure contemplated under the Bi-partied settlement for the domestic inquiry was not followed. For all these reasons it is submitted that the dismissal order may be set aside and he may be reinstated in service with full back wages with other reliefs.

4. The management resisted the claim by the written statement Exhibit-'3'. It is denied that the domestic inquiry was against the principles of Natural Justice. It is submitted that the charge was explained to the worker in Marathi. He admitted that he followed the same and thereafter pleaded guilty of the said charge. It is averred that the copies of the documents were given to the workman and the original were shown to him on the next date. On the basis of the documents and the admission of guilty by the workman the inquiry office submitted his report. It is denied that the findings of the inquiry officer are perveser and illegal.

5. The management contended that the workman was given a show cause notice so far as the proposed punishment is concerned. He was given personal hearing. He was also asked if he wants to be represented through adovcate. It is denied that the inquiry officer to receive the medical certificate produced by the workman. It is averred that the punishment imposed on the workman is just legal and proper. It is prayed that under such circumstances the reference may be answered in favour of the management.

6. My Learned Predecessor framed issues at Exhibit-'4'. It is agreed that issues No. 1 & 2 are to be tried as preliminary issues. The issues and my findings thereon are as follows :

Issues	Findings
1. Whether the inquiry held against the workman was not held properly and the rules of natural justice were not followed ?	The inquiry was just and proper
2. Whether the findings of the Inquiry officer are perverse ?	No

REASONS

7. It is not in dispute that the workman was initially appointed as a subordinate staff (peon) by the Bank of India, at Pune Branch on 1-2-1973. He was confirmed in the said capacity on 2-10-78. He was promoted as a clerk in 1981 and transferred to Sachapir Street (Savings) Branch. When he was working there he was suspended on 30-7-87. A chargesheet 21-7-1990 was served on him on 30-7-1990.

8. In short the charges (Ex-5|5) against the worker were as (a) Engaging in any trade or a business out side the scope of his duties except with the written permission of the bank; (b) doing any act prejudicial to the interest of the bank for appropriating the fraud on the bank to the tune of Rs. 81,427. The details of charge which I need not mention it here. But it is the fact that he chargesheet runs in to nine pages. It is in English. It is tried to argut on behalf of the workman that it is a clumsy chargesheet and the worker is put to difficulties. It can be seen that the bilateral settlement provides for suspension during the investigation. It is the case of the bank that the worker was suspended during the investigation and after completion of the investigation a chargesheet was given. It cannot be said that it is not detailed chargesheet. Even for the sake of argument it is said that the investigation was completed at an earlier date even then the delay for issuing the chargesheet cannot be simplicitor said to be prejudicial to the worker. The worker has to show how the prejudice is caused to him. There is no record to that effect.

9. The second contention so far as the workman is concerned that the chargesheet was in English. He could not follow the same. Therefore he wrote a letter dtd. 1-9-90 to the management that the Marathi translation of the chargeshcet should be supplied to him. This is not in dispute. But what is to be seen that what happended later on. The inquiry was conducted on 7-9-1990. That was the first date of the inquiry. Surayakant Vinayak Joshi (Ex-10) the inquiry officer Suresh Prabhakar (Ex-11) the presenting officer and also the worker Maruti Yeshwant Bandal (Ex-8) corroborates each other and affirmed that on the first date of he thearing he workman was asked whether he followed the charge or not. He replied in the negative. Thereafter on his request the chargesheet was translated in Mafathi and explained to him whatever portion he did not follow. Ex-"5|3" are the inquiry proceedings. Page No. 15 is very relevant to this aspect. From perusal of this it can be seen that the chargesheet was translated in to Merathi and explained to the worker. He followed the same and had signed the proceedings to that effect. I therefore, find that there is no substance in the contention of the worker that he was not given the translation of the chargesheet in Marathi and he did not follow the same.

10. The next contention which was taken by the workman was that the inquiry proceeding was in English and he did not follow the same. This argument is with out merit. It is because on the first date of the inquiry i.e. on 7-9-1990 the workman pleaded guilty to the charges.

In other words he accepted the charges to be true. Therefore, there was nothing to be done on the subsequent days. No depositions were recorded of the witnesses. On that day the list of documents and photo copies of the documents were produced on the record and they were given to the worker. It appears from the record and from the testimony of the witness that the original were produced and shown to the worker on 14-9-90 which he accepted to be correct. It is not the case that the workman asked for time for perusal of the documents or that he asked for time for considering the charge which was explained to him in Marathi. Therefore, the contention of the workman that the proceedings were in English and it cased prejudice to him has no merit.

11. It is also the contention of the workman that the proceedings were hurriedly completed. This is without any basis. When the workman pleaded guilty there was nothing remained for the management to do in the matter. Therefore, there was no question of inquiry officer conducting the inquiry hurriedly.

12. It is tried to argue on behalf of the workman, that he was not knowing the procedure in respect of the departmental inquiry and it was not explained to him. This is denied by the inquiry officer. According to him, it is explained in the covering letter sent to the workman. It is admitted position that the workman received latter (Ex-5|2) i.e. the chargesheet dated 21-7-1990. In this letter the procedure which is contemplated in the bi-partied settlement is innumerated. Sub-para 4 of Pragraph-3 clearly speaks that the workman if chooses can represent his case through the office bearer of the union or the next friends. No doubt the inquiry officer had not put the question to the workman whether he is represented by anybody. But that offer even is said to be not offered cannot be said to be a prejudicial one. It is not the case of the workman that even though he wanted to be represented through the Office bearer of the Union on through the advocate he was not allowed to do so by the management. From the proceeding it can be seen that when the matter was before the disciplinary authority the workman was given chances to be heard through advocate which he did. Therefore, it cannot be said that the workman was not aware of the procedure nor that he was not given an opportunity.

13. The Learned advocate for the management argued that the workman after fully understanding the charges accepted the same (Ex.-5/7). Suryakant Joshi and Suresh Prabhakar affirmed to that effect. The workman had not disputed the same. It is not the case of the workman that by using undue infulence his admission was recorded. It can be further seen that apart from the admission which he gave before the inquiry officer in the subsequent representation and explanation to the management the worker accepted the guilt. At Exhibit-'5|33' which is a reply to the banks letter dtd. 27-11-90 it was a show cause notice to the workman why the punishment of dismissal should not be confirmed. He had categorically said that the does not know how he committed the mistake. He had stated that the position that he withdrawn the amount cannot be changed. For all these reasons it is tried to argue on behalf of the management that on the first date the inquiry was over. Even if there is some lacunae, no prejudice is caused to worker to bolster up this proposition the management placed reliance on authorities.

14. The Central Bank of India Ltd. V. Karunamoy Banerjee 62 F.J.R. 481. Their Lordships observed that if the allegations are denied then only the management is required to examine the witness to prove the same and submit the witness for cross-examination for the workman. If, however, the workman admits his guilty there will be nothing more for the employer to enquire into and it will be an empty formality to insist upon the employer to let in evidence about the allegations.

15. In another case i.e. Hindustan Aeronautics Limited v. B. Gulab Singh and Ors. 68 F.J.R. 132 his Lordships observed the position in law is that if the workman against whom the disciplinary proceedings are initiated for acts of misconduct admits his guilt there is no necessity for the employer of hold any domestic inquiry. The same principle is laid down in Hindustan Aeronautics Ltd. V. Shanmugam & Anr. 1992 II L.L.J. 265.

16. From the inquiry proceedings the admission of the guilt of the workman cannot be said to be a conditional one. He had given explanation how he committed the misconduct. In K. Venkateswarlu V. Nagarjuna Grameena Bank and Anr. 1995 II L.L.J. 492. Their Lordships have observed in disciplinary proceedings is deliquent admits the charges or makes an unconditional and unqualified admissions there is nothing to be done by way of departmental inquiry and it cannot be argued that the procedure of departmental inquiry should have been applied not withstanding such admission or confession. When admission made by the delinquent shows that he had committed the misconduct then the question of violation of principles of natural justice cannot have any relevance.

17. There is another contention on behalf of the workman that he was mentally ill when the Acts stated in the chargesheet were committed by him and when the inquiry was conducted against him. It is argued on behalf of the management that this is an after thought. The acts alleged to have committed by the workman are between the period 30th September, 1986 to 20th October, 1986. In respect of charge No. 2 and from 27-2-87 to 21-4-87 in respect of charge No. 2. There is a certificate produced by the workman from Dr. Kelkar Dtd. 3-9-1990 at Exhibit-'5|38'. In the said certificate it is tried to show that he was under treatment for two periods i.e. from 18-9-86 to 6-11-86 and from 24-2-1987 to 21-5-1987. The workman had not examined the doctor or prove the genuiness of the certificate or its contents. In Petlad Turkey Red Dye Works Co., Ltd. V. Dyes and Chemical workers Union and Ors. 20 F.J.R. 539. Thein Lordships observed that if the person has to prove that he was ill on a particular date the mere filing of a certificate of a medical man that he was ill is not accepted as the evidence to show that he was ill. The correctness of the statement made in the certificate has to be proved by the affidavit or by some other evidence. It is argued on behalf of the management that under such circumstances the certificate issued in the year 1990 for the allege sickness of the year 1986-87 without having any record of the doctor such as case papers etc. has no meaning. I accept this contention.

18. It is tried to argue on behalf of the management that having produced the workmans medical reimbursement form for the year 1986—1990 which relates to other sickness of his family members but there is no medical reimbursement form showing that he was mentally sick and for that he spend some amount and submitted the forms for reimbursement. His leave applications also do not speak that he had taken the leave for mental sickness. All these circumstances go to show that the workman was not mentally sick when the alleged misconducts were committed or when the domestic inquiry was conducted. It can be further seen that in the statement of claim these pleas are now raised by him. It is argued on behalf of the management that the workman failed to prove that he submitted any medical certificate on 7th and 14th September 1990 before the inquiry officer for consideration. Therefore, they were not considered by the inquiry officer.

19. It can be seen that the report of the inquiry officer is based on the admission of the workman and the documents on the record. There is no evidence to show that how the findings of the inquiry officer are perverse. For all these reasons I record my findings on the issues accordingly and pass the following Order :

ORDER

1. The inquiry held against the workman was proper and the rules of Natural Justice were followed.
2. The findings of the inquiry officer are not perverse.

S. B. PANSE, Presiding Officer

29-3-1996.

नई दिल्ली, 9 मई, 1996

का०आ० 1563 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इण्डियन ओवरसिस बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-5-96 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या—L-12011/2/93-आई आर (बी-2)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th May, 1996

S.O. 1563.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Overseas Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 2-5-96.

[No. L-12011/2/93-IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU MADRAS

Friday, 29th day of March, 1996

PRESENT :

Thiru N. Subramanian, B.A., B.L., Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 81 of 1993

[In the matter of the dsspute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of Indian Overseas Bank, Madras-2]

BETWEEN

The workmen represented by

The General Secretary,
All India Overseas Bank Employees Union,
P.B. No. 5231/763, Anna Salai, Madras-600002.

AND

The Chairman and Managing Director,
Indian Overseas Bank,
762, Anna Salai, Madras-600002.

REFERENCE :

Order No. L-12011/2/93-IR(B-II), dated 16-8-1993, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for trial hearing on Wednesday, the 6th day of March, 1996 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru. R. Arumugam for Thiruvalaragal Aiyer and Dolia, Advocates appearing for the workmen and of Thiruvalaragal S. Kanniah and K. Selvaraj, advocates appearing for the management, and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :—

AWARD

The Government of India by its letter No. 12011/2/93-IR (B-II) dated 16-8-93 referred for adjudication before this Tribunal u/s 10(1)(d) of the I.D. Act regarding the dispute "whether the action of the management of the Indian Overseas Bank in discontinuing the practice of including increments for the purpose of calculating the subsistence allowance during suspension period in respect of their workmen is justified. If not; to what relief they are entitled ?

2. The case of the petitioner is as follows : The service conditions of the members of the petitioner union are governed by bank awards as modified by the various Bi-partite settlements. Para 557 of Sastry Award reads :

"1. For the first three months one-third of the pay and allowance which the workman would have got but for the suspension.

2. Thereafter where the enquiry is departmental by the Bank, one half of the pay and allowances for the succeeding months. Where the enquiry is by an outside agency, one-third of the pay and allowances for the next three months and thereafter one half for the succeeding months until the enquiry is over."

In the Bi-partite settlement dated 8-9-83 para 557 of Sastry Award as endorsed by para 17.14 of the Desai Award partially modified as under :

Whereas the investigation is not entrusted to or taken up by an outside agency subsistence allowance will be payable of the following rates :

"1. For the first 3 months 1/3 of the pay and allowance which the workman would have got but for the suspension.

2. Thereafter 1/2 of the pay and allowances.

3. After one year full pay and allowance if the enquiry is not delayed for the reason attibutable to the concerned workman or any of his representatives."

The subsistence allowance should be paid by taking into account the increments, which fall due during the period of suspension. Therefore the workmen are entitled to get increment reckoned for calculating subsistence allowance, as a matter of course even during the period of suspension. The respondent bank had been paying subsistence allowance accordingly till 1988. Subsequently, the respondent bank decided that increments which fall due during the period of suspension should not be included for calculation of subsistence allowance. They issued a circular dated 21-1-1988 to all its offices to discontinue the inclusion of increments for the purpose of calculating subsistence allowance during the period of suspension. Inclusion of increment has been part of service condition of its members. Even assuming without admitting it was only a practice but does not have sanction of the Awards and settlement. This practice and custom and usage have been for a period of over 35 years. The respondent bank have no authority or right to alter such practice to the detriment of the petitioner union and its members. Even assuming that the respondents have right to alter or change the service conditions due notice u/s 9-A of the I. D. Act ought to have been issued. The respondents have committed unfair labour practice. Hence it is prayed the Tribunal pleased to pass award directing the respondent to continue to include the increments for the purpose of calculating subsistence allowances during the suspension period.

5. The respondent bank filed its counter contending that the wording of the clause pertaining to payment of subsistence allowance both Sastry and Desai award viz. the pay and allowance which the workmen would have got but for the suspension cannot be liberally interpreted to conclude annual increment. It is provided in clause 521(2)(c) of Shastri Award that if the workman is acquitted finally "he shall be deemed to have been ON DUTY during the period of suspension if any and shall be entitled to full pay and allowance as has got increment reckoned for calculating subsistence allowance sion." The workmen under suspension are not entitled to as a matter of course. Increment is an incident of employs as a matter of course. Increment is an incidence of employment and employee gets an increment by working full year and drawing full salary. During the period of suspension the contract of service remains suspended. So employees

are not entitled to increment during the period eventhough the relationship of masters and servants continues. After the conclusion of the enquiry if it is decided not to take action against the workman he shall be deemed to have been 'on duty and shall be entitled to get wages and allowances and all other privileges including increments. The respondent for the past had mistakenly taken into account the increment which fall due during the period of suspension for calculating subsistence allowance payable by an incorrect interpretation of the relevant provision of the award and the same will not in any way create a right on the petitioner. Recently the High Court of Jammu and Kashmir has taken a view holding that the suspended employee is not entitled to increment during the period of suspension. Hence the petitioner union cannot claim enhanced subsistence allowance on the plea that the increment became due during the period of suspension. The right to claim benefit of increment can be decided only if he is ultimately reinstated. The averments that the inclusion of increment for the purpose of calculating subsistence allowance as a part of service condition is unsustainable. The petitioners are not entitled to have any notice u/s 9-A of I.D. Act. The petitioner filed a Writ Petition in W.P. No. 3080/88 before our High Court challenging the circular dated 21-1-1988 and the same was dismissed on 7-1-1992 as withdrawn. This will constitute resjudicata. Hence the claim of the petitioner may be dismissed with costs.

6. No documents filed on either side of the parties.

7. The point for consideration is "Whether the action of the Management of Indian Overseas Bank in discontinuing the practice of including increments for the purpose of calculating the subsistence allowance during suspension period in respect of their workmen is justified. If not, to what relief they are entitled ?

8. Point : The petitioner Union claims that the respondent bank after 1988 discontinued the practice of including the increment which fall during the period of suspension of an employee for the purpose of calculating subsistence allowance is not justified and illegal. Admittedly, prior to 1988, the increment which fall due during the period of suspension was included for calculating the subsistence allowance. Subsequently the respondent bank issued a circular on 21-8-88 disallowing inclusion of increment fall due during the period of suspension of calculating subsistence allowance. The petitioner's counsel relied on 2 awards viz. Desai Award and Shastry Award. In Desai Award clause 557 provides for payment of subsistence allowance. In clause 557 for the first 3 months 1/3 of the pay and allowance which the workman would have got but for the suspension. No. 2. Thereafter where the enquiry is departmental by the Bank, one half of the pay and allowances for the succeeding months. Where the enquiry is by an outside agency, one-third of the pay and allowances for the next three months and thereafter one-half for the succeeding months until the enquiry is over."

9. In Desai Award very same provision is endorsed for payment of subsistence allowance during the period of suspension. In settlement dated 8-9-83 also subsistence allowance payable for the first 3 months 1/3 pay and allowance which the workman would have got for the suspension. Thereafter 1/2 of the pay and allowances. After one year full pay and allowances if the enquiry is not delayed for reasons attributable to the concerned workman or any of his representatives. So it is argued by the petitioner's counsel the suspended workman is entitled to percentage from his pay and allowance as subsistence allowance during the period of suspension. Every workman is entitled to yearly increment. If the increment falls due during the period of suspension it has been taken into account for calculating subsistence allowance. According to the Respondent as per awards and the settlement the subsistence allowance is payable only from pay and allowance payable to the workman but for the suspension. Increment is not an allowance like Dearness Allowance, House Rent Allowance and City Compensatory Allowance. Increment is not a matter of right to claim, the workman has to earn by working. Therefore increment which falls due during the period of suspension cannot be included for calculating a subsistence allowance. The respondent's counsel relied on a decision of our High Court reported in 1995-II LLN 1084. Our High Court has held :

"It may be pointed out that the object of granting subsistence allowance is to enable the petitioner to subsist and to participate and defend himself in the disciplinary proceedings. The increments are to be given normally to an employee who regularly performs his duties. As the petitioner has been under suspension, the question of giving the benefit of increments does not arise. Moreover the increment does not automatically follows. Therefore an employee under suspension is not entitled to annual increment during the period of suspension. In a case reported in 1992 II LLJ page 723 the High Court of Jammu and Kashmir has held :

"Suspended employee is not entitled to increment during the period of suspension and hence he cannot claim enhanced subsistence allowance on the increment on the plea that the increment became due during the suspension period." So from the decision cited above, it is very clear that increment is not a matter of right to be given to the employees and the suspended employee is not entitled to any increment during the period of suspension and he cannot claim enhanced subsistence allowance, on the plea that increment became due during the suspension period. Therefore, the claim of the petitioner Union to include the increment which falls due during the period of suspension for calculating subsistence allowance is not justified. On the other hand, discontinuance of practice of the respondent including increment falls due during the period of suspension for calculating the subsistence allowance is justified.

In the result, an award is passed justifying the action of the management in discontinuing the practice of including annual increment falls due during the period of suspension in calculating the subsistence allowance. No costs.
Dated, this the 29th day of March, 1996.

N. SUBRAMANIAN, Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For both sides : None.

DOCUMENTS MARKED

For both sides : Nil.

नई दिल्ली, 10 मई, 1996

का०आ० 1564.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/180/92-आई आर(बी)]

पी०जे० मकईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th May, 1996

S.O. 1564.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SBI and their workman, which was received by the Central Government on the 9-5-1996.

[No. L-12012/180/92-IR(B)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI

I. D. No. 16/93

In the matter of dispute between :

Shri Ravi Seth,
Janta Deposit Collector through General Secretary,
State Bank of India Staff Association,
2124/2, Hari Singh Nalwa Street No. 58,
Karol Bagh,
New Delhi-110005.

Versus

Deputy General Manager,
State Bank of India,
Zonal Office,
11, Sansad Marg,
New Delhi-110001.

APPEARANCES :

None for the workman.
Shri Pawan Kumar for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/180/92-I.R.(B-3) dated 5-2-93 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether Shri Ravi Seth, Janta Deposit Collector, is a workman of State Bank of India ? If so, whether the action of the management of State Bank of India in terminating his services w.e.f. 10-1-90 is legal and justified ? If not, to what relief Shri Ravi Seth is entitled to ?"

2. The applicant in statement of claim has alleged that the workman was working as Janta Deposit Collector at Fountain Branch of the State Bank of India since 2-2-80. He was appointed on the said job following agreement between Bank and the workman. Deposit mobilisation is one of the Chief Functions of the Bank as part of Deposit Schemes. The workman after collecting deposit from door to door from the customers are required to deposit money very next date in the bank branch. He used to complete all record concerning this deposit. He used to be paid commission from the management on the basis of the amounts collected by him. According to the workman he was employed by the management and on 30-10-88 Manager of the bank asked the workman to pay Rs. 5000 out of the commission amount whatever the workman had recejved from the Bank. The Branch Manager also told the workman that all other Janta Depositors are paying 10 per cent of the total commission whatever they received from the Bank. The workman refused to do so and on 10-1-90 the management decided not to utilise the services of the workman as Janta Deposit Collector. The act of the management was illegal and hence this dispute.

3. The Management in its written statement alleged that the dispute of the workman was misconceived, untenable and bad in law. There was no relationship of master and servant between the parties nor that of employer and employee. The workman had committed fraud and the management being a financial institution could not afford to have its agents committing irregularities. The Agency was terminated as per the agreement and there was no question of payment of any retrenchment compensation, etc. under the I.D. Act.

4. The Management examined Shri M. L. Gulati MW1 and the workman did not appear and was proceeded against exparte.

5. I have heard representative for the management and have gone through the record. On perusal of the evidence produced by the Management I am satisfied that Shri Ravi Seth is not a workman as defined under the I.D. Act. He was an Agent of the management making collections for it and the question of termination of his service does not arise. There was a lot of difference between master and agent and employer and employee. A master could terminate the services of his agent any time and the forum for going through the dispute was not the Industrial Tribunal but any other Agency, I am of the view that in this case the Management has done nothing illegal and the termination of Shri Ravi Seth was fully justified on the basis of the allegations made in the written statement and the facts of the case. Moreover, the workman Ravi Seth has himself not come into the witness box nor his representative to show any illegality in the entire matter. Parties are however, left to bear their own costs.

15th April, 1996.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मई, 1996

का०आ० 1565.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार नार्थ इस्टर्न रेलवे के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-5-96 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-41012/89/94-आई आर बी आई]

पी०जे० माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th May, 1996

S.O. 1565.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of N. Eastern Rly. and their workman, which was received by the Central Government on the 9-5-96.

[No. L-41012/89/94-IRBI]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT DEOKI PLACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 94 of 1995

Shri Gauri Shanker
C/o B. D. Tiwari
96/196 Roshan Bajaj Lane
Ganesh Ganj, Lucknow.

AND

Divsional Electrical Engineer
N.E. Railway (Workshop)
Izatnagar, Bareilly.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-41012|89|94 dated 19-7-95, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of N.E. Rly. Bareilly in termination the service of Shri Gauri Shankar substitute Khalasi, w.e.f. 18-8-1985 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. The concerned workman Gauri Shanker in his claim statement has alleged that he was engaged as substitute khalasi on 19-11-83 by the opposite party Divisional Electrical Engineer, Izatnagar Bareilly. He continued to work at this post upto 17-8-85. In this way he had acquired temporary status Under Rule 2512 Railway establishment Manual. Further he was given annual increment D.A., H.R.A. CCA and PTO's during this period. His provident fund was also deducted. His termination is bad as there has been no compliance of Section 25-F and 25-H of I.D. Act. He has been making representation from 1-6-86 to 6-9-90 details of which have also been given. Thereafter conciliation proceeding were started.

3. The opposite party has filed reply in which it is admitted that the concerned workman was appointed as Khalasi from the date mentioned by him. However their plea is that originally he was appointed for a period of 3 months. His term was fur her extended from time to time for 15 months ultimately when his term expired, the same was not extended as there was no need for it. In this way it is not a case of retrenchment.

4. The concerned workman has filed rejoinder in which the new facts raised in the claim statement have been denied.

5. The first point which needs consideration is as to whether the concerned workman was appointed to a fixed period. There is oral evidence of H. N. Sharma, Office Sudt., Izatnagar Bareilly. In his cross examination he has admitted that the concerned workman was taken on 19-11-83 and after completion of 120 days he was provided all the benefits and facility of temporary employee. However his term was for fixed period. This fact has been denied by Gauri Shanker in his evidence. I am not inclined to believe the version of the mangement that the term of concerned workman was for a fixed period as the opposite party has not filed the copies of verious order by which he was appointed for a fix period. Had he been appointed for a fix period he would have not been extended the benefits of temporary employee. Further he was doing the job of permanent nature. In this way my findings is that the concerned workman was not appointed for a fixed term instead he was appointed temporarily. There is no dispute that he had worked from 19-12-83 to date of termination i.e. 17-8-85. In this way he had completed more 240 days in a calendar year preceding the date of termination.

6. Admittedly he has not been given notice pay and compensation which was mandatory under Section 25-F of I.D. Act. Hence his termination is bad in law.

7. No doubt there is gross delay in raising the Industrial dispute but the same has been explained. Exhibits W-1 to W-66 are a various copies of letters and postal receipts by which the concerned workman had been ventilating his grievance till he initia ed conciliation proceedings. Hence teh delay will not disentitle him in the relief of reinstatement. Instead it will be enough if he will be denied back wages.

8. Accordingly my award is that termination of concerned workman from 18-8-85 is bad in law hence he will be entitled for reinstatement but not for back wages.

30-4-1996.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मई, 1996

का०आ० 1566 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मध्य रेलवे के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-5-96 को प्राप्त हुआ था

[संख्या एल--41011/44/91-1 आई आर बी आई]

पी०जे० माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th My, 1996

S.O. 1566.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Rly., and their workman, which was received by the Central Government on the 9-5-1996.

[No. L-41011|44|91-IRBI]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 28 of 1996

BETWEEN :

PRESIDENT :

Rashtriya Chaturth Shreni Rail Mazdoor Congress, 4 Hirapur Nagra, Jhansi.

AND

Divisional Rly. Manager,
(Personnel) Central Rly.,
Jhansi.

AWARD u|s 33-A of I.D. Act.

1. This is an application under sec. 33-A of I. D. Act, by Hiralal and 212 others which have been moved under the following circumstances—

In all there are 213 workmen the details of which are given in the annexed list. They had raised an industrial dispute which has been registered as I.D. No. 201|91 Hiralal and 212 others versus Central Rly. In the claim statement of I.D. 201|91, it was alleged that they hot weather waterman working for the last 18 to 20 years. Yet they have not been regularised. When they claimed for regularisation, opposite party central railway stopped taking work from them w.e.f. 1-4-92 i.e. during the pendency of reference which amounts to change in condition of service under sec. 9-A of I. D. Act which could not be done without compliance of section 33. Hence a composite relief was sought for reinstatement and regularisation. When this reference became ripe for arguments the same prayer was once again made. At this stage doubt was expressed as to whether the relief under sec. 33-A of I.D. Act, could be awarded in the parent case. In order to rest this controversey at rest, the applicant moved an application on 20-3-96 u|s 33-A of the Act, seperately copy was served upon the opposite party and the same was registered as I. D. Case no. 28|96, 26-3-96 was fixed for hearing but none turned up on behalf of the railway. Being of the view that railway might have been handicapped by some unavoidable circumstances, I did not proceed to pass orders for about a month. Still no one has turned up. Hence I have no option but to proceed exparte against the railway.

2. Thus hard fact is that there is no reply to the fact that during the pendency of reference I.D. No. 201|91 the services of the applicants have been put to an end which certainly amounts to change in conditions of service. Apart from the absence of denial there is also positive evidence of workmen by way of affidavit in I.D. Case no. 201 of 1991 which being read in persuance of request of the applicants.

3. In this it is established that the services of all the applicants have been put to an end and which certainly amounts to change in condition of service. It is also not disputed that the opposite party had taken prior permission of this tribunal before effecting this change of service condition. In this way there has been utter breach of sec. 9A and 33 of I.D. Act, in terminating the services of the applicants. As such the applicants are entitled for reinstatement in service.

4. I award accordingly.

5. The applicants shall also get Rs. 200|- as costs of the case.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

मंडल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य) झांसी के एम०आर०सी०एल० रेल कर्मियों की सूची :

नाम	पिता का नाम	पता	रेल सेवा में लगने की प्रथम दिनांक
1 2	3	4	5
1. श्री हीरा लाल (एम०सी०)	श्री राम दास	लहरगिद्द, एस०आई०सी० इन्टर कालेज के० नालागंज, सीपरी बाजार, झांसी ।	31-1-84
2. अजीउद्दीन	श्री मुईनउद्दीन	आर०बी-1, 753, श्री रानी लक्ष्मी नगर, सीपरी बाजार, झांसी	19-8-81
3. धनीराम	श्री हरु	ग्राम बल्लमपुर, जिला झांसी	1-4-76
4. प्रमोद कुमार	श्री मुरलीधर	30 प्रेमगंज, सीपरी बाजार, झांसी	1-4-87
5. यदुनाथ सिंह	श्री रघुवीरसिंह	आर०बी०-1, 752 डी० रानी लक्ष्मीबाई, झांसी	1-4-87
6. बलवान सिंह	श्री कल्लू	ग्राम बलौरा, जिला झांसी	1-4-86
7. हरीसिंह	श्री हरदु	167 रेलगंज, पुलिया सं० 9, झांसी	12-4-86
8. गोविन्द दास	श्री भाटू	132, अलीगोल खिड़की अन्दर, झांसी	1-4-78
9. पारीक्षत	श्री रामदास	ग्राम हंसारी, जिला झांसी म	1-4-78

1	2	3	4	5
10.	श्री महेश साहू	श्री रघुवर साहू	211/12, नैनागढ़, नगरा झांसी	1-4-35
11.	श्री लाल सिंह	श्री सरजू प्रसाद	ग्राम व पो० करकोस, तह० मोंठ, झांसी	22-5-85
12.	श्री मनीराम	श्री खच्चू राम	107, प्रेमगंज सीपरी बाजार, झांसी	12-4-87
13.	श्री श्याम लाल	श्री कल्लू	513 महाबरन नगरा, झांसी	1-4-76
14.	श्री महेश कुमार	श्री बाबू लाल	6 इस्लामगंज, प्रेमनगर नगरा झांसी	1-4-78
15.	श्री उमाशंकर	श्री राम लाल	ग्राम बल्लमपुर, जिला झांसी	1-4-76
16.	श्री मुन्नाकुमार सक्सैना	श्री फूल चंद	359/1, प्रेमगंज, सीपरी बाजार, झांसी	22-4-85
17.	श्री महेश	श्री बिन्दोले	गोरा करन कोच थाना कोंच, जालौन	1-4-78
18.	श्री मु० रफीक	श्री चिन्मन खां	135/1 अली गोल खिड़की, बाहर, दतिया गेट, झांसी	1-4-78
19.	श्री श्रीमती रनिबाई	पत्नी श्री धन्नू	510, अम्बेडकर रोड, बंगला नं० 261 आउट हाउस, रेलवे कालोनी, झांसी	1-4-78
20.	श्री प्रेम नारायन	पुत्र श्री गरीबदास	श्री सोतानाथ मंदिर के पास, लाडगंज रानीपुर, झांसी	12-4-85
21.	श्री कैलाश	श्री विश्वनाथ	पठारी गांव, झांसी	1-4-73
22.	श्री दतुआ	श्री गोरे लाल	ग्राम बल्लमपुर, झांसी	1-4-76
23.	श्री कोप सिंह	श्री बारे लाल	नालगंज, सीपरी बाजार, झांसी	22-5-85
23ए.	श्री रूप सिंह	पुत्र श्री मगन लाल	ग्रा०पो० अंसारी, झांसी	20-4-80
24.	श्री बृजभान	पुत्र श्री धनीराम	261, डा० अम्बेदकर रोड, आउट हाउस रेलवे कालोनी, झांसी	26-1-83
25.	श्री हरिश्चन्द	श्री जयसिंह	45/1 छोटी मस्जिद पुलिया नं० 9, झांसी	4-4-87
26.	श्री बृजलाल	श्री बाबू लाल	32 ईदगाह, पुलिया नं० 9, झांसी	26-5-85
27.	श्री गोविन्द प्रकाश सैनी	श्री दयाराम	700/44 नाथ की कोठी, सीपरी बाजार झांसी	3-6-86
28.	श्री गंगाराम	श्री लक्ष्मण	235, नन्दनपुरा, सीपरी बाजार, झांसी	20-6-85
29.	श्री दिलीप कुमार	श्री भइयालाल	331/1 नैनागढ़, नगरा, झांसी	20-1-83
30.	श्री नरोत्तमदास	श्री रामसेवक	ग्राम महाम्बानी, पो० बंगरा, जालौन	6-4-87
31.	श्री ओम प्रकाश	श्री बाबू लाल	72 ईदगाह पु०नं० 9, झांसी	23-6-85
32.	श्री उमाशंकर	श्री चेटाराम	5 मार्केट मोहल्ला, यूनियन बैंक के पास सदर बाजार' झांसी	8-5-87
33.	श्री बाल किशन	श्री फूलसिंह	ग्राम बल्लमपुर, झांसी	1-4-86
34.	श्री उमेशकुमार	श्री मायाराम	स्टेशन रोड, बस्तर के सामने, अनर्रा बांदा	26-5-85
35.	श्री मानिकलाल	श्री सरजू प्रसाद	505 ई मार्केट मो० यूनियन बैंक के पास सदर बाजार, झांसी	3-6-86
36.	श्री महेन्द्र पाल	श्री हरप्रसाद	8 प्रेमगंज, सीपरी बाजार, झांसी	20-6-85
37.	श्री बलराम	श्री सुखइया	ग्रा० व पो० छतरामपुर, तह० राठ, हमीरपुर	1-4-78
38.	श्री कैलाश	श्री नत्थू	33 बी पी०ए०सी० वाहिनी, झांसी	23-3-80
39.	श्री रामबाबू	श्री गोपाल	दीनदयाल कालोनी, नंदनपुरा, झांसी	1-4-86

1	2	3	4	5
40.	श्री मोहनलाल	श्री कल्लूराम	8/26, लालता प्रसाद कम्पाउन्ड, सदर बाजार, झांसी	8-5-87
41	श्री कांशीराम	रामप्रसाद	380-डी कारखाना रोड, ओवर ब्रिज रोड, बालमंदिर स्कूल के पीछे, झांसी	8-7-76
42.	श्री घनश्याम	श्री हरकिशोर	राजनगर, महावीरन, नगरा, झांसी	1-4-78
43.	श्री किशनकुमार	श्री फूलनसिंह	594/12/कालशीपुरा, मर्सहा गंज, सीपरी बाजार, झांसी	1-4-78 (आगरा)
44.	श्री सुरेशकुमार	श्री दुलारे	868, एवटगंज, ग्वाल टोली, झांसी	4-4-84
45	श्री अरविंद कुमार	श्री भगवानदास	98, बाहर खन्डेरावगेट, नहृ० के पास गांधी भवन के सामने, झांसी ,	1-4-86
46.	श्री दयाचन्द्र	श्री दीनानाथ	91-जी. लालकुर्ती बाजार, झांसी	21-4-82
47.	श्री सुरेशचंद्र	श्री मक्खनलाल	278 नैनागढ़ पुलिस चौकी के पास, प्रेम नगर, झांसी	20-3-83
48.	श्री किशोरी शरण	श्री नाथूराम	166/1-बी० नंदनपुरा, सीपरी बाजार, झांसी	10-5-78
49.	श्री करन सिंह	श्री नरेन्द्र सिंह	ग्रा० बटीली पो० कामरारी, दतिया	3-4-87
50.	श्री दिलीप सिंह परिहार	श्री छक्कीलाल	ग्रा० व पो० हसारी, जि० झांसी	9-4-76
51.	श्री राजेन्द्र कुमार	श्री गोपाल	175/9 बाहर दतियागेट, झांसी	1-4-87
52.	श्री अर्जुन प्रसाद	श्री ग्यासी राम	13/3 (2) नयापुरा, कलारी के पीछे, झांसी	23-6-77
53.	श्री प्रदीप कुमार	श्री हरीदास	18 प्रेमगंज, सीपरी बाजार, झांसी	1-4-86
54.	श्री घनश्यामदास	श्री बाबूलाल	56, चिरंजीलाल का हाता, नैनागढ़, नगरा, झांसी	1-4-78
55.	श्री प्रेमचन्द	श्री श्यामलाल	34/3 प्रेमगंज, सीपरी बाजार, झांसी	1-4-87
56.	श्री काशीप्रसाद	श्री सुम्मेर	14 प्रेमगंज, सीपरी बाजार, झांसी	12-7-86
57.	श्री मेवा लाल	श्री कुंवर राज	रक्सा, पो० रक्सा, झांसी	3-7-79
58.	श्री छोटे लाल	श्री मंगली	9/6 बिहारी पुरा, प्रेमनगर, झांसी	19-5-82
59.	श्री रामदयाल	श्री गोटाराम	241/3 नैनागढ़, नगरा, झांसी	1-4-87
60.	श्री रमेश चन्द्र	श्री पहलू	10 महावीरनपुरा, प्रेमनगर, थाना नगरा, झांसी	1-4-78
61.	श्री राजेश साहू	श्री तुला साहू	9 16/75ए मुहम्मादलाई बाबा नैनागढ़ झांसी	20-4-82
62.	श्री हुकम चन्द	श्री ग्यासी लाल	म०नं० 19 निकोनिया पुलिया नं० 9, झांसी	1-4-86
63.	श्री सीताराम	श्री भोंटे	ग्रा० चतुरताई पो० मा कुमा, झांसी	1-4-87
64.	श्री ओम प्रकाश	श्री बारेलाल	म०नं० 246/73 नी० कलाई बाबा, झांसी	1-4-87
65.	श्री राम दास	श्री चेतरामबाबरे	582 शिव बिल्डा भार के सामने, कसाई ढोला, प्रेम नगर, झांसी	1-4-86
66.	श्री मुन्ना लाल	श्री बिष्टे	सूबे खा खिड़की म०नं० 84, झांसी	1-4-85
67.	श्री ठाकुरदास	श्री गज्जूराम	म०नं० 5 नयापुरा, पु०नं० 9, झांसी	23-4-85

1	2	3	4	5
68.	मो० रहीम	श्री मो० बशीर	म०नं० 69, मोहल्ला मुकरयाना, झांसी	1-4-78
69.	श्री हरि राम	श्री सुम्मेर	विजय नगर सलीमपत, पो० चमरौआ, झांसी	1-4-76
70.	श्री बैजनाथ	श्री मोहनलाल	ग्रा० पुअरपरा, पो० कुहर, टीकमगढ़, झांसी	1-4-83
71.	श्री मुरलीधर	श्री भागीरथ	19, ईदगाह म.नं० 9, झांसी	22-5-85
72.	श्री हरीराम	श्री मंगलसिंह	257/आर नंदनपुरा, सीपरी बाजार, झांसी	1-4-75
73.	श्री विनोदकुमार म	श्री कल्लू	5/3 महारिनपुरा प्रेम नगर, झांसी	1-4-76
74.	श्री महेश चन्द्र	श्री बांकेलाल शर्मा	432 नानकगंज, सीपरी बाजार, झांसी	3-7-79
75.	श्री वीरेन्द्र कुमार	श्री कोमलसिंह	32/87 नैनागढ़, नगरा, झांसी	23-6-77
76.	श्री राम प्रकाश	श्री मुन्ना	ग्राम पोस्ट पी०ए०सी०, प्रेमनगर झांसी	1-4-36
77.	श्री मानसिंह सिंह	श्री नन्द किशोर	ग्राम सफा जिला झांसी	3-1-84
78	श्री नारायन	श्री [illegible]	सूजे खां खिड़की म०नं० 148, झांसी	19-8-81
79.	मु० शमीर	श्री करामत खां	म०नं० 31 तिकोनिया पु०नं० 9, झांसी	1-4-76
80.	श्री हरनारायन	श्री मुकन्दी	ग्रा० डेली, जिला झांसी	1-4-77
81.	श्री घन श्याम	श्री हरगोविन्द	69, अंदर लक्ष्मी गेट, झांसी	1-4-87
82.	श्री रमेश	श्री राम दयाल	275 गुदरी मुहल्ला, कलारी के पीछे, झांसी	1-4-86
83.	श्री किशोरी लाल	श्री नाथूराम	121 मकरयाना दतिया गेट अंदर, झांसी	12-4-86
84.	श्री श्याम लाल	श्री सुन्दर लाल	98 कछयाना पु०नं० 9, झांसी	19-12-83
85.	श्री मोहन लाल	श्री बाबूलाल	13/2 नया कछयाना पु०नं० 9, झांसी	1-4-78
86.	श्री सैमुअल	श्री जार्ज जेकब	जे०एए०टी० वार्ड० 8 रानी लक्ष्मी नगर, झांसी	1-4-78
87.	श्री रामप्रसाद	श्री रम्भू	241/28 नैनागढ़, नगरा, झांसी	1-7-85
88.	श्री पुकरन सिंह	श्री बलूसिंह	ग्रा० व पो० हरदोई गूजर, जिला जालौन	22-5-85
89.	श्री देवी दयाल	श्री रामलाल	170/ नंदनपुरा सीपरी बाजार, झांसी	3-6-86
90.	रज्जाऊखां	शकूर खां	ग्राम भोजला पो० बूढ़ा, झांसी	12-4-87
91.	मु. नासिर	मु० युसूफ	98 मोहनी पाबा, झांसी	1-4-76
92.	अब्दुल रशीद	अब्दुल मजीद	55 सिमाते खाना, झांसी	1-4-78
93.	श्री धनीराम	श्री रामदास	89/1 बाहर दतिया गेट, झांसी	22-5-85
94.	श्री गुलाब चन्द	श्री हर चरन	85/2 खुशीपुरा खारे कुएं के पास, झांसी	1-4-76
95.	गफ्फार अहमद	गफूर अहमद खां	31 अली गोल, झांसी	22-4-88
96.	श्री ओम प्रकाश	श्री छेदी लाल	84 बड़ा कुआ पु०नं० 9, झांसी	1-4-78
97.	श्री माहीलाल	श्री उमराव	48 बड़ा कुआ पु०नं०, 9, झांसी	1-4-78
98.	श्री मोती लाल	श्री कामताप्रसाद	26 पुराना कछियाना पु०नं० 9, झांसी	1-4-78
99.	श्री मुन्नाराजा	श्री रघुराज सिंह	मसीहागंज, सीपरी बाजार, झांसी	12-4-85
100.	श्री भगवान दास	श्री गज्जूराम	133, स्कूलपुरा प्रेम नगर, झांसी	1-4-78
101.	श्री जोंजी	श्री विलियम	आर०वी०-1, 754 एच रानी लक्ष्मीनगर, झांसी	1-4-76

1	2	3	4	5
102.	रमेश चन्द	डल्कू	11 ईदगाह पु०नं० 9, झांसी	22-5-85
103.	भगवान दास	गरीबदास	40 छोटी मस्जिद पु०नं० 9, झांसी	17-8-81
104.	राम लाल	हरदास	190 पेंच मुहल्ला हड्डी घर के सामने नंदन-पुरा के पास, झांसी	3-1-84
105.	श्री राम	राम चरन	353 ,, ,, ,,	1-4-76
106.	राजाराम	उद्दा	330 नन्दनपुरा पेंच मुहल्ला, झांसी	1-4-87
107.	रामकिशोर	श्यामा प्रसाद	28 झागरी गंज, झांसी	1-4-87
108.	कन्छेदीलाल	गोविन्द दास	366, नैनागढ़, ननरा, झांसी	1-4-86
109.	प्रभुदयाल	छक्कीलाल	65 छोटी मस्जिद पु. नं. 9 झांसी	26-1-83
110.	छक्कीलाल	रामदीन	ग्राम बलोरा, जिला झांसी	4-4-87
111.	अजीज अहमद	नसीम मो.	712 एवरगंज, सीपरी, बाजार, झांसी	26-5-85
112.	नंदकिशोर	झम्मनलाल	135 स्कूल पुरा, प्रेमनगर, झांसी	3-6-86
113.	रविशंकर	मल्थूराम	नानकगंज, सीपरी बाजार, झांसी	20-6-8 5
114.	चिम्मन लाल	किशोरी	175 कूरयाना शंकर मंदिर, पु. नं. 9, झांसी	20-1-83
115.	नाथूराम	लाल जी	ग्रा. खिरगपट्टी, पो. भट्टा, गांव झांसी	6-4-83
116.	रमेश चंद	पन्ना लाल	पो. मरेरा, जिला दतिया	23-6-85
117.	घनश्याम	बैजनाथ	185/2 आरामशीन नंदनपुरा, झांसी	1-4-86
118.	दिनेश कुमार	भगवान दास	190 बंगला घाटेकोरियन के मंदिर के पास, झांसी	5-8-87
119.	राम किशन	धनश्याम दास	म.नं. 6 प्रेगगन्ज, सीपरी बाजार, झांसी	24-5-85
120.	अमर सिंह	सूक्कू सिंह	म.नं. 297, खुशीपुरम, झांसी	3-6-86
121.	आदराम	छोटे लाल	172, खुशी पुरा, झांसी	20-6-85
122.	मंगल सिंह	दयाराम	लोको शेड, बांदा	1-4-78
123.	बाबू लाल	राम प्रसाद	सीपरी बाजार, नानकगंज, 56 म.नं. झांसी	23-3-80
124.	राम लाल	गोकुल	पुलिस चौकी के सामने नगरा, झांसी	1-4-86
125.	ओम प्रकाश	रामजीत लाल	म.नं. 225, धौनी प्याऊ, मालीपाड़ा, मथुरा	8-5-87
126.	मकबूल बेग	मनीर बेग	25/2 थाना प्रेम नगर के पीछे, नगरा, झांसी	8-7-86
127.	अब्दुल रसीद	मुन्शी	नं. बिहारी पुरा गडिया फाटक नगरा, म.नं. 220, झांसी	1-4-75
128.	रामलाल यादव	ज्याता प्रसाद यादव	ग्राम मडोरा, पो. मदगऊ, झांसी	1-4-78
129.	नन्द किशोर	भजनलाल	20 ठाकुरमाना प. नं. 9 झांसी	4-4-87
130.	मानसिंह	लचू	101 सूजेशा, खिड़की, झांसी	1-4-86
131.	बाबू लाल	किशनलाल	कलारी के पीछे प.नं. 9 झांसी	21-4-82
132.	राकेश कुमार	प्रभु दयाल	आर.बी.-1756 जी, रानी लक्ष्मी नगर, झांसी	20-3-93
133.	रमेश कुमार	चतरे	604 मसीहागंज बोटराज, कम्पाउन्ड के पीछे, सीपरी बाजार, झांसी	10-5-79
134.	सुरेश कुमार	राम प्यारे	631 नई बस्ती झांसी	26-1-83

1	2	3	4	5
135.	सन्तोष	नटर	ग्रा. कबौरा, जिला झांसी	4-4-87
136.	फखरुद्दीन	चम्मू खां	25 अनार दतिया गेट, झांसी	26-5-85
137.	धनीराम	लल्ला	171/2, बी. प्राइमरी स्कूल कस्तूरबा के पीछे नगर, झांसी	3-6-90
138.	संजय कुमार	भगवान दास	75/2 अन्दर उन्नाव गेट, झांसी	3-4-85
139.	कन्हैया लाल	लक्ष्मी नारायण	70/2 अन्दर अन्नाव गेट, झांसी	1-4-85
140.	ललितमोहन	नत्थू	मम.नं. 22, चमरयाना, प्रेम नगर, झांसी	1-4-78
141.	आनंद कुमार जेम्स एडवर्ड जेम्स		24 पीसा सिरजा, सीपरी बाजार, झांसी	3-6-81
142.	श्याम बाबू	प्यारे लाल	63/22 चावली, आगरा	22-4-74 (आगराकैन्ट)
143.	श्रीमती द्रोप दुलारी	पत्नी श्री हेतराम	104/53 उर्खरा, डा. परतापपुरा, आगरा	8-5-79 (आगरा कैन्ट)
144.	श्रीमती गोमती बाई	पत्नी श्री हल्ला खलासी द्वारा राजाराम	म.नं. 16 रेलवे क्वार्टर, आगरा कैन्ट	3-4-78 (आगरा कैन्ट)
145.	श्रीमती शान्ती देवी	पत्नी श्री रामदास तिवारी	डी-22 श्री करतार सिंह का बंगला रेलवे कालोनी, आगरा कैन्ट	1-4-71 (आगरा कैन्ट)
146.	श्रीमती मानकुमारी	पत्नी श्री रामलाल	लेखराज का नगला धनोली, आगरा	1-4-72 (आगरा कैन्ट)
147.	श्रीमती लक्ष्मीबाई	पत्नी श्री शान मोहम्मदपुत्री कल्लन,	56/25 खमीर चन्द का नगला, आगरा कैन्ट	2-4-72 (आगरा कैन्ट)
148.	कासिम	पुत्र श्री गोपाल ग्राम मलेरा	22बी, पी.ए.सी. प्रेमनगर झांसी	3-6-82
149.	राकेश चन्द	पुत्र श्री पहलू	10, प्रेमनगर नगरा, झांसी	3-4-80
150.	उमाशंकर	पुत्र चेतराम	सदर बाजार, झांसी	3-6-86
151.	श्रीपत पुत्र श्री जगन		नि. 23 पी.ए.सी. बटालियन राजगढ़ झांसी	1-11-81
152.	श्री राम बाबू	पुत्र श्री सीताराम साहु	477 नई बस्ती, झांसी	20-5-79
153.	श्रीपत	जगन	ग्राम भटौरा पी.ए.सी. राजगढ़, झांसी	1-4-80
154.	सुरेश	हरचरन	149 प्रेमचन्द सीपरी बाजार, झांसी	20-4-85
155.	चन्द्रभान	मनीराम	71 छोटी मस्जिद म.नं. 9, झांसी	1-4-78
156.	हीरा लाल	सूखे	ग्रा. कब्वेर पो. बजरा, झांसी	1-4-80
157.	अयूब खां रूप नगर	मुनीर खां	19 चढ़ा हुआ म.नं. 9 झांसी	—
158.	अशोक तिवारी	पुत्र देवीराम तिवारी	175 नन्दनपुरा सीपरी बाजार, झांसी।	1-6-1978
159.	कैलाश चन्द (एस०सी०)	पुत्र श्री भिक्का	690 मसीहागंज सीपरी बाजार, झांसी	27-3-1980
160.	बाबू सिंह	पुत्र श्री पहलू	1174/1, शीन्धू कम्पाउन्ड सीपरी बाजार, झांसी	22-2-1983
161.	रामसिंह यादव	पुत्र हर प्रसाद	36/13 प्रेमगंज चन्द्रभान कम्पाउन्ड सीपरी बाजार, झांसी	8-4-1982
162.	छोटे लाल	पुत्र रन्धीर	163 नानक गंज सीपरी बाजार, झांसी	24-1-1979
163.	नारायणदास	पुत्र रामदास	105 नानक गंज	19-6-1978

1	2	3	4	5
164.	ओम प्रकाश	पुत्र गोबिन्द दास	82 प्रेमगंज चन्द्रभान कम्पाउन्ड, झांसी	20-4-1974
165.	राम प्रकाश	पुत्र हर चरण	ग्राम लोहागढ़ पोस्ट लोहागढ़, जि० झांसी	1-4-1987
166.	लखन	पुत्र हरदास	22 भैरों खिड़की, झांसी	1-4-1987
167.	रज्जन	तुलसी	115 नई बस्ती चांद दरवाजा, झांसी	21-11-1983
168.	ओम प्रकाश सिंह	पुत्र बी० एल० सिंह	69 महावीरन नगरा, झांसी	8-5-1987
169.	किशन लाल	पुत्र मंगली	पो० चमरउआ जि० झांसी	3-11-1976
170.	रामचरण	पुत्र श्रवन्दी	24 नरसिंहराव टोरिया, झांसी	1-4-1977
171.	राजेन्द्र कुमार (एस०सी०)	पुत्र सभरलाल	1212/13 गोन्दू कम्पाउन्ड झांसी	20-2-1983
172.	प्रमोद कुमार	पुत्र बृजलाल माली	25/12ए प्यारेलाल हाता नागरा झांसी	1-4-1985
173.	अर्जुन दास	पुत्र मुक्लटे	17 गणेश बाजार, झांसी	19-4-1978
174.	कन्हैया लाल	पुत्र राजकिशोर	60 झांर खड़िया, झांसी	3-6-1986
175.	बाला प्रसाद श्रीवास्तव	माधो प्रसाद	66 अन्दर सैयर गेट झांसी (कुस्टयाना)	18-3-1983
176.	रमेश कुमार	छक्ककी लाल	87 मेवती पुरा झांसी	19-12-1977
177.	उस्लाम खां	पुत्र अमिर खां	के०टी०पी०पी० 134 रो रेलवे कालोनी रानी लक्ष्मी नगर झांसी गुड्स रोड सीपरी	6-4-1987
178.	अरविन्द कुमार	पुत्र नारायण दास	18 नानक गंज सीपरी बाजार, झांसी	1-4-1987
179.	मथुरा प्रसाद	पुत्र पन्ना लाल	72 नानक गंज सीपरी बाजार, झांसी	1-4-1987
180.	ऐलस बाई	पत्नी स्व० जार्ज जेकब	टी०वाई०-8 रानी लक्ष्मी नगर वर्मा शैल के पीछे सीपरी बाजार, झांसी	24-5-1973
181.	शान्ति बाई	पत्नी काशीराम	103 गुड्स शैड सीपरी बाजार, झांसी	1-4-1970
182.	शान्ति बाई	पत्नी राम प्रसाद	621 स्टे० शेड सिविल लाइन झांसी	5-4-1972
183.	शीला बाई	पत्नी श्याम लाल	199 नई बस्ती चांद दरवाजा झांसी	4-4-1971
184.	नन्द रानी	पत्नी झुमान		7-5-1969
185.	धन्नो बाई (एस०सी०)	पत्नी हर लाल	100 रेस्ट हाऊस जी०आर०पी०, झांसी	7-5-1969
186.	कस्तूरा बाई (एस०सी०)	पत्नी भगवानदास	रेस्ट हाऊस जी०आर०पी० झांसी	1-4-1980
187.	शिमला बाई	पत्नी मदन मोहन	92/2 आशिक चौराह नई बस्ती, झांसी	1-4-1988
188.	आबादी बाई	पत्नी हसमत खां	64 ब्रिजरोड न्यू रेलवे अस्पताल, झांसी	1-4-1970
189.	खुररन	पुत्र अब्दुल गफूर	के० 1133 रेलवे कालोनी रानी लक्ष्मी नगर, झांसी	1-4-1977
190.	हरलाल	पुत्र शिव दयाल	सिनोनिया पो० सिनोनिया निवाड़ी पृथ्वीपुर टीकमगढ म०प्र०	19-2-1983
191.	असलम खां	पुत्र अब्दुल गफूर	133 रेलवे कालोनी रानी लक्ष्मी नगर, झांसी	2-5-1985
192.	ललता बाई	पत्नी परम	कल्याणपुरा, पो० मोहरा चौ० बासी, जि० झांसी	19-9-1978
193.	सुरेश कुमार	पुत्र बाबू लाल	म०न० 526 नानक गंज सीपरी बाजार, झांसी	1-4-1987

1 2	3	4	5
194. मेवा लाल	पुत्र राम दास	म०न० 35 खिचड़ीपुरा पुलियां नं० 9 झांसी	21-6-1979
195. बाबू लाल	पुत्र गज्जूराम	100/14 बाहर भंडारी गेट, झांसी	1-5-1973
196. मानहर्बंर	पर्त्री धर्मसिंह	58 गुदड़ी कलारी के पास (शहर)	1-4-1981
197. रमेश अहमद	बीर खां	जुम्मन खां की झोपड़ी मुन्तका अगम	21-10-1976
198. दशरथ	हरकुंग्रार	पुलिया न०टी० ओओ	27-4-1978
199. सुन्दर सिंह पुत्र	श्री सरदार सिंह	गांव सदरबन, पो. बिचपुरी, आगरा	19-12-78
200. अशोक कुमार	मुन्ना लाल	मसीहागंज, प्राइमरी स्कूल के पास सीपरी बाजार, झांसी	1977
201. शिव कुमार	चिम्मन लाल सिंह	20 तिकोनिया पक्का फर्स पुलिया नं. 9, झांसी।	1987
202. शंकर लाल	तुलसी दास	211 ईसाईटोला कमलसिंह कालोनी, झांसी	1987
203. जगदीश	हरचरन	172 अलीगोल, झांसी।	1987
204. रमेश	राम दास	525 नानक गंज, सीपरी बाजार झांसी।	1987
205. धनीराम	करजू	10 नानकगंज, सीपरी बाजार, झांसी।	1972
206. जानकी प्रसाद	लक्ष्मी प्रसाद	ग्रा. पृथ्वीपुर, पो. स्यावरी, तह. महरानीपुर, झांसी।	1987
207. मुन्ना लाल	रामदीन	609/11 मसीहागंज, सैन्ट मैरी स्कूल के पास, सीपरी बाजार, झांसी।	1986
208. मन्ना लाल	अजुद्दी	मसीहागंज म.नं. 554/20 वोदनगर, सीपरी बाजार झांसी	1978
209. राम किशन	नन्दराम	525 खुशीपुरा, झांसी	1985
210. किशन लाल	पन्ना लाल	ग्रा. पो. बराटा, झांसी।	1970
211. तेज सिंह	गोविन्द सिंह	ग्रा. व पो. बिजोली, झांसी मु. लालपुरा।	1981
212. रमेश कुमार	राम दयाल	882 मसीहागंज, सीपरी बाजार झांसी	1985
213. श्री महेश चंद	लक्ष्मन लाल	51, ईदगाह, पुलिया नं. 9, झांसी	1987

नई दिल्ली, 10 मई, 1996

का.आ. 1567.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मध्य रेलवे के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4/5/96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-41012/85/92-आईआरबीआई]

पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, tne 10th May, 1996

S.O. 1567.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Rly., and their workman, which was received by the Central Government on 9-5-1996.

[No. L-41012|85|92-IRBI)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, PANDU NAGAR, DEOKI PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute No. 77 of 1993

1. Divisional Railway Manager (B)
Central Railway, Jhansi.

2. Senior G. O. M. S.,
Central Railway, Jhansi

AND

Shri Surender Singh,
Rashtrya Chaturth Shereni Rail Mazdoor Congress,
4, Hirapura Nagra, Jhansi.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-41012|85|92 dated 24-9-93, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of DRM and Sr. D.O.M.S., Central Railway, Jhansi in terminating the services of Shri Pratap Singh w.e.f. 2-4-88 is justified ? If not, what relief he is entitled to ?"

2. The case of concerned workman Pratap Singh is that he was appointed as casual labour on 24-3-73 by the opposite party. After completing 120 days he acquired temporary statous on 3-9-86. His medical examination had also taken place in which he was successful. Yet his services were terminoted on 2-4-88 illegally. His termination is bad in law as juniors to him retained in service.

3. The opposite party failed to put in appearance despite of sufficient service.

4. There is unrebutted affidavit of Pratap Singh in support of his claim which is also supported by exhibited W-1 to W-8. In this way the claim of workman is proved to my satisfaction. It is established that junior to the workman have been retained in service. Hence his Termination is bad in law because of breach of section 2-H of I.D. Act.

5. Hence my answer is that termination of concerned workman w.e.f. 2-4-88 is not justified. Hence he is entitled for reinstatement with full back wages.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मई, 1996

का.आ. 1568—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नार्थ ईस्टर्न रेलवे के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9/5/96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-41012/100/90-आईआरबीआई]

पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th May, 1996

S.O. 1568.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of N. Eastern Rly., and their workman, which was received by the Central Government on 9-5-1996.

[No. L-41012|100|90-IRBI]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 123 of 1991

BETWEEN :

D. M. E. (C&W), N. E. Railway,
Lucknow

AND

General Secretary,

N. E. Railway Sharmik Sangh,
C|o Shri B. D. Tiwari.
96|196, Roshan Bajai Lane,
Ganeshganj, Lucknow.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-41012|100|90|I.R. (D.U.) dated 4|10-9-91, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the Disciplinary Authority, North Eastern Railway, Lucknow is justified in awarding him punishment of W.I.T. for five years and reversion to Fitter Gr. III to Sri Zilkad Ahmad ? If not, what relief he is entitled to ?"

2. In the above noted case a no claim Award was given on 5-7-95 which was also published. Later on at the instance of concerned workman the ex-parte Award was setaside. Fresh opportunity was given to the concerned workman to prove his case. Once again he fail to put in appearance. There is no evidence on behalf of the concerned workman.

3. In the absence of any evidence the reference is answer againt the concerned workman he will be not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मई, 1996

का.आ. 1569—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-12012/261/93-आईआरबीआई]
पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th May, 1996

S.O. 1569.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SBI and their workman, which was received by the Central Governmen on 9-5-1996.

[No. L-12012|261|92-IRBI]

P. J. MICHAEL, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT PANDU NAGAR, DEOKI PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute No. 34 of 1994

In the matter of dispute between :

Sri Ghanshyam Lal Srivastava
S|o Sri D. L. Srivastava
r|o State Bank Compound
Bank Road Gorakhpur.

AND

Assistant Manager
State Bank of India,
Gorakhpur.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012|261|93 I.R. B-2 dated 28-5-94 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of State Bank of India, Gorakhpur, in dispensing with the services of Sri Ghanshyam Lal Srivastava, Canteen Staff w.e.f. 1-9-87 vide their Memo No.-Admn.|33|984 dated 31-8-87 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?

2. From the pleadings of the parties and other material on record it becomes common ground that the concerned workman Ghanshyam Lal Srivastava, was initially appointed as Canteen Worker in the State Bank of India Staff Canteen State Bank of India Gorakhpur on 6-6-75 through Local Implementation Committee. Later on his designation was changed as LEKHAPAL w.e.f. 1-8-82. Thereafter he was asked not to perform his duties at this job. On 17-9-84, an agreement took place between management of State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation by which it was agreed that entire staff of the canteen will become direct employee of State Bank of India subject to certain conditions. After this agreement, the concerned workman continued to work and drew salary from State Bank of India till 31-8-87, when his services were terminated.

3. The case of the concerned workman is that he was an employee of the opposite party State Bank of India from the very inception. In any case it was also urged before me that atleast the concerned workman became direct employee of the State Bank of India from the date of agreement till the date of his termination as work was taken by the opposite party from him and wages were also paid to him by the same. The concerned workman has completed for more than 240 days in a calendar year hence his services cannot be terminated without compliance of section 25-F of I. D. Act. Further it is alleged that juniors to him were retained in service and no opportunity was given to him for being taken in service when new hands were taken. In this way his termination is bad in law.

4. The opposite party has filed written statement in which it is denied that the concerned workman was ever the employee of the opposite party. Instead

he was the employee of Local Implementation Committee. As there were more than 200 workmen in Gorakhpur Branch, the opposite party had agreed to take the management of this canteen and absorb the employees as their employees. It is further alleged that the case of the concerned workman was considered and was found not suitable as he was over age at the time of original entry in service and further as he was over qualified. As the concerned workman was not employee of the opposite party no question compliance of section 25-G & H of I. D. Act arises.

5. In the first place the authorised representative of the concerned workman with the aid of case of Parimal Chaudra Raha and others Versus Life Insurance Corporation of India, 1995 Lab. I. C. 2064 (SC) has urged that the concerned workman is the direct employee of the opposite party. In this case it was held that where canteen is run as was being run in the instant case, the employees of such canteen will be deemed to the employees of the management if there is statutory obligation on the part of employer to provide a canteen like in Factories Act. Such employee will also be treated as Direct employee of the management where it is agreed between the two parties or where there is condition of service to provide canteen. In the instant case State Bank of India is certainly not statutory obliged to maintain a canteen under Factories Act. It has also not been alleged or much less proved that to provide canteen was a condition of service of the State Bank of India employees. In its absence my finding is that the concerned workman cannot be extended the benefit of above mentioned authority and cannot be held to be the direct employee of State Bank of India, opposite party atleast upto the date of agreement.

6. Now we may consider as to whether the concerned workman should be treated direct employee of the opposite party w.e.f. 17-9-1984, i.e. the date of agreement. The concerned workman has adduced his evidence that after the agreement he has been continuously working in this canteen under the supervision of the opposite party and is being paid wages. Although Babu Ram Assistant Manager, State Bank of India, has entered into the witness box but he has not denied these facts. Instead he has spoken about the objection of the management with regard to concerned workman being over age and over qualified. In this way the evidence of the concerned workman is more cogent than that of the opposite party. On this basis it is held that the concerned workman has been working as directly under the opposite party from the date of agreement till his termination. As such he became the employee of the opposite party.

7. Admittedly the concerned workman was removed from service w.e.f. 1-9-1987 without paying retrenchment compensation, and notice pay which was obligatory. In its absence his termination is bad inlaw.

8. There is no evidence worth the name to show that there has been breach of section 25-G and 25-H of I. D. Act. Hence termination cannot be held to be bad on this score.

9. Lastly, some thing may be said about the objection of the opposite party in not regularising the services of the concerned workman in terms of the agreement. It is alleged by Babu Ram M.W. 1 that the concerned workman was over age over qualified. In support of this contention his school leaving certificate has also been filed which lend support to it. We may refer to para (3) of agreement dated 17-9-1984 by which the management have been given option to relax the age. Indeed management had vide order dated 2-7-1987 recommended to higher authorities for relaxation of age. It is not clear as to what transpired thereafter. Since the concerned workman had put in service for 10 years and had become palpably over age when this agreement took place his age ought to have been relaxed specially when the branch manager in his letter dated 2-7-1987 had written that the work and conduct of the concerned workman was satisfactoral and age should be relaxed.

10. As regards objection of the opposite party about the workman being over qualified, reference may be made to the case of Manphool Singh versus Union of India 1994 (69) FIR 399 in which Hon'ble High Court of Allahabad had held that this cannot be abar to the regularisation of services.

11. Hence, both the grounds on which the concerned workman has not been regulasised in service by the opposite party are not tenable

12. In the end my award is that the termination of the concerned workman's service by the opposite party is bad in law as suc hhe is entitled for reinstatement with back wages from the date of reference at the rate at which he was drawing wages at the time of termination. He shall also be entitled to Rs. 100/- as costs from the opposite party.

13. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 10 मई, 1996

का.आ. 1570—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उसके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-5-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-12015/16/90-आईआरबीआई]

पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th May, 1996

S.O. 1570.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal,New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial

dispute between the employes in relation to the management of RBI and their workman, which was received by the Central Government on 9-5-96.

[No. L-12015/16/90-IRBI]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 5/91

In the matter of dispute between :

The Vice President, Reserve Bank of India, Staff Association, C/o Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, New Delhi-110001.

Versus

1. The Manager, Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, New Delhi.

2. All India Reserve Bank Employees Association (Impleaded Party).

APPEARANCES :

Shri V.K. Nigam for R.B.I. Staff Association.
Shri Harish Sharma for R.B.E. Association.
Shri N.V. Desh Pandey with Shri R. Mehandiratta for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12015/16/90-I.R.B. III dated 14-1-91 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the alternative (i) given by the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in para 10 of their Award can be interpreted to mean that the Reserve Bank of India can fix the seniority of 30 workman in the common cadre? If not, what is the correct position about the implementation of the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi?"

2. In the statement of claim filed by the workman, it is alleged that a reference was earlier made to this Tribunal in an Industrial Dispute in which the reference was as follows :—

"Whether the action of the Management of R.B.I. in not giving seniority in accordance with the combined seniority Agreement to the 30 workmen is justified? If not, to what relief the concerned workmen are entitled?"

3. The then Industrial Tribunal had answered the reference and the concluding para was as follows :

"(1) these 30 workmen be kept in the clerical cadre on loss of 2/3rd of their seniority in non-clerical cadre and they shall not be transferable to the present Cash Deptt., or (ii) if it is the contention of the Management that it is not feasible to kept them in the clerical cadre and without any loss of seniority; common cadre be taking into account their full service in the non-clerical cadre and without any loss of seniority; or (iii) they may be given further option to revert to the non-clerical cadre in their parent department with their original seniority."

4. It has been alleged by the Reserve Bank of India Staff Association, New Delhi, hereinafter referred to as Staff Association, that while implementing the Award, the Bank issued letter dated 2-4-1990 to each individual concerned employee advising them that the Bank has since decided to accept Option No. 1, accordingly they could not be transferred to the Cash Department and as a consequence thereof, the promotional chances accruing in Cash Department and other benefits arising there from will not be admissible to them.

5. It has further been alleged by the Staff Association that since the Bank's above letter did not indicate their new cadre relating seniority position and their designation, this created utter confussion and doubt on the contention of the management, as a result of which the present reference has been made to this Tribunal to decide the issue as to whether the alternative (i) given by the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in para 10 of their Award can be interpreted to mean that the Reserve Bank of India can fix the seniority of 30 workmen in the common cadre or not.

6. It has further been alleged by the Staff Association that the Bank has not only negatived whole exercise on the part of this Hon'ble Tribunal culminating into the Award, but has also otherwise tried to justifiy and substantiate that these affected workmen were better placed on 1/3rd seniority of their total non-clerical service counted for their placement in the common cadre as at least they were in a position to chew the fruits of promotion in Cash Department when it justified to treat the common cadre and the clerical cadre on the same footing for the purpose of switch over to exclusive clerical cadre as

against the present position arising by Bank's ostensibly accepting first alternative while pretending to treat common cadre and clerical cadre as district cadre which has culminated in depriving their legilimate rights to prmotion in the Cash Department (i) by not transferring them to Cash Department (ii) at the same time retaining their position below the common cadre employees for purpose of seniority and promotion, both sides Clerical and Non-clerical. As a consequence of Bank's action, the workmen concerned have been thrown out of all the three cadres viz. non-clerical, cerical and common cadre.

7. It is further alleged by the staff association that the acceptance of alternative (i) prescribed in para 10 of the Award, is governed under the various clause 1 to 4 of the combined seniority scheme and can only be interpreted to mean to switch over these 30 workmen to their exclusive clerical cadre from non-clerical cadre courting for the purpose 1|3rd seniority of total non-clerical service only after they have been actually admitted in the exclusive cadre.

8. The staff association has challenged action of the management in implementing the Award on the following grounds :

(i) Because the workmen concerned have been placed among common cadre employees on loss of 2|3rd seniority of total non-clerical service.

(ii) Because the Bank has in fact applied alternative (ii), while misleading having accepted alternative (i) prescribed in para 10 of the Award and denied them full seniority which is not permissible as per directions contained in alternative (ii).

(iii) Because the workmen concerned have not been actually admitted in the exclusive clerical cadre and since clause iv(b) of the Combined Seniority Scheme has not been honoured by implementing alternative (iii) prescribed in para 10 of the Award.

(iv) Because they have been debarred of promotions in Cash Department having been fixed in the common cadre.

(v) Because the provision of the combined seniority scheme cannot be used to the detriment of the employees.

9. The Bank, however, has denied the allegations of the staff association.

10. It has been averred by the Bank management that this Tribunal had by its' Award dated 20th December, 1989 in I.D. Case No. 104|87 directed the management to choose one of the options given in paragraph 10 thereof and take action within one month from the date of enforcement of the said Award and accordingly the management had exercised Option No.1 and has taken necessary action in terms of the same. Unsatisfied by the action of the management, the opposite party had taken up the issue of implementation of the Award with the Government and the Government has referred the dispute to this Tribunal again under Section 36-A of the Industrial Disputes Act, 1947.

11. It has been further averred by the management that the Award dated 20-12-1989 in I.D. Case No. 104|87 related to the dispute relating to the 'Scheme for Combined Seniority' list and switch over, from non-clerical to clerical cadre'. In the said I.D. Case, there was no dispute regarding the non-clerical employees, who were eligible in terms of clause 1(a) of the Scheme and exercised their option in terms of clause 2(a) thereof. Bank's plea with respect to justification for imposing further condition as referred to in paragraph 3 of the Award aforesaid, was not accepted by the Tribunal. While disapproving Bank's action to the extent of making the workmen liable to be posted to the Cash Department, the Tribunal gave following three options : —

(i) These 30 workmen be kept in the clerical cadre on loss of 2|3rd of their seniority in the non-clerical cadre and they shall not be transferable to the parent Cash Department, or

(ii) If it is the contention of the management that it is not feasible to keep them in the clerical cadre, they may be absorbed in the common cadre by taking into account their full service in the non-clerical cadre and without any loss of seniority. or

(iii) They may be given a further option to revert to the non-clerical cadre in their parent department with their original seniority. The choice in the matter is left to the management keeping in view the fact that the workmen had accepted the further condition laid down by the management, however, oppressive it may have been.

12. It is further averred by the management that the intention of the Tribunal was to protect the interest of this workmen to the extent that :— that :—

(i) On switch over, in pursuance of their (workman) option as per the Scheme, when they are loosing their 2|3rd seniority in their parent cadre (i.e. from where they had opted for switch over), the Bank should not be allowed to make them liable for posting in the Cash Department because they had opted for coming out from the Cash Department and to avail their future avenue of promotional chances only in clerical category, which they were not entitled to prior to their switch over.

(ii) If the workmen are liable to be posted also in the Cash Department, inspite of their opting switch over in such event their fixation in the new cadre should be made without making them loss of their seniority in their parent cadre (i.e. from where they had opted for switch over).

13. It is further averred by the management that after switch over under the Scheme aforesaid, the claiments were also liable to be posted in any department of the Bank, including Cash Department, but the Tribunal did not approve this term, i.e. posting of the workmen again back to the Cash Department from where they had opted for clerical cadre. It was in this context that this Tribunal had disapproved the Bank's action for stipulating further condition making obligatory on the part of the workmen, who had opted for switch over to accept the condition for their posting in any Department of the Bank, including Cash Department and this Tribunal had given the second option. Mere inclusion of the term 'common cadre' should not be taken as a basis for interpretation of the said direction of the said direction of this Tribunal to construe that the intention of this Tribunal was :

(i) To direct the Bank to place the workmen in 'common cadre' without loss of their 2|3rd seniority in their parent cadre even though they were no more liable to be posted in Cash Department, i.e., the Department where they were working as CNEs. It has further been averred that the direction No. (ii) given to the Bank as second option, was given by this Hon'ble Tribunal to enable the Bank to comply with the directions of the Tribunal in the event of their being any technical or other problem for the Bank to adopt and comply with the first direction.

14. It has been further averred by the management that if the benefits aforesaid are given to the workmen, after their placement in the new cadre, in terms of the direction of this Tribunal as per its first direction, the placement of the workmen is to be made on loss of 2|3rd of their seniority in the non-clerical cadre. Merely because the workmen had been ranked for the purpose of seniority in the cadre known as 'common cadre', it is not expedient in the interest of justice and it may not be the proper construction of the terms of the Award of this Tribunal to construe the same to suggest that the workmen should be placed in the common cadre taking into account their full service in their non-clerical cadre, i.e. as CNEs in Cash Department, because the placement of workmen in the common cadre has been made due to the fact that after 26th July, 1973, the said new cadre which comprises of both clerks and CNEs has come into existence as also in spite of the fact that the cadre in which the workmen have been placed, in pursuance of adoption of first direction contained in the Award aforesaid is known as the 'common cadre', the workmen are no more liable to be posted in the Cash Department.

15. Vide order dated 15-10-1991, the All India Reserve Bank Employees Association, herein after referred to as the 'Employees Association', was permitted to be added as a party in the present case as a result they have also filed written statement to the statement of claim of Staff Association.

16. In their written statement, the Employees Association has averred that the All India Reserve Bank Employees' Association is the majority union of Class-III Employees of the Reserve Bank of India having over 85 per cent of the Class-III Employees, i.e., about 16,000 workmen as its' members. It is the only recognised union and the sole bargaing union of the Class-III Employees of the Reserve Bank of India.

17. It is further averred by the Employees' Association that the Award dated 20-12-1989 of this Tribunal arose out of a dispute raised by about 30 Class-III employees to the effect that the Reserve Bank of India has not given them seniority in accordance with the Combined Seniority Agreement. The said Combined Seniority Agreement is an agreement or the settlement arrived at solely between the Employees Association on the one hand and Reserve Bank Management on the other hand covering all the Class-III staff all over India counting to more then 18,000 Employees . The said agreement|settlement was nothing, but culmination of demand raised by the Employees Association as early as in the year 1954 followed by adjudication by the National Industrial Tribunal headed by justice K. T. Desai and by Hon'ble Supreme Court of India (AIR BEA Vs. RBI 1996 (1)SCR 25), series of negatiations in the matter bringing parity amongst the promotional prospects of all the Class-III Employees of the Bank, deputed to work in various Department of the Bank.

18. It has been further averred by the Employees Association that the main issue raised by 30 workmen concerned in the Industrial Dispute No. 104|1987 was that they having left the non-clerical and joined clerical stream by foregoing 2|3rd of their service rendered prior to attaining of eligibility qualifications, should not be now posted to any Department and made to work under their erstwhile juniors in the non-clerical category, who have since been promoted or having a better seniority position in their original department. As a subsidiary issue, they had urged that under the Settlement|Scheme, they were entitled to be switched over to a clerical cadre and not to a common cadre of Clerks|Coin Note Examiners and that the written consent was obtained from them by suppression of facts and in any event was not covered by Settlement and if they were to be transferred to a Common Category of Clerk|Coin Note Examiners, then there was no question of their foregoing 2|3rd seniority; that in view of this, their earliest option and its fallouts were to be treated non-est.

19. It is further averred by the Employees Association that the claim put forward in the I.D. No. 104|87 was not peculiar to these 30 workmen, but the same in spirit applied to over 2000 employees, who had opted from non-clerical to clerical stream as on 7th May, 1972 and fully applicable to over a thousand employees, who had adopted for after 7-5-1972 consequent to their attaining eligibility qualifications. Any relief to the effect of giving the benefit of full non-clerical| pre-graduation service for the purpose of seniority in the common category of Clerk|Coin Note Examiner or allowing employees to return to non-clerical stream would totally be retrograde and set the position to pre 7-5-1972 itself. Since 1972 settlement, vested legal rights of seniority, which have accrued to thousands of employees and could not be disturbed casually to cater the whims of certain employees.

20. It is further averred by the Employees Association that the option No. 1 of the Award dated 20-12-1979 in I.D. Case No. 104|87 first directs the Bank for the switchees to be placed only on a pure clerical cadre on loss of 2|3rd seniority of the non-clerical service and secondly directs that they should not be transferable to their parent department, i.e., Cash Department. Option No. 2 envisages absorption of the switchees in the common cadre by giving them the benefit of entire non-clerical service for the purpose of seniority and Option No. 3 envisages their reversion to the non-clerical category and department with their original seniority. The present reference for interpretation is confined to Option No. 1 and seeks to raise the question as to whether the Award permits the Bank, acting under Option No. 1, to fix the seniority of workmen in the common cadre. It is urged by the Employees' Association that the working of Award are quite clear and to not call for any interpretation at all. Fixation of seniority arises only in the cadre in which the employee is placed|abcorbed|recruited. Option No. 1 deals with clerical cadre only and it clearly specifies that fixation of seniority in the clerical cadre will be based on loss of 2|3rd seniority of the non-clerical service. It does not mention any where of common cadre and as such the question of fixation of seniority in the common cadre does not arise at all under Option No. 1. Obviously, there is a confusion on the part of the appropriate Government on the question as to why would there be inter-se seniority position between employees in the clerical cadre and those in the common cadre of Clerks| Coin Note Examiners. This is an issue wholly outside the ambition of Industrial Dispute No. 104 of 1987 and the Award. The common cadre| category recruits are as much a part of clerical category as a pure clerk. There could not be any ground on which they can be deprived of the seniority from the date of their recruitment as such.

21. It is further averred by the employees Association that as regards correct position of the Award is concerned, the 30 workmen have been declared to have been absorbed in the pure clerical cadre with loss of 2|3rd seniority of service and they have been exempted from being transferred to Cash Department. These were the two conditions of Option No. 1 as envisaged and these have been fulfilled and implemented. The portion of the letter of the Bank dated 18-7-1990 which mentions the seniority position of these workmen as Clerks vis-a-vis those who were recruited to the common cadre prior to them was wholly extraneous and cannot in any manner be called into to challenge the implementation of the Award. In short, this aspect of the matter pertains to the question as to what be the seniority of the common cadre recruits for the promotions available to clerks and not to the interpretation of the Award for it's implementation. It is urged by the Employees' Association that any other interpretation given to the Option No. 1 will either amount to amendment of the Award dated 20-12-1989 or would be the adjudication of entirely a new dispute.

22. It is further emphasised by the Employees Association that the said 30 workmen have tried to confound the position relating to their absorption in the clerical cadre with the loss of 2|3 seniority and the seniority claims as Clerks of those who had been recruited in the common cadre of Clerks Grade-II|Coin Note Examiner Grade-II. Both are entirely two different aspects. The workmen have tried to urge that the respondent Bank had not exercised Option No. 1 within the stipulated period, i.e. 14-4-1990. Since the letter of the Bank dated 2-4-1990 addressed them as Clerk Grade-II|Coin Note Examiner Grade-II and did not indicate their new cadre, relative seniority position and designation, it would mean that the

Option No. 1 was not exercised. It would be seen that the letter dated 2-4-1990 clearly spells out that the Bank had decided to exercise Option No. 1, with this the option stood exercised within the stipulated period. Rest of the requirements were not mandatory. Even in respect of this, the queries raised by the workmen dated 2-4-1990 stood answered by the Bank's letter of 18-7-1990, which was merely clerificatory in nature, wherein the fact that they stood absorbed in clerical cadre, with designation of Clerks and assigned seniority w.e.f. a specific date had been clearly mentioned. Thus, the question of the workmen exercising Option No. 2|3rd does not arise at all. Similarly, the claim of the workmen that they were worse of than before the Award, is also of no merit. Their principal contention was that they ought not to be transferred or made to work in the Cash Department, stand met and so is their claim to be transferred to pure clerical cadre. The workmen have repeatedly in their claim statement sought to misrepresent :—

(a) that they have been placed among the common cadre employees;

(b) that their seniority has been fixed in the common cadre and they have not been admitted into the exclusive clerical cadre.

23. It has been averred by the Employees Association that none of these everments are factual and they have been admitted only into the exclusive clerical cadre and assigned seniority therein only. They have been neither placed among common cadre employees nor assigned seniority into the common cadre.

24. I have heard the representatives of the parties and have gone through the file.

25. I have perused the Award dated 20-12-1989 of this Tribunal. The relevant paragraphs 8,9 and 10 are reproduced hereunder:—

"8. On merits it may straighaway be noticed that all the 30 workmen covered by this reference were actually informed of the further condition imposed by the Management and all of them had in fact given the requiste undertakings. There is also no evidence on the record to show that these undertakings were given under any form of duress and hence to all intents and purposes the undertakings given by workmen are voluntary. The question that arises is whether the action of the Management in imposing the further condition is legal and justified. On a consideration of the entire facts and circumstances, the detailed reasons of which will be given in the following paragraphs, the answer of this question is clearly in negative and in that event the so called voluntary undertakings given by the workmen are meaningless."

"9. The first point to be noted is that the original option of the workmen was exclusively for their automatic switchover to the clerical cadre under clause 2(b) of the combined seniority scheme. These workmen sacrificed 2|3rd of their non-clerical seniority for their switching over to clerical cadre as contemplated under the Scheme. The Scheme does not contemplate the loss of 2|3rd seniority for the transfer of these workmen to the common cadre. In fact no such clause has been provided under the Scheme to effect their transfer to the cammon cadre on 1|3rd seniority of non-clerical grade. Clause 2(b) read with Clause 4(b) that "Until such time he is acually transferred to the clerical cadre, an optee from the non-clerical cadre will, however, continue to be in the non-clerical cadre in which he is placed at the time of option and will accordingly remain eligible for the promotion in the non-clerical cadre". There is also no-provision in the Scheme that the Management could impose any additional condition on the optees under the Scheme. It is pertinent to observe here that the creation of the new common cadres of clerical Coin Note Examiners and the Switch over from non-clerical to clerical cadre are two different aspects and the bank is trying to confound the two while determining the seniority of these 30 workers. Since under the combined seniority scheme the cadre of clerical and non-clerical cadre which once were treated to be two district cadres, the common cadre has no connection whatsoever so far as switch over to clerical cadre is concerned and there arise no question of lossing their original position as defined in clause 4(b) in the non-clerical cadre in which they are placed at the time of option. It would appear to be an act of high handedness if the 30 workmen were required to work on 1|3rd of their seniority in the non-clerical cadre, in the parent cash department itself. The contention of the bank that the pre '72 staff interested in posing to the clerical cadre were required to acquire necessary qualifications within one or two months or soon thereafter so as to be eligible for fixing their seniority with Pre '72 clerks is without any force. In the first instance there is no such provision in the Scheme. Secondly, it is well known that graduation is a course of three years and it is not possible to expect from anyone to complete his graduation within one or two months from the date of enforcement of the Scheme as has been expressed by the ban. Therefore, the allegation of the bank that these 30 workmen took their own time in acquiring the requisite qualifications does not

hold any water. The stipulation of the Management that these workmen will have to work in their parent department on lost seniority which means even junior persons junior to them who may not have opted out of the non-clerical cadre is cruel to the extreme. It may be pointed out that such stipulation lacs lawful consideration and consequently is bad in law. It is mainfestly clear from the "Scheme" that the loss of 2|3rd seniority of non-clerical grade is contemplated solely for the purpose of switch over to the clerical cadre and not for the purpose of switch over to the common cadre. It may also be noted that the only justification for taking away 8|3rd seniority of the workmen is for switch over to clerical cadre and there would be no justification whatsoever for taking away any part of the senorty of these workmen if they were to be placed in the common cadre. The action of the Management has resulted in extrement justice to these workmen from the promotional point of view as their transfer to the common cadre, that too on 1|3rd seniority, would mean to work as junior to both the direct recruite in common cadre and their colleagues in the cash department which would otherwise mean delayed promotion on both sides resulting in financial and status loss."

"10. In view of the discussion made above, this reference is answered in favour of the workmen and against the Management. It is directed that either (i) these 30 workers be kept in the clerical cadre on loss of 2|3rd of their seniority in the non-clerical cadre and they shall not be transferable to the parent cash department or (ii) if it is the contention of the Management that it is not feasible to keep them in the clerical cadre, they may be absorbed in the common cadre by taking into account their full service in the non-clerical cadre and without any loss of seniority; or (iii) they may be given a further option to revert to the non-clerical cadre in their parent department with their original seniority. The choice in the matter is left to the Management keeping in view the fact that the workmen had accepted the further condition laid down by the Management, however, the oppressive it may have been. The Management shall make up its mind in choosing any of these alternatives within one month of the enforcement of this award failing which the choice will pass on to the workmen who in turn must exercise their choice within one month thereafter and if any of the workmen fails to exercise the choice, the situation of workman as prevailed before the making of this reference shall hold good. This reference stands disposed of accordingly."

26. From alternative (i), as above, it is quite clear, that it firstly directs the Bank Management for the switchees to be placed only on a pure clerical cadre on loss of 2|3rd seniority of their service in the non-clerical service and secondly it directs that the switchees should not be trasnferable to to their parent department, i.e., cash department. There can be no other logical interpretation.

27. Now, let me examine the steps taken by the Bank Management while implementing the direction contained in alternative(i). In paragraph 18 of their written statement, the Bank Management have stated that the 30 workmen concerned have been declared to have been absorbed in the pure clerical cadre with loss of 2|3d seniority of their service in non-clerical cadre and they have been exempted from being transferred to cash department. It has been urged by the Bank Management that these were the two conditions of alternative(i), and the same have been fulfilled and implemented. They have produced letters dated 2-4-90 and 18-7-90 addressed to the workmen concerned individually. The relevant contents of letter dated 2-4-90 are as under :-

"Dear Sir,

You are advised that in terms of the Award dated 20-12-89 in Industrial Dispute No. 104|87 passed by the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, the Bank has since decided to accept Option No. 1 given in the Award. Accordingly, you will not be transferred to the cash department as a consequence thereof, the promotional charges, accruing in Cash Department and other benefits arisen therefrom will not be available to you.

Yours faithfully,

Sd|-

P. MANAGER"

The relevant contents of letter dated 18-7-90 are as under :

"Dear Sir,

Please refer to your letter dated 2-4-90 asking the Bank to clerify the cadre to which you belong, your designation and your position in the seniority list fixed subsequent to the Award dated 20th December, 1989 passed by the Central Government Industrial Tribunal in I. D. Case No. 104|87.

2. In terms of the direction contained in Option No. 1 of the Award, you have been kept in the clerical cadre and your designation, therefore, is Clerk Gr. II. This, however, does not change your seniority vis-a-vis the common cadre Class-III employees of the Bank. This is because in terms of the order of the Award, your seniority is to be fixed in clerical cadre on loss of 2|3rd of your service as Coin Note Examiner in the Cash Department. Your seniority is accordingly fixed as on *10-5-74. As you are also aware between **7-5-72 and *10-5-74, there have been fresh recruitments in the common cadre of Clerk Gr. II|Coin Note Examiners Gr. II

and by virtue of their date of appointment as Clerk Gr. II Coin Note Examiners Gr. II in the common cadre those recruited prior to *10-5-74, are senior to you as clerks. Though your seniority falls below some of the common cadre employees, you are designated as Clerk Gr. II and as such your channel of promotion shall be that available to pure clerks.

Yours faithfully,
Sd/-
(V. SHARMA)
P. MANAGER

*Notional date of seniority.

**Date on which common cadre was introduced in New Delhi Office."

28. As discussed here-in-above, alternative(i) given by the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in para 10 of their Award cannot be interpreted to mean that the Reserve Bank of India can fix the seniority of 30 workmen in the common cadre nor it has been done, as alleged by the staff association. They have been absorbed purely in the clerical cadre as Clerk Gr. II with loss of 2/3rd of their seniority in the non-clerical cadre.

29. As regards the correct position about the implementation of the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, it is held that in paragraph 10 of the Award, the Bank management had been given choice to choose either of the 3 alternatives within one month of the enforcement of the Award. The Bank management chose alternative(i) as is evidence from their undisputable letter dated 2-4-1990 addressed to each of the 30 workmen within stipulated period. All the 30 workmen concerned have been absorbed as Clerk Gr.II as aforesaid and they are not transferable to the parent Cash Department. This reference stands disposed of accordingly. Parties shall bear their own costs.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मई, 1996

का० आ० 1571:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-5-96 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल–12011/58/89/आई आर बी आई12011/48/89/आई आर बी आई 12011/50/89 आई आर बी आई 12011/6/90/आई आर बी आई 12012/185/90 आई आर बी आई 12012/12/91/आई आर बी आई 12012/125/91) आई आर बी आई]

पी० जे० माईकल,
डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th May, 1996

S.O. 1571.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kshetriya Kisan Grammi Bank and their workman, which was received by the Central Government on the 9-5-96.

[No. L-12011/58/89-IRBI; 12011/48/89-IRBI; 12011/50/89-IRBI; 12011/6/90-IRBI; 12012/155/90-IRBI; 12012/124/91-IRBI; 12012/125/91-IRBI]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, DEOKI PLACE ROAD, KANPUR.

Industrial Dispute No. 243 of 1989

In the matter of dispute between :

Shri Narender Singh Yadav,
C/o Shri V. L. Sekhri,
26/104 Birhana Road,
Kanpur.

AND

The Chairman,

Kshetriye Kishan Gramin Bank,
Head Office,
Kusherhry Road,
Mainpuri (UP).

Industrial Dispute No. 244 of 1989.

In the matter of dispute between :

Shri Avnindra Kumar,
C/o Shri V. N. Sekhri,
26/104 Birhana Road,
Kanpur.

AND

The Chanrman,

Kshetriya Kishan Gramin Bank,
Head Office,
Kutchery Road,
Mainpuri (U.P.).

Industrial Dispute No. 251 of 1989.

In the matter of dispute between :

Shri Yogesh Chandra Sharma,
C|o Shri V. N. Sekhri,
26|104 Birhana Road,
Kanpur.

AND

The Chairman,

Kshetriya Kishan Gramin Bank,
Head Office,
Kutchery Road,
Mainpuri (U.P.).

Industrial Dispute No. 96 of 1990.

In the matter of dispute between :

Shri Kastur Chand,
C|o Sri V. N. Sekhri,
26|104 Birhana Road,
Kanpur

AND

The Chairman,
Kshetriya Kishan Gramin Bank,
Mainpuri

Industrial Dispute No. 5 of 1991.

In the matter of dispute between :

Shri Pramod Kumar Sharma ,
C|o Shri V. N. Sekhari,
26|104 Birhana Road,
Kanpur.

Kanpur.

AND

The Chairman,
Kshetriya Kishan Gramin Bank,
Kacheri Road,

Industrial Dispute No. 66 of 1992.
Shri Gopendra Kumar Sharma,
C|o Shri V. N. Sekhari,
26|104 Birhana Road,
Kanpur.

AND

The Chairman,
Kshetriya Kishan Gramin Bank,
Kachheri Road,
Mainpuri.

Industrial Dispute No. 67 of 1992.

In the matter of dispute between :

Shri Pradeep Kumar Tiwari,
C|o Shri V. K. Sekhri,
26|104 Birhana Road,
Kanpur.

AND

The Chairman,
Kshtriya Kishan Gramin Bank,
Kachehri Road,
Mainpuri-2050001.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi has referred the following disputes for adjudication to this Tribunal vide notification nos. L-12011|58|89-IR(B)-I dt. 4-10-89 :

Whether the action of the management of Kshetriya Kishan Gramin Bank Mainpuri, in terminating the services of Narender Singh Yadav, Ex-Assistant-cum-Cashier w.e.f. 27-6-83 is fair, just and legal? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?

L-12011|48|89-I.R.(B) dt. 4-10-89.

Whether the action of the management of Kshetriya Gramin Bank, Mainpuri in relation to their Dhatri Branch in terminating the services of Shri Avnindra Kumar Ex-Asstt.-cum-Cashier w.e.f. 21-6-83 is fair, just and legal? If not, to what relief the workman concerned is entitled?

L-12011|50|89-I.R. Bank-I dt. 6-10-1989 :

Whether the action of the management of Kshetriya Kishan Gramin Bank, Mainpuri in respect of their Garooma (Mainpuri) Branch in terminating the services of Shri Yogesh Chander Sharma, Ex-Asstt-cum-Cashier w.e.f. 17-9-83 is fair just and legal ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?

L-12011|6|90-I.R. Bank-I|I.R. Bank-III dated 9-4-1990 :

Whether the action of the management of Kshetriya Kisan Gramin Bank, Mainpuri in terminating the services of Shri Kastur Chand Ex-Clerk-cum-Cashier w.e.f. 24-6-1983 is legal & justified? If not to what relief the workman is entitled to?

L-12012|185|90-I.R.B-III dt. 31-1-91 :

Whether the action of the management of Kshetriya Kisan Gramin Bank, Mainpuri in terminating the services of Shri Pramod Kumar Sharma, Assistant-cum-Cashier, w.e.f. 10-1-1984 was justified? If not, to what relief the workman is entitled to;

L-12012|124|91-I.R.B.III dt. 31-3-92 :

Whether the action of the management of Kshetriya Kishan Gramin Bank, Mainpuri, was justified in terminating the services of Shri Gopendra Kumar Sharma w.e.f. 19-5-1983? If not, to what relief the workman is entitled to?

L-12012|124|91-I.R.B. III dt. 31-3-92 :

Whether the action of the management of Kshtriya Kisan Gramin Bank, in terminating the services of the workman Shri Pradeep Kumar Tiwari w.e.f. 25-6-83 was justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?

2. The aforesaid 7 cases have been consolidated by this Tribunal on 14-9-95 at the request of workmen, as common question of law and facts are involved in it. I.D. 43 of 1989 is the leading case in which evidence has also been adduced by the parties and award is given accordingly.

3. I.D. Case No. 243 of 89.

The case of the applicant Narender Singh Yadav is that he was appointed as Assistant-cum-Cashier by the opposite party, on 17-11-81 at Shahjahanpur Branch in District Mainpuri. He continuously worked upto 27-9-86 whereafter, his services were retrenched without payment of retrenchment compensation. Further junior to him have been retained in service.

4. I.D. Case No. 244 of 89.

The case of the applicant Avanindra Kumar is that he was appointed as Assistant-cum-Cashier by the opposite party on 1-1-82 at Kalhora Branch (District Mainpuri). He continuously worked upto 21-6-83, whereafter his serivces were retrenched without payment of retrenchment compensation. Further juniors to him have been retained in service.

5. I.D. Case No. 251 of 89.

The case of the applicant Yogesh Chandra Sharma is that he was appointed as Assistant-cum-cashier by the opposite party on 14-9-82 at Nishampur Garooma Branch, District Mainpuri. He continuously worked upto 16-9-83 whereafter his services were retrenched without payment of retrenchment compensation w.e.f. 14-12-83. Further juniors to him have been retained in service.

6. I.D. Case No 96 of 90.

The case of the applicant Kastoor Chand is that he was appointed as Assistant-cum-Cashier by the opposite party on 5-2-82 at Sathna, Vasrana and Ureser Mainpuri and he continuously worked upto 24-6-83 whereafter his services were retrenched without payment of retrenchment compensation. Further juniors to him have beenretained in service

7. I.D. Case No. 66 of 92.

The case of the applicant Gopendra Kumar Sharma is that he was appointed as Assistant-cum-Cashier by the opposite party on 24-9-81 at Head Office Mainpuri. He continuously worked upto 18-5-83 whereafter his services were retrenched without payment of retrenchment compensation. Further juniors to him have been retained in service.

8. I.D. Case No. 67 of 1992.

The case of the applicant Pradeep Kumar Tiwari, is that he was appointed as Assistant-cum-Cashier by the opposite party on 7-9-81. He worked upto 24-6-83 whereafter his services were retrenched without payment have been retained in services.

9. I.D. Case No. 5 of 1991.

The case of the applicant Pramod Kumar Sharma is that he was appointed as Assistant-cum-Cashier by the opposite party on 11-5-83. He worked continuously upto 9-1-84, whereafter his services were retrenched without payment of retrenchment compensation. Further juniors to him have been retained in service.

10. Although in each of the reference, the opposite party has filed separate written statement but their objection is common. Hence it is being mentioned in respect of all the claims.

11. It is alleged that appointment of each of the concerned workman was for a fixed period of three months which was renewed subsequently. As the services of the each concerned workman came to an end by efflux of time, it is not a case of retrenchment. It is noteworthy that in none of the cases, the management has specifically denied that either of the concerned workman had not worked continuously as claimed by each of them. Instead their patent plea had been that their appointment was for a fixed period. It was alleged that subsequently the power of appointment was taken away from the President and was vested in BSRB. The initial appointment was bad. The validity of reference has also been challenged, by way of amendment.

12. The each of the concerned workman has filed rejoinder in which the factual pleas raised in the written statement have been denied.

13. Before taking up the evidence on record it may be mentioned that some workman junior to the concerned workmen had also been fired and they had taken up the matter before the Hon'ble High Court where they succeeded. As a result of this decision these workmen were taken into service. This fact was brought to my notice. When I inquired from the authorised representative of the opposite party as to why the concerned workmen should also not be taken into service on the basis of parity. He sought time. Thereafter some amicable talks also took place between the authorised representative of the concerned workman, the authorised representative of the management. Management had offered that in case the concerned workmen were prepared to forgo their backwages, management may be prevailed upon to take them in service.

14. The authorised representative of the concerned workmen was prepared for it. Hence, a date was given. When the case came up for hearing again the authorised representative of the management informed that as President of opposite party ban was not authorised they were unable to take back concerned workmen in service. In other words these talks failed.

15. Now the matter may be taken up on merits. The first point which needs consideration is as to whether the concerned workmen had completed 240 days in a calender year preceding their retrenchment.

16. As has become obvious from narration of claim statement that each of the concerned workman had claimed that he had completed more than 240 days in a calender year.

17. Indeed in written statement the management has also not specifically denied this fact. Instead their plea have been that their appointment were for fixed periods. When a fact is specifically alleged and is not specifically denied in the written statement under order 8 rule 5 C.P.C. it will be deemed to have been admitted. On this plea alone it should be deemed that the claim of the each of the concerned workman regarding their having completed more than 240 days in a calender year preceding their retrenchment stands admitted. Further this fact has not been denied by witness of the management Ashish Kumar M.W.1. Apart from this Ext. W-25, W-26 and Ex. W-14 are the certificates issued by the President of the opposite party bank relating to Pradip Kumar, Kastoor Chand and Pramod Kumar to show that they have worked for more than 240 days in a calender year. Further the opposite party has also nor filed any letter of appointment to show that the concerned workmen were appointed for a fixed period of 3 months. In its absence, it will be deemed that each of the applicant had continuously worked for more than 240 days in a calender year preceding their respective retrenchment. As such they were entitled for benefit of section 25-F I.D. Act, at the time of retrenchment which certainly has not been done which renders retrenchment of each of the concerned workman as bad in law.

18. The concerned workmen will not be entitled for benefit of Section 25G of I.D. Act, as juniors to the concerned workmen have been taken in service at the intervention of Hon'ble High Court. Objection has also been raised on behalf of management that reference is bad in law. It may be mentioned that the management have challenged the reference in a varieties of ways before the Hon'ble High Court in Civil Misc. Writ Petition No. 4222 of 91 which was dismissal of writ petition in my opinion, all the objection relating to reference should stand replled. It was also alleged that initial appointment of the concerned workman was bad in law. Nothing has been shown as to how the appointment of adhoc or temporary cashier-cum-clerk was bad. In the absence of such explanation this objection is over ruled.

19. Lastly, it was submitted that power of appointment has been withdrawn from the President. President would not have power to make appointment from the date such power is withdrawn. But it will not render bad the appointments made by him prior to such withdrawal of powers. Hence, this will in no way entitled the management to retrench the workmen.

20. In the end having found that the retrenchment of each of the concerned workmen is bad in law they are entitled for reinstatement. However they will be nor entitled for back wages from the date of termination as reference is highly belated. Instead I order that they will be entitled for back wages for the last three years preceding the date of publication of award at the rate at which they were being paid wages at the time of their respective retrenchment. Each of the concerned shall also be entitled to get Rs. 100 as costs of the case from the management.

21. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 मई, 1996

का०आ० 1572.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-6-1996 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44

और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला फरीदाबाद के राजस्व ग्राम अलाहपुर (पलवल), हदबस्त संख्या-66 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या : एस—38013/11/96—एस०एस०-I]
जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 15th May, 1996

S.O. 1572.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st June, 1996 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana namely :—

The areas falling within the limits of revenue Village Alahapur (Palwal) Had Bast No. 66 of Faridabad District.

[No. S-38013/11/96-SS.I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मई, 1996

का०आ० 1573 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-6-1996 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला नालगोन्डा के बीबीनगर मंडल में राजस्व ग्राम नेमारोगोमुला की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या : एस-38013/12/96—एस एस-1]
जे०पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, 15th May, 1996

S.O. 1573.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st June, 1996 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The areas falling within the limits of Nemarigomula revenue village in Bibinagar Mandal of Nalgonda District."

[No. S-38013/12/96-S.S. I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मई, 1996

का०आ० 1574 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-6-1996 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला पेरियार के इरोड तालुक में राजस्व ग्राम सरकार पेरिय अग्रहारम, सरकार चिन्न अग्रहारम, नंजै अत्तुक्कुलि, पुदूर, तिण्डल (इरोड पूर्व फिरका के अधीन), तिण्डल (इरोड पश्चिम फिरका के अधीन), गंगापुरम (इरोड पश्चिम फिरका के अधीन), वेप्पमपालयम, पुदूर पुदुप्पालयम, वैरपालयम, ब्राम्हन चिन्न अग्रहारम, पीलमेडु, वेण्डिपालयम, मोडचाण्डि सत्यमंगलम, नंजै तलवैपालयम, नंजै लाक्कापुरम, नंजनपुरम, पगलतांपालयम, विलरसमपट्टी, कडिरमपट्टी, अट्टयम पालयम नासियनूर और एल्लप्पालयम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या : एस—38013/13/96—एस.एस.-I]
जे०पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 15th May, 1996

S.O. 1574.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st June, 1996 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act

shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely:—

"Areas comprising the revenue Villages of Sarkar Peria Agraharam, Sarkar Sinna Agraharam, Nanjai Uthukuli, Pudur, Thindal (Erode-East Firkka), Thindal Erode-West Firkka), Gangapuram (Erode-West Firkka), Veppamplayam, Vyrampalayam, Pudur Pudupalayam, Brahmana Senna Agraharam, Peelamedu, Vendipalayam, Modavandi Sathyamangalam, Nanjai Thalavaipalayam, Nanjai Lakkapuram, Nanjanapuram, Pagalathampalayam, Villarasampatty, Kadirampatty, Aitayampalayam, Nasivanur, Ellapalayam in Erode Taluk of Periyar District.".

[No. S-38013/13/96-S.S. I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मई, 1996

का. आ. 1575.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भारतीय खाद्य निगम सेवा को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 6 के अंतर्गत आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छह मास की अवधि तक के लिए तत्काल लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस-11017/5/91-आई०आर० (पालिसी विधायी)]

हरीचन्द्र गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 17th May, 1996

S.O. 1575.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Food Corporation of India, which are covered by entry 6 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercises of the powers conferred by Sub-clause (vi) of Clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months.

[No. S-11017/5/91-IR(PL)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996